चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

18 नवंबर–24 नवंबर 2013

फिर छात्र आंदोलन

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

देश की ग़ुलामी के दौर में हुए स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद हुए राजनीतिक परिवर्तनों में छात्रों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी. स्वातंत्र्योत्तर काल में देश में दो बड़े परिवर्तनकारी आंदोलन हुए, एक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और दूसरा वीपी सिंह के नेतृत्व में. यह दोनों आंदोलन ऐसे समय हुए, जब देश की राजनीति में भ्रष्ट ताक़तें मज़बूत हो रही थीं और राजनीतिक ठहराव को तोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. दोनों आंदोलनों में युवाशक्ति ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था. आज फिर भारतीय राजनीति और समाज में ठहराव महसूस किया जा रहा है, देश भ्रष्ट ताक़तों की गिरफ़्त में है और गंभीर संकट से जूझ रहा है. ऐसे में फिर से एक बड़े और परिवर्तनकारी आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और अब इसकी अगुआई कर रहे हैं समाजसेवी अन्ना हजारे. अन्ना की परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता को देखते हुए आज का युवा न सिर्फ़ उनके साथ खड़ा है, बल्कि एक भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व्यवस्था वाले भारत का सपना भी देख रहा है.

नीरज सिंह

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई के अपने अभियान में युवाओं के उत्साह को और बल देते हुए कई बार यह कहा है कि युवाशक्ति ही राष्ट्रशक्ति है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फ़ायदे के लिए उन्हें अपने पक्ष में इस तरह कर लिया है कि छात्र राजनीति और उनके मुद्दे इन्हीं पार्टियों के होकर रह गए हैं. छात्र ख़ुद को जिनती जल्दी इस अवस्था से बाहर निकालेंगे और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तभी सही मायनों में देश स्वतंत्र हो पाएगा.

अन्ना हजारे के इस विचार से देश भर के युवा सहमत हैं और इसको लेकर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है. वे इस बात से भी सहमत हैं कि भ्रष्टाचार और ख़ासकर राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार ही दूसरी सभी मुश्किलों का स्रोत बन रहा है. लेकिन ग़ौर कीजिए तो यह विचार पिछले कई दशकों तक सिर्फ़ भाषणों में सीमित था. और इससे लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था. छात्रों ने जब भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहा तो छात्र संघों में बैठे राजनीतिक दलों के एजेंटों ने उन्हें नेतृत्व ही नहीं दिया, बल्कि रोड़े अटकाए. यही वजह है कि जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा तो छात्रों को एक विकल्प मिला और अब छात्र अन्ना हजारे को नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्वीकार कर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं. राजनीतिक और सामाजिक तौर पर देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है. इसी सोच के साथ समूचे प्रदेश के छात्र बतौर एक संगठन छात्र–युवा संघर्ष मोर्चा के रूप में अन्ना हजारे के साथ उनके समर्थन में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना तैयार करते हुए एक नए आंदोलन की भूमिका लिख रहे हैं.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो देश की राजनीति में रूढ़ पड़ चुकी व्यवस्था को बदलने के लिए छात्रों ने लंबी लड़ाई लड़ी है. लेकिन मौजूदा दौर की जो मुश्किलें हैं, यह कोई एक दो दिन की नहीं, बल्कि दशकों की हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अब आकर छात्र एक मोर्चे के तौर पर आंदोलित क्यों हो रहा है? अन्ना हजारे के विचारों में ही उसे उम्मीद की किरण क्यों दिख रही है? और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही क्यों हो रही है? यह ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है और इसे स्पष्ट करने के लिए भारतीय राजनीति में पचास साठ के दशक से लेकर अब तक छात्र राजनीति के भीतर होने वाले बदलाव को समझना होगा.

छात्र राजनीति में आने वाला बदलाव दरअसल भारतीय राजनीति में आने वाले बदलाव के साथ ही चल रहा था. आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के कुछ दशकों की जो राजनीति थी, वह आज़ादी की लड़ाई के बाद निर्मित हुई क्रांतिकारी भावना से, ख़ासकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हुए संघर्ष के साथ जुड़ी हुई थी. जब देश इस उन्माद से निकलकर बाहर आया तो कांग्रेस पार्टी के सामने कोई विपक्ष नहीं था. ऐसे में देश भर में छात्र राजनीति एक महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में उभरी. उस वक्त कांग्रेस का एक तरह से पूरे देश में वर्चस्व था. उसके ख़िलाफ़ देश में जो पहली चुनौती उभरनी शुरू हुई, वह छात्रों ने ही पेश की. तब भी छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए कई घटनाएं सामने आईं, जैसे पटना विश्वविद्यालय में 50 के दशक में छात्रों पर गोलीकांड हुआ. उस दौर में छात्र बदलाव की राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्वर बन रहे थे. 60–70 के दशक में यूरोप के भीतर छात्र आंदोलन हुए, ख़ासकर फ्रांस में. इधर भारत में भी ज़बरदस्त छात्र आंदोलन हो रहे थे, चाहे वह उत्तर भारत में अंग्रेज़ी हटाने को लेकर आंदोलन हो या फिर 74 आते–आते जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ आंदोलन हो, जब लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई. इस तरह से अगर इस देश में किसी ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करने में महत्वूर्ण भूमिका निभाई तो सही मायनों में वे छात्र ही थे.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री और छात्र युवा संघ मोर्चा के संयोजक उमेश सिंह के मुताबिक, 'वास्तव में देश राजनीति और उससे पैदा हुई मुश्किलों के दौर में बदलाव लाने में छात्रों की भूमिका सही तौर पर 70 के दशक में ही सामने आई. छात्रों ने बदलाव के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और कांग्रेस के वर्चस्व को ख़त्म करके बहुदलीय लोकतंत्र बनाने में बड़ा योगदान दिया.'

हालांकि, इसी दशक में छात्र राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ और जातिवादी राजनीति छात्र राजनीति में घुसने लगी. कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई ने इस कारनामें की शुरुआत की और फिर उसके जवाब में समाजवादियों की छात्र राजनीति भी इसी ओर मुड़ गई. यहां पर एक सवाल उठता है कि यह सभी कारण तो आज भी मौजूद हैं तो क्या यह समझा जाए कि 2013 में जिस छात्र आंदोलन की शुरुआत हो रही है, वह दलगत राजनीति से ऊपर उठ गया है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रहे दिनेश सिंह यादव इसके जवाब में कहते हैं कि 'वास्तव में छात्र संगठन यह स्वीकार कर रहे हैं कि दलगत राजनीति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है. हाल के दिनों का उदाहरण लें तो देश में इस समय चुनावी माहौल है, लेकिन कोई भी पार्टी छात्र हितों को अपने एजेंडे में नहीं शामिल कर रही है.' हमारा देश 2020 तक युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा. लेकिन इस युवा देश के तमगे को लेकर हम क्या करेंगे, जब अभी 26 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही वरिष्ठ छात्र नेता राजेश सिंह जो कि पिछले एक दशक से छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, का मानना है कि 'प्रदेश का छात्र भी यह समझ गया है कि राजनीतिक दलों ने उसे केवल धोख़ा दिया है, उसे इस्तेमाल किया है. और अन्ना हजारे जी सत्तापक्ष और अन्य पार्टियों के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम अन्ना जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र यह घोषणा कर रहे हैं कि छात्रों का समर्थन उसी के साथ होगा जो छात्र हित को अपने एजेंडे में शामिल करेगा.' लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता शम्मी सिंह के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दिनेश सिंह यादव
छात्रसंघ अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

मनीष पांडेय
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, केएपीजी कॉलेज, मदोही

शैलेन्द्र पांडे
पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, वाराणसी

सुरेश यादव
पूर्व महामंत्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

उमेश सिंह
पूर्व जनरल सेक्रेटरी, बीएचयू

विकास तिवारी
छात्रनेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

राहुल की नाकामी, कांग्रेस की मुसीबत 03

जंगलराज की ओर लौट रहा बिहार 05

माया-मुलायम लिखेंगे नई पठकथा 06

साई की महिमा 12

फिर छात्र आंदोलन

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पृष्ठ एक का शेष

मुताबिक, अन्ना हजारे ने देश की मुश्किलों को समझा है और उसका सही हल समझाया है और अगर अब नौजवान उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में नव–नक्सलवाद जन्म ले लेगा और उसका प्रतिनिधित्व बेरोज़गार छात्र करेंगे.

वास्तव में यह सभी मुद्दे अन्ना हजारे जी के जनलोकपाल की मांग में बतौर स्टेक शामिल हैं, इसलिए न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि समूचे देश के छात्र उनकी मांग को अपनी आवाज़ दे रहे हैं. अगर ऐसा है तो यह भी समझना होगा कि छात्रों के जो वास्तविक संगठन थे और जो उनकी लड़ाई थी, वह अपने लक्ष्य से भटकी क्यों? 80 के दशक तक आते–आते छात्र संगठन पूरी तरह अपने मूल राजनीतिक दलों के ज़ेबी संगठन बन गए और फिर छात्र नेता पार्टी के नेताओं की जय–जयकार और अपने लिए टिकटों के जुगाड़ को ही मुख्य ध्येय समझने लगे थे. इस तरह जो छात्र राजनीति बदलाव के लिए जानी जाती थी, वह अब अवसरवाद की ओर मुखर हो गई. छात्र संघ लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होने लगे.

90 के दशक में देश में दो बड़ी घटनाएं घटीं, पहला राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद और दूसरा सरकारी नौकरियों में आरक्षण. इन दोनों के पक्ष और विपक्ष में हुए आंदोलनों ने छात्र एकजुटता को सांप्रदायिक और जातीय आधार पर बांट दिया. जाति और धर्म के टकराव के तौर पर शुरू हुई आईडेंटिटी पोलिटिक्स ने छात्र राजनीति के भीतर ज़हर भर दिया. तो क्या यह ज़हर अब कम हो रहा है. इस आंदोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कॉलेजों से जुड़े छात्र संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना शिबली नोमानी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मिर्ज़ा शाने आलम बेग का मानना है कि 'आंदोलनों में उतार–चढ़ाव तो आते ही रहते हैं. लेकिन बतौर छात्र आपका असली मक़सद तो यही है न कि आप रोज़गार हासिल करिए.' मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो यह ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा मानती है. हाल ही मुलायम सिंह ने यह नारा भी दिया कि जय जवान, जय किसान, जय मुसलमान. लेकिन सवाल तो यह है कि यह सरकार ढेड़ साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी और पुरानी नियुक्तियां अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं. नई वैकेंसी की तो बात ही छोड़िए. तो छात्र इनके बहकावे में कब तक रहेगा? इस आंदोलन से जुड़े पी.जी. कॉलेज गाजीपुर के छात्र नेता फज़लुल इस्लाम अपनी राय रखते हुए बताते हैं कि 'आरक्षण तो तब मिलेगा, जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो. उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो अभी 2009 के बाद के सारे रिज़ल्ट रुके हुए हैं, जबकि तब से लेकर अब कर लाखों नए उम्मीदवार आ गए. इसलिए हम ऐसे आंदोलन को जन्म देना चाहते हैं जो उन्हें सबक़ सिखाए, जिन्होंने हमें धोख़ा दिया है. इस सबक़ के तौर पर अब हम एक ऐसे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसकी बेदाग़ छवि है और उनके सरोकार राजनीतिक न होकर सामाजिक हैं.'

एक सवाल यह भी है कि जब राजनीतिक दल छात्र संगठनों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं तो वे इसकी बहाली क्यों नहीं चाहते? दरअसल, बदलावों के तेवर से सत्ता हमेशा डरती रही है. बिहार में 87–88 में आख़िरी छात्र संघ चुनाव हुए, जबकि लालू यादव ख़ुद छात्र राजनीति से आए और 15 साल तक सत्ता में रहे. नीतीश भी छात्र राजनीति से आए हैं. लेकिन बिहार में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए. वास्तव में मुख्यधारा की राजनीति को हमेशा यह डर रहता है कि छात्रसंघ हमारे लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं. उनके ग़ैर–जनवादी कामों पर विरोध कर सकते हैं. सत्ता ने उन्हें अपने लिए असुविधाजनक माना. यही वजह है कि 80 के दशक के बाद देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों को छावनी के तौर पर बदल दिया गया. छात्र संघ भंग करने शुरू किए गए. आंदोलन से जुड़े और काशीनरेश पी जी कॉलेज, भदोही के पूर्व अध्यक्ष मनीष पांडेय मानते हैं कि 'कैंपस के भीतर जो हड़ताल और धरने प्रदर्शन और आंदोलन होते थे, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के रूप में तब्दील किया गया. यही वजह है कि उस दौर के बाद बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस कुलपति बनाए जाने लगे, क्योंकि कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा विषय बना दिया गया.'

वास्तव में विश्वविद्यालयों में होने वाले ये आंदोलन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं थे. कैंपस के भीतर पैदा हुए ज्यादातर आंदोलन शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली गिरावट, छात्र हितों की अनदेखी के ख़िलाफ़ उठने वाले स्वर थे, जिन्हें बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का नाम दिया गया. वास्तव में सरकारों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत युवाओं की एकजुट ताक़त पर हमला किया. एनडीए सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसके माध्यम से शिक्षा में सुधार और इन्वेस्टमेंट की बात की गई. उस समिति ने कहा कि परिसरों से छात्र राजनीति को ख़त्म कर दिया जाए. उसी तरह से यूजीसी ने महमूदुर्हमान समिति बनाई, जिसमें कहा गया कि चूंकि छात्र राजनीति से विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है, इसलिए छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाई जाए. सरकारें छात्र एकजुटता को सत्ता विरोधी शक्ति के तौर पर देख रही थीं, इसलिए पहले तो उसमें आपराधिक तत्व घुसाए फिर उन्हें बदनाम करते हुए उनपर प्रतिबंध लगाना शुरू किया. इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री सुरेश यादव इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि 'दरअसल, ये असामाजिक तत्व थोपे हुए लोग थे, इसलिए छात्रों से ये कटे हुए थे. जब सरकार ने इनके विरोध के तौर पर इन्हें ख़त्म करना शुरू किया तो छात्रों की ओर से भी इसका कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं हुआ.'

वास्तव में छात्र राजनीति को ख़त्म करने के पीछे यह मक़सद तो था ही नहीं कि पठन–पाठन का माहौल बेहतर बनाया जाए. ऐसा होता तो बिहार और झारखंड, जहां पर वर्षों से छात्र संघ नहीं हैं, वहां के विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अब तक कीर्तिमान कायम कर चुके होते. वास्तव में यह एक युवा शक्ति के रूप में बौद्धिक विपक्ष को मारने की साज़िश थी, जिसे रणनीति के तहत सभी दलों ने मिलकर ख़त्म कर दिया.

एक और सवाल उठता है कि जो सरकारें छात्र आंदोलनों की इस तरह विरोधी रही हों, उनसे यह उम्मीद कैसे की जाए कि वे इसे हाथों–हाथ ले लेंगी. छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के संयोजक व वरिष्ठ छात्र नेता विकास तिवारी इसके जवाब में कहते हैं कि 'दरअसल, छात्रों के संघठनों का जनता से कोई संवाद नहीं रह गया है और यह संवाद ख़त्म करने की भूमिका राजनेताओं ने ही निभाई. उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है.'

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री सुरेश यादव कहते हैं कि 'दुनिया में जहां भी बड़े युवा आंदोलन या छात्र आंदोलन हुए, वह कभी भी छात्रों के मसले को लेकर नहीं हुए, वह व्यापकता लिए हुए समाज में बदलाव के लिए हुए.' चाहे वह जेपी का आंदोलन हो या वी पी सिंह के नेतृत्व में हुआ आंदोलन हो, जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लामबंदी हुई और उसमें छात्र बड़ी भूमिका में रहे. फ्रांस का छात्र आंदोलन हो इजिप्ट का छात्र आंदोलन या फिर हाल में पृथक राज्य तेलंगाना को लेकर. ये सभी आंदोलन कोई फीस वृद्धि या सीटों में बढ़ोतरी को लेकर नहीं हुए थे. ये सब के सब राजनीतिक–सामाजिक आंदोलन थे. टी डी कॉलेज बलिया छात्र नेता व इस आंदोलन से जुड़े श्रीप्रांत सिंह के मुताबिक 'सरकारें चाहती हैं कि छात्र अगर इन मसलों को लेकर वजूद में आए तो उनके मंसूबों के पूरे होने में मुश्किलें आएंगी. लेकिन अब इस बात का डर इसलिए नहीं है, क्योंकि हम इस लड़ाई को लोकसभा चुनावों के पहले शुरू कर रहे हैं, जिससे देश की निगाहें हमारे ऊपर रहेंगी. दूसरे इसे हम अन्ना जी के नेतृत्व में शुरू कर रहे हैं. वे देश भर में भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इससे हमारा संवाद भी देश भर की जनता के साथ जुड़ेगा.'

वास्तव में देश ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद कोई बड़ा छात्र आंदोलन नहीं देखा. इसलिए इस आंदोलन की ओर लोग और भी उम्मीद से देख रहे हैं. छात्र युवा संघ मोर्चा के संयोजक उमेश सिंह के मुताबिक 'तुलनात्मक रूप से देखें तो जेपी के समय में जो वैक्यूम था, मौजूदा वैक्यूम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है. आज जब जीडीपी का जितना हिस्सा शिक्षा पर ख़र्च हो रहा है, उतना हिस्सा अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा पर ख़र्च हो रहा है.'

वास्तव में देश में ऐसे मुद्दे व्याप्त हैं जो वर्षों से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे. निश्चित तौर आने वाले वक्त में छात्रों की अगुवाई में होने वाले इस नए आंदोलन की ओर समूचा युवा वर्ग उम्मीद के साथ देखेगा. दुष्यंत के शब्दों में 'पर्वत सी हो चुकी पीर' को पिघलने के लिए ऐसे क़दम की सख़्त ज़रूरत थी, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 37
दिल्ली, 18 नवंबर–24 नवंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

सीएजी की बड़ी उपलब्धि

दिलीप चेरियन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के मौजूदा यूपीए सरकार में ज्यादा दोस्त नहीं रह गए हैं, लेकिन मौजूदा सीएजी शशिकांत शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं. पिछले दिनों शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के ऑडीटर्स बोर्ड के सदस्य के रूप में छह वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया. सदस्य के रूप में. जिसमें विश्व भर में कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के ऑडिट करने की ज़िम्मेदारी होगी. लेकिन सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि शर्मा को यह ज़िम्मदारी आसानी से नहीं मिली है. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने उनकी सदस्यता का विरोध किया और उसकी जगह फिलीपींस को ज़िम्मेदारी दिए जाने की पैरवी कर की थी. लेकिन शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय राजनयिक समुदाय के समक्ष बेहतर तरीक़े से अपनी दावेदारी पेश की साथ ही चीन और पाकिस्तान से अपने पक्ष में वोट देने के लिए आग्रह किया. इस कदम से वैश्विक समुदाय के बीच भारतीय राजनय स्थापित होगा और लोगों का इस ओर ध्यान जाएगा.

भारत के सीएजी के लिए प्रतिष्ठित यूएन के लिए काम करने का यह कोई पहला अवसर नहीं है, लेकिन तब भी जब घर में सरकार और सीएजी के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. ■

उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नौकरशाह अब राजनीतिक आकाओं द्वारा मौखिक रूप से दिए गए आदेशों का पालन न करें. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया कि नौकरशाहों का कार्यकाल निर्धारित किया जाए, जिससे कि उनके कार्य करने में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो सके. अधिकांश लोग इस निर्णय को एक ऐतिहासिक निर्णय मान रहे हैं. स्वाभाविक रूप से अदालत के इस निर्णय से नौकरशाह प्रफुल्लित हैं और राजनीतिक हलकों में अदालत के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ फुसफुसाहट हो रही है. हालांकि, पूर्व कैबिनेट सचिव टीआरएस सुब्रमण्यम सहित जिन 80 गणमान्य लोगों ने याचिका दायर की थी, उनके अनुसार सुशासन की दिशा में यह निर्णय एक बहुत बड़ा क़दम है.

साफतौर पर उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और हरियाणा के आईएएस आधिकारी अशोक खेमका और अन्य मामलों में अधिकारियों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई के विरोध में जनता के आक्रोश ने कहीं न कहीं असर डाला है. लेकिन सरकार को इस आदेश को लागू करने के लिए बहुत कुछ करना होगा. इस आदेश को लागू करने, नौकरशाहों के स्थानांतरण को नियंत्रित करने, उनकी पदस्थापना और उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए क़ानून बनाने का निर्देश दिया है. सिविल सर्विसेस एसोसिएशन ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है, उन्हें सरकार द्वारा इस नियम को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य करना होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि बिना कार्यान्वयन के इसका कोई औचित्य नहीं है! ■

गैर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोत्साहन

पहली बार हाइड्रोकार्बन नियामक प्राधिकरण का महानिदेशक किसी नौकरशाह की बजाय एक स्पेशलिस्ट को बनाया जा रहा है. ऐसा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बी एन तालुकदार के नाम को मंजूरी देने के बाद संभव हो सका है. अब तक इस अर्ध–नियामक प्राधिकरण के प्रमुख के पद पर किसी नौकरशाहों की नियुक्ति होती थी. परिपाटी से इतर यह निर्णय स्वागत योग्य है. सूत्रों के अनुसार तालुकदार के नाम का चयन दो माह पूर्व पेट्रोलियम सचिव विवेक राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किया था. जो कि 1981 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी आर एन चौबे की जगह लेंगे. एक नौकरशाह की जगह एक टेक्नोक्रेट का चुनाव करने के बाद (तालुकदार 2007 से इंडियन ऑयल में अन्वेषण निदेशक के रूप में कार्यरत हैं) मंत्रालय संभवत: तेल की खोज और विकास से जुड़े मसलों पर टकराव रुख के समाप्त होने की उम्मीद कर रहा है. एक प्रतिष्ठित पद को खोने के बाद नौकरशाह बुरा महसूस कर रहे होंगे लेकिन गैर प्रशासनिक अधिकारी इस निर्णय के परिपाटी बनने की आशा कर रहे होंगे! ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

दीप्तिमान संयुक्त सचिव बने

रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी दीप्तिमान दास को जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित आयोग का संयुक्त सचिव बनाया गया है. दास वर्तमान में उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. वह भरतीय आयुध निर्माण सेवा में कार्यरत आदित्य मिश्रा की जगह लेंगे.

बेहुरिया पहुंची मानवाधिकार आयोग

1977 बैच की वरिष्ठ आयकर अधिकरी परविंदर सोही बेहुरिया को राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है. बेहुरिया वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) विभाग की सदस्य हैं, जो आयकर विभाग के नोडल प्राधिकरण के अंतर्गत आता है.

श्रीनिवासन डीओपीटी से जुड़े

2002 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी जगन्नाथ श्रीनिवासन को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में उप सचिव नियुक्त किया गया है. वह 1999 बैच के अधिकारी अमरप्रीत दुग्गल की जगह लेंगे, जिनको केंद्रीय सचिवालय में स्थांतरित किया गया है.

सहाय को नई ज़िम्मेदारी

1989 बैच के असम–मेघालय कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशिलेश सहाय को जनजातीय मामलों वाले मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है. सरकार ने मंत्रालय में यह नया पद सृजित किया है. सहाय जल्द ही ज्वाइन करेंगे.

महर्षि उर्वरक विभाग में सचिव बने

1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव महर्षि को सुधीर मित्तल के स्थान पर उर्वरक विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है. सुधीर मित्तल 30 नवंबर को रिटायर्ड हो गए. वर्तमान में महर्षि प्रवासी भारतीय मामलों के मत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

राहुल गांधी कि रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है. वे जहां जा रहे हैं, उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जिस उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, वहां हालत और भी दयनीय है. अब तक अलीगढ़, रामपुर, हमीरपुर और सलीमपुर में हुईं चार रैलियों में पार्टी के अनुसार भीड़ कम थी. अलीगढ़ और हमीरपुर में भीड़ बेहद कम थी. वहां लगभग 20 हज़ार या उससे भी कम लोग पहुंचे थे.

राहुल की नाकामी, कांग्रेस की मुसीबत

कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा तबका आज भी राहुल गांधी की योग्यताओं पर भरोसा नहीं करता. लेकिन चूंकि, सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का संचालन इस तरीक़े से किया कि राहुल के मुक़ाबले कोई और नेता पार्टी में उभर ही नहीं सका, लिहाजा राहुल के नेतृत्व को स्वीकारना इन नेताओं की मजबूरी भी बन गई, पर राहुल की स्वीकार्यता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है. राहुल गांधी के हर बयान के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी होतीं हैं, उसमें हर कांग्रेसी यह सोच कर परेशान हो जाता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में लौट पाएगी?

रूबी अरुण

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद, बीते 22 सालों में गांधी परिवार ने भारतीय राजनीति में सीधे तौर पर देश की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली है. लेकिन कांग्रेस का चेहरा गांधी परिवार ही बना रहा है. पार्टी के लिए सड़क से सत्ता तक का संघर्ष भी गांधी परिवार ने किया और सत्ता बिना आधार वाले नेताओं ने संभाली. शायद यही वजह रही कि आज कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास न तो कोई चेहरा बचा, न ही कोई संगठन. पर राहुल के साथ जो मुश्किल है, वो ये कि आज तक राहुल गांधी ने अपनी ऐसी कोई लियाकत पेश नहीं की, जिसकी बिना पर कांग्रेस के नेताओं में यह उम्मीद जगे कि राहुल के हाथों में पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है या फिर राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता हासिल कर सकती है. हालात बेहद दुरूह हैं और 2004 से बिल्कुल उलट. 2004 में कांग्रेस ने छह साल से चल रही एनडीए सरकार को ललकारा था और अपने ब्रांड के बूते सत्ता में आ गई थी. पर अब लगभग दस सालों बाद स्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हैं. अब देश के लोग ब्रांड राजनीति को तरजीह नहीं देते. जिस तर्ज पर अमेरिका में बुश और केनेडी के ब्रैंड का क्षरण हो चुका है उसी तरह भारत में भी नेहरू–गांधी नाम के लेबल की चमक कम पड़ चुकी है. बावजूद इसके राहुल अपने परिवार के नाम की राजनीति करते नज़र आ रहे हैं. राष्ट्रीय समस्याओं और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों से इतर, चुनावी सभाओं में वे अपनी दादी और पिता को याद करते सुने जाते हैं. जिस पर उन्हें सहानुभूति कम मिलती है, मज़ाक ज्यादा उड़ता है. और यह सब जनसांख्यकीय परिवर्तनों की वजह से हो रहा है, जिसकी समझ कांग्रेस के नेताओं या राहुल गांधी के सलाहकारों में नहीं है. भारत में अभी जो मतदाता हैं, उनमें ज़्यादातर का जन्म 1975 के बाद हुआ है. इन मतदाताओं के लिए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कमोबेश राजीव गांधी भी एक ऐतिहासिक चरित्र की भांति हैं, जिनसे आज के मतदाता प्रेरित होना ज़रूरी नहीं समझते. यही वजह रही कि पिछले उत्तर प्रदेश चुनावों में राहुल गांधी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उन इलाक़ों में भी नहीं जितवा सके, जो इलाक़े पारंपरिक रूप से उनके परिवार के समर्थक रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा तबका आज भी राहुल गांधी की योग्यताओं पर भरोसा नहीं करता. पर चूंकि, सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का संचालन इस तरीक़े से किया है कि राहुल के मुकाबले कोई और नेता पार्टी में उभर ही नहीं सका, लिहाजा राहुल के नेतृत्व को स्वीकारना इन नेताओं की मजबूरी भी बन गई. पर राहुल की स्वीकार्यता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है. राहुल गांधी के हर बयान के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी होतीं हैं उसमें हर कांग्रेसी यह सोच कर परेशान हो जाता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में लौट पाएगी? कांग्रेस नेतृत्व के जिस दौर से गुज़र रही है, उसमें कांग्रेस का हाथ खाली रह जाएगा. क्योंकि राहुल गांधी राजनीति के जो दांव आजमाते हैं, उससे फ़ायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाता है. राहुल पार्टी के लिए नहीं बल्कि ख़ुद के लिए संघर्ष करते नज़र आते हैं. ठीक वैसे ही जैसे दूसरा कोई भी और कांग्रेसी नेता. राहुल की बातों में, उनकी सियासत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहीं नहीं होते, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह मनमोहन सिंह के एजेंडे में राहुल गांधी की जगह नहीं होती. राहुल गांधी को अगर सत्ता में आना है तो कांग्रेस को बहुमत में आना होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आम लोगों का कोई ख़ास रुझान राहुल गांधी कि तरफ़ नहीं दिख रहा.

अब देश के लोग ब्रांड राजनीति को तरजीह नहीं देते. जिस तर्ज पर अमेरिका में बुश और केनेडी के ब्रांडों का क्षरण हो चुका है, उसी तर्ज पर भारत में भी नेहरू-गांधी नाम के लेबल की चमक कम पड़ चुकी है. बावजूद इसके राहुल अपने परिवार के नाम की राजनीति करते नज़र आ रहे हैं. राष्ट्रीय समस्याओं और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों से इतर, चुनावी सभाओं में वे अपनी दादी और पिता को याद करते सुने जाते हैं.

राहुल गांधी कि रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है. वे जहां जा रहे हैं, उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जिस उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, वहां हालत और भी दयनीय है. अब तक अलीगढ़, रामपुर, हमीरपुर और सलीमपुर में हुईं चार रैलियों में पार्टी के अनुसार भीड़ कम थी. अलीगढ़ और हमीरपुर में भीड़ बेहद कम थी. वहां लगभग 20 हज़ार या उससे भी कम लोग पहुंचे थे. इसके उलट रामपुर और सलीमपुर में 50 हज़ार की भीड़ मौजूद थी.

हमीरपुर में आई कम भीड़ को राहुल ने भी नोटिस किया था. पार्टी ने इसकी ज़िम्मेदारी झांसी सांसद और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री प्रदीप जैन के साथ कांग्रेस विधायक ज़ादीन, विवेक कुमार सिंह और दलजीत सिंह को सौंपी थी, लेकिन वे रैली ग्राउंड को भर नहीं पाए, जबकि अब तक हुई राहुल की ये चारों रैलियां कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से बेहद ख़ास थीं. 2009 के चुनावों में इन चारों जगहों में से तीन में कांग्रेस दूसरे और एक में तीसरे स्थान पर थी. हमीरपुर, सलीमपुर और रामपुर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, जबकि अलीगढ़ में चौधरी बृजेंद्र सिंह 23.95 प्रतिशत वोट लाकर भी हार गए थे. रामपुर में कांग्रेस की बेगम नूर बानो समाजवादी पार्टी की जयाप्रदा से हार गई थीं, वहीं हमीरपुर में सिद्ध गोपाल साहू को बीएसपी के विजय बहादुर सिंह ने हरा दिया था और सलीमपुर में भोला पांडे को बीएसपी के ही रामशंकर राजभर ने परास्त किया था.

जम्मू में राहुल कि रैली हुई. वहां राहुल के भाषण के बीच में ही सरपंचों ने बग़ावती तेवर अख़्तियार कर लिए. बिहार के सारण ज़िले में राहुल गांधी की सभा में ख़ूब हंगामा हुआ. मांझी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल के सामने ही लोग उनके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करते रहे. मध्य प्रदेश में राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सागर के राहतगढ़ और इंदौर में सभाएं कीं, लेकिन वहां भी उम्मीद से कम लोग इकट्ठा हुए. राहुल बुंदेलखंड गए. उन्हें और पार्टी नेताओं को उम्मीद थी की यहां के लोग उनका साथ देंगे और सभा में जम कर अपनी उपस्थिति दिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. राहुल के हेलीकॉप्टर ने लैंड करने के पहले सभा स्थल के कई चक्कर लगाए, ताकि भीड़ जमा हो सके. पर यह मशक्कत भी काम नहीं आई और वहां बीस हज़ार से भी कम लोगों कि मौजूदगी रही. राहुल गांधी के आने के बाद संचालन कर रहे विनोद चौधरी ने उनके जयकारों के नारे लगवाने चाहे, लेकिन भीड़ ने उनका साथ नहीं दिया. फ़जीहत होती देख विनोद चौधरी चुप हो गए, इसके बाद फिर किसी कांग्रेसी नेता कि हिम्मत नहीं हुई कि वो मंच पर आकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और भीड़ से लगाने को कहे. दिल्ली में होने वाली रैली के लिए हरेक कांग्रेस नेता को एक लक्ष्य दिया गया कि हर एक नेता को शहर से एक हज़ार और देहातों से इक्यावन सौ कार्यकर्ता लाने हैं. इंदौर से दिल्ली एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, पर उसमें पहले दिन सिर्फ़ पंद्रह कांग्रेसी कार्यकर्त्ता ही सवार हुए. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपना पूरा ज़ोर लगा दिया, फिर भी नतीजे उत्साहवर्धक नहीं रहे.

अब तो कांग्रेसी नेता भी भीड़ जुटाने के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते. बातचीत के दरम्यान एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि वे अपने–अपने क्षेत्र के लोगों से भी अगर रैली में आने कि गुज़ारिश करते हैं तो उल्टे उन्हीं से सवाल पूछा जाता है कि पिछले पांच सालों से विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं, बिजली का बिल बढ़ गया, पानी नहीं आ रहा है, सब्जी और दूध के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में वे कांग्रेस की रैली में क्यों जाएं.

ज़ाहिर है कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए हालात बेहद दुश्वारी भरे हैं. राहुल तो देश की जनता पर भरोसा दिखला रहे हैं, पर देश का उन पर भरोसा ख़त्म हो चला है. कम से कम मौजूदा वक़्त में दिखाई तो यही दे रहा है. बतौर संसद राहुल गांधी ने लगभग नौ साल का समय बिताया है, पर उनके खाते में एक भी उल्लेखनीय काम नहीं हैं. हां, अपने गैर ज़िम्मेदाराना बयानों और हरकतों कि वजह से वे गाहे–बगाहे विवादों में ज़रूर आते रहे हैं. विपक्षियों पर इल्ज़ाम मढ़ते हुए राहुल कोई ऐसी बात नहीं कहते , जिसे सुनकर ये लगे कि उनके पास देश के बेहतर भविष्य को लेकर कोई योजना है. पार्टी के नेता भले ही यह बात कहते रहे हों कि राहुल गांधी कि क़ाबिलियत पर उन्हें भरोसा है, पर राहुल ने कभी ऐसी पहल नहीं की जिससे यह आभास हो कि उन्हें ख़ुद पर भरोसा है. राहुल ने अभी तक कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई.

न सिर्फ़ राहुल बल्कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पिछले एक–दो सालों में कोई उत्साहजनक काम नहीं किया है. सोनिया गांधी की नाकामी ये रही कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का कोई नया चेहरा, नेतृत्व के तौर पर उभरने नहीं दिया और न ही राहुल गांधी को सरकार और पार्टी के शीर्ष पद के योग्य बना सकीं. सोनिया गांधी के इर्द–गिर्द वही पुराने चारणों की फ़ौज़ है या फिर नए लोगों में वे लोग शामिल हैं जो किसी न किसी की राजनीतिक वंश–बेल हैं. विधानसभा चुनावों में भी पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है और बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ उल्लेखनीय नहीं कर पा रही हैं. राहुल गांधी के नाम के बाद अगर किसी नए नाम कि चर्चा नेतृत्व के तौर पर होती है तो वो हैं सोनिया गांधी कि बेटी प्रियंका गांधी. पर उपलब्धियों के लिहाज से देखा जाए तो वे भी शून्य ही नज़र आती हैं. रॉबर्ट वाड्रा कि पत्नी होना भी प्रियंका के लिए सियासी राह में कांटे ही बिछाता है. रही सही कसर राहुल और सोनिया के सलाहकारों की मंडली पूरी कर देती है, जो उन्हें हमेशा जनविरोधी सलाह ही देती है.

क्योंकि आज कांग्रेस जिन मुश्किलों की गिरफ़्त में है, उसके लिए उसके ग़लत राजनीतिक फ़ैसले ही ज़िम्मेदार हैं. लिहाजा अभी के सियासी हालातों और लोगों की कांग्रेस के प्रति नाराज़गी देखते हुए यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई अब हिन्दुस्तान कि सियासी तस्वीर में गांधी परिवार 2014 के आम चुनावों के बाद हाशिये पर सिमट कर रह जाएगा? या फिर जिस तरह नब्बे के दशक में बेहद मुश्किल स्थितियों से घिरी सोनिया गांधी ने अपने परिवार की वापसी भारतीय लोकतंत्र में कराई थी, वैसा ही कोई चमत्कार वे कर पाएंगी और अपने बेटे के प्रधानमंत्री बनने के सपने को साकार कर पाएंगी? ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति में आरोप–प्रत्यारोपों का दौर तो हमेशा चलता रहा है, लेकिन आजकल बात इससे भी आगे बढ़ गई है. नेताओं में किसी भी मुद्दे पर राय देने की जगह अनियंत्रित ढंग से ज़बान चला देने की होड़–सी लगी है. विभिन्न मुद्दों पर बहसों और हर तरह के विचारों के सामने आने से लोकतंत्र मज़बूत होता है, लेकिन अशिष्ट–असंसदीय टिप्पणियों से संसदीय लोकतंत्र की अवधारणाएं न सिर्फ़ आहत होती हैं, बल्कि इससे स्वस्थ बहस की परंपरा भी छीजती है.

राजनीतिक बहसों का गिरता स्तर

गूंगी गुड़िया से देहाती औरत तक

लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं में लानत-मलामत का दौर जारी है. भारतीय राजनीति में एक ऐसा भी दौर गुज़रा है जब नेतागण इज़्ज़त के साथ एक-दूसरे को सुनते थे और एक उच्च आदर्श को मतभिन्नता से परे रखकर फ़ैसले किए जाते थे. ऐसा भी समय देश ने देखा है जब समाजवादी, वामपंथी और दक्षिणपंथियों ने एक ही घाट पर पानी पिया. लेकिन आज राजनीतिक बहसें गाली-गलौज की हद तक असंसदीय हो चुकी हैं. कोई नेता अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करता, जो जन सामान्य की भाषा में वर्ज्य हैं.

कृष्णकांत

आज़ादी के बाद देश में सौ फूलों को खिलने दो, सौ विचारों को पनपने दो की अवधारणा स्थापित हुई थी, जिसमें विश्वास रखने का मतलब है कि आप हर किसी को अपनी बात रखने और अपनी बात पर उसे असहमत होने का हक़ देते हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की इस अवधारणा की न सिर्फ़ घोर वकालत की थी, बल्कि इसे अपने आचरण में भी उतारा था. उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनकी और देश के लिए बनाई गई उनकी नीतियों की बखिया उधेड़ने और नेहरू द्वारा मुस्कराते हुए उसे सम्मान के साथ सुनने के तमाम क़िस्से हम सब सुनते आए हैं. वह लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा थी जो आज़ादी के कड़े संघर्षों से निकली थी. लेकिन बाद के वर्षों में यह संसदीय परंपरा छीजती गई और राजनीतिक बहसों का स्तर गिरता चला गया.

हाल ही में मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी को शैतान कह डाला. इसके कुछ दिन पहले बिहार के भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि वे ईर्ष्यावश देहाती औरत की तरह नरेंद्र मोदी से झगड़ रहे हैं. इस पर नाराज़ महिलाओं का एक समूह चूड़ी, सिंदूर, चुनरी, टिकुली आदि लेकर गिरिराज के सरकारी आवास पर पहुंचा और उनके ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. महिलाओं का कहना था कि भाजपा नेता ने महिलाओं का अपमान किया है. हालांकि, बाद में गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि उनके बयान से महिलाएं आहत हैं तो उन्हें खेद है. गिरिराज भले ही अफ़सोस जता दें, लेकिन राजनीति की उस परंपरा का क्या करें, जिसके तहत नेता अक्सर ही ऐसी बयानबाज़ी करते हैं.

इसके पहले जब सपा नेता नरेश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी की तुलना विधवा औरत से करते हुए अभद्र टिप्पणी की, तो उस पर तल्ख़ प्रतिक्रिया तो हुई ही, महिला आयोग ने इसे महिलाओं के लिए अपमानजनक मानते हुए संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की बात कही. हालांकि, यह कोई पहला मसला नहीं है. भारतीय राजनीति में विरोधियों की खिल्ली उड़ाने और असंसदीय छीटाकशी करने का बहुत पुराना इतिहास रहा है. आज़ादी से पहले तीस के दशक में इसकी शुरुआत हो गई थी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के पहनावे और उनके व्यक्तित्व को लेकर उन्हें नंगा फ़कीर कह डाला था. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनीं तो सार्वजनिक तौर पर या संसदीय बहसों में बहुत कम बोला करती थीं. उनकी चुप्पी पर नेहरू के ज़बरदस्त आलोचक रहे डॉ. राममनोहर लोहिया उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित करने लगे थे. कहते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी को अपनी निजी बातचीत में चुड़ैल कहा करते थे. इंदिरा गांधी के समय ही पाकिस्तान में याह्या खान राष्ट्रपति थे, जो उन्हें वो औरत (दैट वुमन) कहकर पुकारते थे. जिस तरह से आज अहम मसलों पर राय न रखने के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनमोहन कहा जाता है, उसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चुप्पी के कारण उन्हें मौनी बाबा कहकर उनकी आलोचना की जाती थी. हाल के वर्षों में ऐसे बयानों की बाढ़ सी आ गई है और इस तरह के ज्यादातर बयान गाली–गलौज के स्तर के होते हैं. दरअसल, नेतागण बहस–मुबाहिसे में अपने विरोधी की खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राय: वे डगमगा जाते हैं और बात बिगड़ जाती है. कभी–कभी लगता है कि ऐसे बयान उसी तरह आवेश में दिए जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को गुस्से में गाली देता है.

बात 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान की है. अभिनता से नेता बने राजेश खन्ना भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी पर इतने नाराज़ हुए कि मर्यादा तोड़ते हुए टिप्पणी की कि औलाद नहीं हैं पर दामाद है. ये पब्लिक है सब जानती है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अपने राजनीतिक विरोधियों से अक्सर खरी खोटी सुनती रही हैं. अटल जी के नेतृत्व काल में विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी सोनिया गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द बोले थे. इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने 2010 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. कुछ ही महीने बीते होंगे जब राहुल गांधी ने अपने भाषण में केरल के वामपंथी नेता अच्युतानंद की बढ़ती उम्र का ज़िक्र किया तो जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल एक अमूल बेबी हैं जो दूसरे अमूल बेबियों के लिए प्रचार करने आए हैं. सौम्य स्वभाव के नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी चुनावी राजनीति में पदार्पण करने वाले अरविंद केजरीवाल को धमका कर राजनीतिक विश्लेषकों को हतप्रभ कर दिया था. सलमान ने कहा कि उनको फ़र्रुखाबाद आने दीजिए, लेकिन वो वहां से वापस कैसे जाएंगे? इस कड़ी में चाल, चरित्र और चेहरे की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा के नेता भी पीछे नहीं हैं. अमर्यादित टिप्पणियों के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भी नाम उस समय सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया, जब उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर को पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड कह डाला. हालांकि, थरूर ने सधा हुआ जवाब दिया कि सुनंदा मेरे लिए अमूल्य हैं, जिन्हें रुपयों में तोला नहीं जा सकता. अपने आंदोलनों ने जब अन्ना हजारे देश की चेतना को हिला रहे थे, उनके मंच से अभिनेता ओमपुरी ने अपने अमर्यादित बयान से राजनीतिक गलियारे में यह कहकर हलचल मचा दी थी कि मुझे इस बात पर शर्म आती है जब कोई आईएएस या आईपीएस एक गंवार नेता को सेल्यूट करता है. हमारे नेताओं में से पचास फ़ीसदी गंवार हैं. उनको कभी वोट मत दीजिए. बाल ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आटे का बोरा कहा था, तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अपने ही वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को बासी अचार कह चुके हैं.

हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए कह डाला था कि एक आदमी 55 दिन से बांध से पानी छोड़ने की रट लगाए हुए है. वह अनशन पर है, क्या उसे पानी मिल गया. जब पानी ही नहीं है तो कहां से छोड़ें, अब क्या पेशाब कर दें. जब पीने को पानी है ही नहीं, तो पेशाब भी नहीं होती. अजीत उसी सभा में बिजली की किल्लत पर बोले कि रात में दो बजे बिजली काट देते हैं. आजकल रात में बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं. बिजली नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे. ज़ाहिर है कि इसे हम आप किसी लंपट की बदज़ुबानी के तौर पर नहीं देख सकते. यह एक राज्य की बिजली–पानी जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर वहां के उपमुख्यमंत्री की राय थी.

अजीत पवार अकेले नेता नहीं हैं जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हों. कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी नरेंद्र मोदी की तुलना यमराज से कर चुके हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मोदी को मौत का सौदागर कह चुकी हैं. सपा छोड़ कांग्रेसी हुए बेनी प्रसाद बर्मा भी कुछ महीनों से अपने उलूल–जुलूल बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. बेनी बाबू भी लोकसभा चुनावों में सपा की अर्थी निकलने की घोषणा के साथ मुलायम को आतंकवादियों का साथी, भ्रष्टाचारी, गुंडा और बदमाश बता चुके हैं. इस पर पलटवार करते हुए सपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री शिवपाल यादव ने बेनी को नशेड़ी, तस्कर आदि बताया था. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी तभी चर्चा में आते हैं जब कोई ज़ुबानी तीर चलाने का कारनामा करते हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों पर चल रही एक बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी को झिड़कते हुए कह दिया था कि कल तक आप पैसे के लिए पर्दे पर ठुमके लगा रही थीं और आज राजनीतिक विश्लेषक बन गई हैं, राजनीति सिखा रही हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी का वह भाषण आपको याद होगा कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ उंगली उठाएगा या समझेगा कि हिंदू कमज़ोर हैं और उनका कोई नेता नहीं हैं, अगर कोई सोचता है कि ये नेता वोटों के लिए हमारे जूते चाटेंगे तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस हाथ को काट डालूंगा. इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुर्सी संभालने के बाद एक रैली में खाद की क़ीमतें बढ़ने का विरोध करते हुए कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर 10 बार मिल चुकी हूं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. क्या अब मैं जाकर उन्हें मारूं? अगर मैं ऐसा करूंगी तो आप मुझे गुंडा कहेंगे, मुझे तो बिना कुछ किए भी लोग गुंडा बुलाते हैं. उसी दौरान ममता बनर्जी ने एक बलात्कार पीड़ित को 20 हज़ार रुपये मुआवज़ा देने की घोषणा की तो माकपा नेता अनिसुर्रहमान ने टिप्पणी की कि हम ममता दी से पूछना चाहते हैं उन्हें कितना मुआवज़ा चाहिए. बलात्कार कराने के लिए वे कितना पैसा लेंगी. रहमान की इस टिप्पणी की माकपा नेताओं ने भी निंदा की थी.

पिछले ही साल चंडीगढ़ में एक रैली में भाजपा नेता नितिन गडकरी ने लालू और मुलायम के लोकसभा से वॉकआउट का ज़िक्र करते हुए कहा था, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जो यूपीए और सरकार के विरोध की बात करते हैं, वे भी जाकर सीबीआई के सामने जाकर झुक गए. जो लोग शेर जैसे दहाड़ने की बात करते हैं लेकिन कुत्ते जैसे बनकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के तलुए चाटते हैं. ये ज़बानें एक ऐसे देश के नेताओं की हैं जो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में शुमार किया जाता है. यहां पर छह दशक पुराना लोकतंत्र है और विशेषज्ञों की ज़ुबानी इसे सफल भी क़रार दिया जाता है. लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों की जमात में लगातार ऐसी हरकतें होती रहती हैं. जनता से जुड़े मसले नेताओं के बीच बहुत कम ही चर्चा का विषय बनते हैं. भूख, ग़रीबी, बेकारी, विस्थापन, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जाति–धर्म के नाम पर विद्वेष आदि के मसलों पर नेताओं के बीच कभी इतनी शिद्दत से चर्चा नहीं होती. वहां पर इस तरह की लड़ाइयां सामने नहीं आतीं. जनहित के मुद्दों का कभी चर्चा के केंद्र में न आना और फिज़ूल बातों पर लानत–मलामत होना लगातार पतित होती राजनीति का संकेत है.

राजनीतिक गलियारों में आरोप–प्रत्यारोपों का दौर तो हमेशा चलता रहा है, लेकिन आजकल बात इससे भी कुछ आगे बढ़ गई है. नेताओं के बीच किसी भी मुद्दे पर राय देने और टिप्पणी करने की जगह अनियंत्रित ढंग से, बहुत बार तो सामान्य लोक–व्यवहार को किनारे कर अभद्रता की हद तक ज़बान चला देने की होड़–सी लगी है. ऐसी बहसों के लिए टीवी पर चलने वाली वे बहसें भी ज़िम्मेदार हैं, जिसमें एक–दूसरे पर हमले करते हुए आवेश में आकर नेतागण मर्यादा और संसदीय परंपरा की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं. विभिन्न मुद्दों पर बहसों और हर तरह के विचारों के सामने आने से लोकतंत्र मज़बूत होता है, लेकिन अशिष्ट–असंसदीय टिप्पणियों से संसदीय लोकतंत्र की अवधारणाएं न सिर्फ़ आहत होती हैं, बल्कि इससे स्वस्थ बहस की परंपरा भी छीजती है. ■

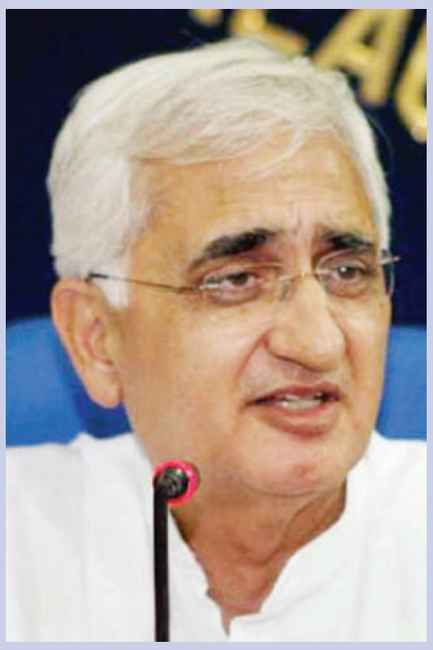

भारतीय राजनीति की उस परंपरा का क्या करें, जिसके तहत नेता अक्सर ही अमर्यादित बयानबाज़ी करते हैं. वे बहस-मुबाहिसे में अपने विरोधी की खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राय: डगमगा जाते हैं. कभी-कभी लगता है कि ऐसे बयान उसी तरह आवेश में दिए जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को गुस्से में गाली देता है.

feedback@chauthiduniya.com

जैसे–जैसे बीजेपी मजबूत होगी जेडीयू के अंदर का असंतोष बढ़ेगा. आज उनके छोटे–छोटे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि नीतीश में अब वो करिश्मा नहीं रह गया है. अब नीतीश का सामाजिक समीकरण भी टूट रहा है. बहरहाल नीतीश की परेशानियां कम होती दिख नहीं रही हैं. आए दिन असंतोष के स्वर उभर रहे हैं. लेकिन नीतीश हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं.

जंगलराज की ओर लौट रहा बिहार

बिहार में लगातार बढ़ती अपराधिक घटनाओं के चलते नीतीश सरकार का संकट बढ़ रहा है. अब फिर से राज्य उस दौर में लौट रहा है जब चौक-चौराहों पर लोग कहने लगे हैं कि बिहार फिर से जंगलराज की ओर लौट रहा है. बोधगया बम बलास्ट, बगहा गोलीकांड से अभी नीतीश सरकार उबर भी नहीं पाई थी कि पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए बम धमाकों ने उसकी और किरकिरी कराई. नीतीश सत्ता में आने के बाद से जिस बेहतर क़ानून-व्यवस्था का दंभ भरते रहे हैं, उसे फिर से बहाल करना होगा.

शशि सागर

नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. गठबंधन में रहते हुए बरमेश्वर मुखिया की शव यात्रा के दौरान पटना में हुए उपद्रवियों के तांडव के बाद से लगातार सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होती जा रही है. अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. चौक–चौराहों और बतकही में लोग कहने लगे हैं कि बिहार फिर से जंगलराज की ओर लौट रहा है. मशरक कांड, बोधगया बम बलास्ट, बगहा गोलीकांड से अभी पार्टी उबर भी नहीं पाई थी कि पटना में हुंकार रैली के दौरान हुए बम विस्फोट ने उसकी और किरकिरी कर दी. बात यहीं ख़त्म नहीं हुई.

ऐसा नहीं है कि सारी परेशानियां एकबारगी नीतीश के गले आ पड़ी हैं. धीरे–धीरे ये इकट्ठी और मज़बूत हुई हैं, जिससे निपटना अब उनके लिए भी चुनौती है. एक और परेशानी जो विकराल होती जा रही है, वो ये कि अब उनके ही नेता विभिन्न कारणों से उन्हें और पार्टी को दागदार करने में जुटे हुए हैं. हाल ही में जदयू के राज्यसभा सांसद अनिल सहनी के मुजफ्फरपुर और दिल्ली स्थित आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा. उनपर एमपी कोटे के रेलवे व हवाई कूपन में गड़बड़ी का आरोप है. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बिना यात्रा किए सांसद ने नौ लाख रुपये के भुगतान के लिए दावा किया था. मामले पर सांसद सहनी कहते हैं कि यह उनके नाम पर फर्जी रेल टिकट का धंधा करने वाले ट्रेवल एजेंसी का कारनामा है. साथ ही यह भी कहा कि उनकी ही शिकायत पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है. जदयू नेता के यहां छापे की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी जदयू के कोशाध्यक्ष रहे विनय सिन्हा के घर पर छापेमारी की जा चुकी है. छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने आटे की बोरी से साढ़े चार करोड़ की राशि बरामद की थी. साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ था कि जदयू नेता और उनके पार्टनर के नाम से पटना में पचास फ्लैट हैं. यह किसी से छिपा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश से विनय के करीबी रिश्ते रहे हैं. एक अणे मार्ग आवंटित होने से पहले तक नीतीश उन्हीं के घर रहा करते थे. यह अलग बात है कि ठीक उसी समय बिहार अपना शताब्दी वर्ष मना रहा था और इसी शोर में यह खबर दबकर रह गई थी.

पटना बलास्ट के बाद एक गंभीर आरोप यह भी लगा कि बलास्ट में शामिल मोनू उर्फ तहसीन अख्तर जदयू नेता तकी अख्तर का भतीजा है. बताते चलें कि मोनू तकी अख्तर के बड़े भाई वसीम अख्तर का बेटा है. 2011 में ही बिहार पुलिस उसे ढूंढ़ते हुए उसके पैत्रिक गांव मनियारपुर पहुंची थी. जब इस मामले पर राजनीति गरमाई तो जदयू के नेताओं ने तकी अख्तर के साथ एक संवाददाता सम्मेलन किया. सम्मेलन में जदयू नेता व मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तकी अख्तर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पार्टी और सीएम के चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है. दो साल से मोनू का उसके घरवालों से कोई सम्पर्क नहीं है. इस बीच भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार आतंकियों के प्रति नरम है. तकी अख्तर का हाल के दिनों में मोनू से संबंध रहा है या नहीं, मोनू क्या सच में दो साल से घरवालों से सम्पर्क में नहीं है, यह जांच का विषय है. लेकिन जदयू ने क्लीन चिट दे दिया है. इसी तरह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बाहुबली व पूर्व विधायक रणवीर यादव को भी क्लीन चिट दिया था. रणवीर यादव की पत्नी पूनम यादव फिलहाल जदयू से खगड़िया जिले से विधायक हैं. मुख्यमंत्री की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में जब नीतीश के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया था तो उन्होंने साथ चल रहे गार्ड की कार्बाइन छीन कर लहराई थी और फायरिंग भी की थी. अब यही रणवीर यादव मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं. रणवीर मामले में जदयू के ही नेता कहने लगे हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए. रणवीर ने यह विरोध चिंतन शिविर के बाद दर्ज कराया है. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि शिविर में हम लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया. वे साफ कहते हैं कि सरकार में अधिकारियों का बोलबाला हो गया है वे जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करते हैं.

सूबे में बढ़ती अफसरशाही और नीतीश की कार्यशैली और उन्हें तानाशाही बताने वाले रणवीर पहले नेता नहीं हैं. इससे पहले राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी, मंत्री नरेंद्र सिंह भी विरोध दर्ज कर चुके हैं. विधायक नीरज कुमार बबलू, छेदी पासवान, रमई राम खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. नीतीश के करीबी विधायक माने जाने वाले बबलू ने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए. विधायक छेदी पासवान भी नरेंद्र मोदी के प्रशंसक में से माने जाते हैं. इसी वजह से पार्टी ने उन्हें छह वर्षों के लिए निलंबित भी कर दिया है. छेदी कहते हैं कि पार्टी में भूचाल जैसा तो है ही लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि विधायक चुप क्यूं हैं. जिनके पास भी स्वाभिमान बचा है, उन्हें पार्टी को छोड़कर अलग हो जाना चाहिए. इससे पहले ही तीन सांसद जयनरायण निषाद, पूर्णमासी राम और मंगनी लाल मंडल पार्टी से अलग लाइन तय कर चुके हैं. अभी थोड़े ही दिन पहले जदयू के बाहुबली विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह अपने ही जिले बेगूसराय में जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ चार दिनों की भूख हड़ताल कर चुके हैं. उन्होंने भी आरोप लगाया था कि अफसरशाही बढ़ गई है. साथ ही यह भी चिंता जताई थी कि जब जिले के अफसर हमारे आवेदन को महीनों बीत जाने के बाद भी संज्ञान में नहीं लेतें हैं तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा.

जदयू को दागदार करने वाले चेहरे में नावादा जिले से गोविंदपुर के विधायक कौशल यादव भी हैं. कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव भी नवादा विधानसभा से विधायक हैं. कौशल काफी दिनों से फरार चल रहे हैं. उनपर जिला प्रशासन ने गबन का मामला दर्ज किया है. नवादा दंगे के दौरान विरोधी दलों के द्वारा यह आरोप भी लगाया गया था कि दंगे भड़काने में कौशल यादव और उनके करीबी विधान पार्षद सलमान रागीव का भी हाथ था. जानकार बताते हैं कि विस्फोट के बाद भाजपा को नया मुद्दा मिल गया है नहीं तो ये जदयू के बाहुबली विधायकों और उनके नये–नये कारनामों को ही अपना मुद्दा बनाती. और जदयू के बाहुबली नेता या विधायक आए दिन कारनामे करते ही रहते हैं. दरौंदा से जदयू की विधायक हैं कविता. इनके पति हैं अजय सिंह. अजय सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, हाईकोर्ट उन्हें सज़ा भी सुना चुका है. जगमातो देवी के निधन के बाद दरौंदा की सीट खाली हुई थी. चूंकि अजय आपराधिक चरित्र के थे, इसी वजह से मुख्यमंत्री के कहने पर आनन–फानन में अजय शादी रचाते हैं और उनकी पत्नी को कविता को टिकट दिया जाता है. पिछले दिनों ख़ुद आठवीं पास अजय बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को कब्ज़ाने के चक्कर में चर्चे में आए थे. फ़िलहाल इसके अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल सुलभ हैं. मामला इतना बढ़ गया कि सम्मेलन परिसर में दोनों पक्षों के बीच झगड़े की नौबत आ पड़ी थी. बीच में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था. इतना ही नहीं, जिस दौरान बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी इस समय पार्टी विधायक सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे को लेकर परेशान रही ही थी. अधिकार रैली के तैयारियों के दिन में जेल में बंद मुन्ना शुक्ला भी परेशानी खड़ी कर ही चुके हैं. मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नु शुक्ला फिलहाल लालगंज से जदयू की विधायक हैं. आरोप लगा था कि मुन्ना शुक्ला ने रैली के लिए एक इंजीनियरिंग कालेज के संस्थापक से सात करोड़ की रंगदारी की मांग की थी. अभी पिछले दिनों ही माले के महासचिव यह कह चुके हैं कि चारा घोटाले में सिर्फ़ लालू को ही सज़ा नहीं हुई है. लोगों को बराबर बताया जाना चाहिए कि इसमें जदयू के सांसद जगदीश शर्मा की भी सांसदी गई है और उन्हें सज़ा सुनाई गई है. इससे पहले ही जदयू के ही पूर्णमासी राम यह कह चुके हैं कि चारा घोटाले में नीतीश का भी नाम है और अगर वे दोषी हैं तो उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए. वैसे पार्टी में दागी नेताओं की कमी नहीं है. जदयू के 118 में से 43 विधायकों के ख़िलाफ़ गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.

हाल यह है कि पार्टी से गोह के विधायक रणविजय सिंह जेल से ही रहकर चुनाव जीते है. जदयू के नीरज कहते हैं कि हाल के दिनों में हुई घटनाएं हमारे लिए त्रासदी से कम नहीं हैं. लेकिन दुखद यह है कि आतंकी घटना पर भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है. एक होकर लड़ने के बजाय हमारी कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है. नीरज पूछते हैं कि जब संसद पर हमला हुआ था तो क्या इस समय क्या, इस समय भी हमें अटलबिहारी वाजपयी की कार्य क्षमता पर सवाल उठाना चाहिए था. नीरज कहते हैं कि हमारी पार्टी कुशल क्रियान्वयन कर रही है, हम चुनौती से निपट लेंगे. लेकिन राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन की मानें तो नीतीश की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है. महेंद्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर असंतोष नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह काफ़ी हद तक पट गई है. और जैसे–जैसे बीजेपी मजबूत होगी जेडीयू के अंदर का असंतोष बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अभी तो दो ही मुद्दे नरेंद्र मोदी और अफसरशाही पर उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है, चुनाव आते–आते कई मुद्दे नीतीश के लिए चुनौती बनेंगे. साथ ही महेंद्र यह भी कहते हैं कि आज जो उनके छोटे–छोटे नेता या बाहुबली नेता सवाल खड़े करने लगे हैं. इसकी वजह साफ़ है कि अब उन्हें लगने लगा है कि नीतीश में अब वो करिश्मा नहीं रह गया है. अब नीतीश का सामाजिक समीकरण भी टूट रहा है. बहरहाल नीतीश की परेशानियां कम होती दिख नहीं रही हैं. आए दिन असंतोष के स्वर उभर रहे हैं. लेकिन नीतीश हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं. ■

कुशल यादव

मुन्ना शुक्ला

नीरज कुमार बब्लू

तक़ी अख्तर

अनील साहनी

बोगो सिंह

feedback@chauthiduniya.com

बसपा का कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ने से सपा के माथे पर बल पड़ गए हैं. सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ रही तल्खियों और हमलावर हो चुकी भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के पास भी बसपा ही एकमात्र विकल्प बताई जा रही है. चर्चा है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी को लेकर ज्यादा सहज महसूस नहीं करते हैं.

माया-मुलायम लिखेंगे नई पटकथा

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में एक अलग किस्म की चर्चा छिड़ी है. चर्चा के केन्द्र में कांग्रेस–सपा–बसपा की तिकड़ी है. राजनीति के कुछ मठाधीश अगले वर्ष पांच राज्यों में होने वाले आम चुनाव से पहले ही चुनाव के बाद की तस्वीर उकेरने में लगे हैं. यह लोग माया–मुलायम की राजनीति सोच और स्टाइल को समझकर यूपी की भावी सियासत का अनुमान लगा रहे हैं. राजनैतिक पंडितों का विश्लेषण और सपा–बसपा के खेमों से जो ख़बरें आ रही हैं, इससे लगता है कि दोनों ही दल नये साल पर कुछ बड़े धमाके कर सकते हैं. बात सत्तारूढ़ सपा की करें तो सपा में एक वर्ग कांग्रेस से दूरी बनाए रखने के पक्ष में है. यह धड़ा चाहता है कि चार राज्यों के नतीजे देखने और संसद का शीतकालीन सत्र निपट जाने के बाद केन्द्र की मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए. इससे 2014 के चुनावी जंग में पार्टी को बड़ा फायदा और सहूलियत मिल सकती है. कांग्रेस से अलग होने के बाद सपा प्रमुख तीसरे मोर्चा के गठन की बात करेंगे तो उनकी बातों का गंभीरता से लिया जाएगा. इसके अलावा काफी हद तक केन्द्र की यूपीए गठबंधन सरकार के पाप से भी पीछा छूट जाएगा. सपा जनता को यह बताएगी कि हमने यूपीए सरकार को समर्थन सिर्फ साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए दिया था. अगर सत्ता सुख उठाना होता तो हम भी सरकार को बाहर से समर्थन देने के बजाय सरकार का हिस्सा बन सकते थे. यह बात जनता के समझ में भी आएगी.

बात बसपा की करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी मंथन में लगी हैं. अभी तो उनका ध्यान चार राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है. बसपा इन राज्यों में थोड़ा–बहुत ही सही, अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती है. बसपा के लिए समस्या यह है कि वह यूपी में अपने आप को चुनावी लड़ाई में बनाए नहीं रख पा रही है. ब्राहमण और क्षत्रिय वोटर उससे दूर चला गया है. मुसलमानों में भी बसपा को लेकर अब कोई खास क्रेज नहीं रहा है. हालांकि इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बसपा का दलित वोटर माया की अचल सम्पति जैसा है, जो समय आने पर अपनी ताकत दिखा भी देते हैं. जहां तक बात कांग्रेस की है तो उसके पास राहुल एक मात्र सहारा हैं. राहुल गांधी से किसी को चमत्कारी परिणाम की उम्मीद नहीं है. इस बात का एहसास पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में हो भी चुका है. ऐसे में बसपा और कांग्रेस एक हो जाएं तो

सपा–भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज सकती है. लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कांग्रेस–बसपा गठबंधन को हवा देने वालों की नजर फिलहाल दिल्ली समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं. बसपा दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान कर चल रही है. उसे लगता है कि अगर यहां उसका रिकार्ड अच्छा रहा तो बसपा का भविष्य अपने आप सुनहरा हो सकता है. इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी कद्दावर नेताओं को इन राज्यों में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगा रखा है. इन दिनों बसपा के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है. मिजोरम को छोड़कर चार राज्यों में अभी बसपा के सिर्फ 17 विधायक हैं. मिजोरम में उसने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है.

छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव आगामी 11 नवंबर को है. यहां से बसपा के दो विधायक हैं. पार्टी 90 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की संख्या दहाई तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, यहां दूसरे चरण का चुनाव 19 नवंबर को है. इस दौरान मायावती की पांच सभाएं वहां प्रस्तावित हैं. मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को चुनाव है. यहां

बसपा के सात विधायक हैं. राजस्थान में एक दिसंबर को चुनाव हैं. पार्टी के यहां छह विधायक हैं और दिल्ली में चार दिसंबर को चुनाव है. बसपा के यहां दो विधायक हैं. बसपा इन चारों राज्यों में 60–70 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है. चुनाव परिणामों के बाद ही बसपा सुप्रीमो लोकसभा की रणनीति तैयार करेंगी.

बसपा का कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ने से सपा के माथे पर बल पड़ गए हैं. सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ रही तल्खियों और हमलावर हो चुकी भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के पास भी बसपा ही एकमात्र विकल्प बताई जा रही है. चर्चा है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी को लेकर ज्यादा सहज महसूस नहीं करते हैं. कहा जा रहा है कि राहुल से करीबी बनाए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस और बसपा गठबंधन के सूत्रधार हो सकते हैं. बेनी प्रसाद कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की बात बीतों दिनों कह भी चुके हैं. वह किसी भी तरह से सपा को हाशिये पर डालने की कोशिश में हैं. यही हाल बसपा का भी है, वह जानती है कि समाजवादी पार्टी के बढ़ने का मतलब बसपा का रसातल में जाना है. यह स्थिति शायद ही बसपाई पैदा करना चाहेंगे.

बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मंथन में लगी हैं. अभी तो उनका ध्यान चार राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है. बसपा इन राज्यों में थोड़ा-बहुत ही सही, अपनी ताक़त में इज़ाफ़ा करना चाहती है. बसपा के लिए समस्या यह है कि वह यूपी में अपने आप को चुनावी लड़ाई में बनाए नहीं रख पा रही है. ब्राहमण और क्षत्रिय वोटर उससे दूर चला गया है. मुसलमानों में भी बसपा को लेकर अब कोई ख़ास क्रेज नहीं रहा है. हालांकि इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बसपा का दलित वोटर माया की अचल सम्पति जैसा है, जो समय आने पर अपनी ताक़त दिखा भी देते हैं.

कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलकर समाजवादी सरकार की नाकामी का फायदा उठाने का तानाबाना बुन रही है तो दोनों दलों के बीच कुछ किंतु–परंतु भी सुनाई दे रहे हैं. बसपा सुप्रीमो को एक तो राहुल गांधी का दलित प्रेम रास नहीं आ रहा है, वहीं उनका पुराना दर्द भी किसी से छिपा नहीं है. बसपा ने जितनी बार भी किसी दल से गठबंधन किया, उसका फायदा बसपा से अधिक गठबंधन करने वाले दूसरे दल ने उठाया. बसपा सुप्रीमो तो अपने वोटरों से किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट डलवा देती हैं, लेकिन उनके साथ गठबंधन करने वाले दल ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिससे बसपा को नुकसान उठाना पड़ता है, यही एक पेंच बसपा और कांग्रेस के बीच फंस रहा है. जो हालात बन रहे हैं इसको देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपनी राजनैतिक गणित दुरुस्त करने में लगी बसपा और सपा आने वाले वर्ष में कोई बढ़ा धमाका कर सकते हैं. ■

सांप्रदायिकता पर चुप क्यों है माकपा

अरुण तिवारी

रिलीजन इस ओपियम ऑफ मासेज यानि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है. मार्क्स का यह सिद्धांत शायद भारतीय परिपेक्ष्य में सर्वाधिक सटीक बैठता है. भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीति का स्वभाव पूरी तरह जाति–धर्म आधारित ही है. ऐसी स्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं और सांप्रदायिक व धर्मनिरपेक्ष जैसे मुद्दों को लेकर लगातार बहस हो रही है, ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) का ऐसी बहसों में कहीं भी न दिखना आश्चर्य पैदा करता है. जबकि यह पार्टी हमेशा से इन मसलों पर मुखर रही है. जबकि जातीय भेदभाव मिटाना और सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में लड़ना पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल है.

भाजपा के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद से देश की राजनीति में सांप्रदायिकता को लेकर तरह–तरह की बयानबाजी सामने आ रही है. अपने गुजरात मॉडल का लाख ढिंढोरा पीटने के बावजूद दंगों का जिन्न मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है. कांग्रेस समेत अपने को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली सभी पार्टियां लोगों के बीच इस बात को फैलाने से नहीं चूक रही हैं कि मोदी के देश में प्रधानमंत्री बनते ही देश पूरी तरह सांप्रदायिका की चपेट में आ जाएगा. लेकिन कांग्रेस खुद को चाहे जितना धर्मरिपेक्ष बताने की कोशिश करे, 84 दंगों के कारण जनता उसकी बात मानने की स्थिति में नहीं दिखती. वहीं भाजपा के पुराने सहयोगी रहे जदयू ने भी अपना गठबंधन इस मुद्दे को लेकर तोड़ लिया लेकिन जनता के बीच उसके इस काम के लिए तारीफ कम किरकिरी ही ज्यादा हुई. जदयू की स्थिति गुड़ खाओ, गुलगुले से परहेज जैसी हो गई है. जदयू–भाजपा गठबंधन 17 वर्षों तक रहा. जिस दौरान गुजरात दंगे हुए उस दौरान नीतीश मोदी के समर्थक रहे. न सिर्फ उन्होंने मोदी का पूरी तरह समर्थन किया, बल्कि गुजरात दंगे के बाद उन्होंने ने एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा था उनकी ऐसी इच्छा है कि मोदी गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश की राजनीति में भी अपना योगदान देंगे. ऐसे में उनका विरोध भी जनता में बहुत असर नहीं डाल सका. कमोबेश यही अवस्था सभी राजनीतिक पार्टियों की है.

इन सभी पार्टियों का अपवाद सिर्फ माकपा

ही है. हाल ही तीसरे मोर्चे के गठन के लिए हुए एक कार्यक्रम में पार्टी ने कहा है कि तीसरे मोर्चे का गठन सिर्फ सत्ता के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि मोदी जैसे व्यक्ति को सत्ता में आने से रोकने के लिए भी जरूरी है. वहीं पार्टी ने हाल ही गुजरात दंगों के दौरान हाथ जोड़ी हुई फोटो की वजह से मीडिया में सुर्खियां बनने वाले कुतुबुद्दीन अंसारी को सम्मानित किया. जो यह दर्शाता है कि पार्टी अपने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए काम करते रहना चाहती है. वहीं जहां राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, जुमले पर काम करते हुए जहां अन्य क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र में सबसे बड़ी किसी भी पार्टी से समझौता करने की नौबत में हैं. ऐसी अवस्था माकपा का एजेंडा स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था में वह भाजपा का विरोध करेगी.

लेकिन जिस तरीके से मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद देश में उनके पक्ष में एक तरह की लहर देखी जा रही है, उस तरह की कोई भी लहर माकपा के विरोध में नहीं देखी जा रही है. वह भाजपा या मोदी के विरोध में तो दिखती है लेकिन विरोध में वह ताकत नहीं दिखती जो मोदी को रोकने जैसी हो. वहीं कांग्रेस की पूरी चुनावी मुहिम अपने एजेंडों को छोड़कर मोदी विरोध पर आकर टिक गई है.

हालांकि माकपा अध्यक्ष प्रकाश करात बीते दिनों कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर नहीं, बल्कि मुद्दों पर लड़ा जाएगा. इन चुनावों में व्यक्तियों की पहचान नहीं चलेगी, वरन जनता मुद्दों पर वोट करेगी. लेकिन करात की बात वास्तविकता में साबित होती नहीं दिख रही है क्योंकि सभी चुनावी सर्वेक्षणों में भाजपा द्वारा आगामी चुनाव में सबसे अधिक सीटें लाए जाने का अनुमान लगाया है. वहीं मोदी को भावी पीएम के रूप में देखने वालों की संख्या भी देश में काफी बड़ी है. ऐसे में माकपा द्वारा किसी बड़े चुनावी विरोध की शुरुआत होते न दिखना पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े करता है. जहां सभी पार्टियों द्वारा सांप्रदायिकता के नाम पर लगातार बयान आ रहे हैं, ऐसे में इस मसले पर पार्टी की कोई गंभीर प्रतिक्रिया न आना गंभीर मसला है. गरीबों और शोषितों की बात करने वाली माकपा को अगर अपने पुराने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसे उसी धार के साथ अपनी विचारधारा जनता तक पहुंचानी होगी जिस प्रकार दूसरी राजनीतिक पार्टियां पहुंचा रही हैं.

आगामी लोकसभा चुनाव देश का भविष्य निर्धारित करेंगे और कई मायनों में ऐतिहासिक भी होंगे. जहां इस बात के आसार हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं वहीं उनके हिंदू राष्ट्रवाद और औद्योगिक विकास की धुर विरोधी रही माकपा का इस दौरान चुप रहना और सीधे सामना न करना अखरता है. हालांकि तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है जिसमें कई पार्टियों को जोड़कर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने की फिराक में पार्टी अपनी योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश में है. ■

भाजपा के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद से देश की राजनीति में सांप्रदायिकता को लेकर तरह-तरह की बयानबाज़ी सामने आ रही है. अपने गुजरात मॉडल का लाख ढिंढोरा पीटने के बावजूद दंगों का जिन्न मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है. कांग्रेस समेत अपने को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली सभी पार्टियां लोगों के बीच इस बात को फैलाने से नहीं चूक रही हैं कि मोदी के देश में प्रधानमंत्री बनते ही देश पूरी तरह सांप्रदायिकता की चपेट में आ जाएगा. लेकिन कांग्रेस खुद को चाहे जितना धर्मरिपेक्ष बताने की कोशिश करे, 84 दंगों के कारण जनता उसकी यह बात मानने की स्थिति में नहीं दिखती.

feedback@chauthiduniya.com

पिछली बसपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे आशीष शुक्ला के तक़रीबन चालीस से अधिक समर्थकों ने एनजीओ आली की दो लड़कियों को अगवा कर लिया. इन लोगों ने महिला कर्मियों को शहर के खाटू श्याम मंदिर में क़ैद कर दिया और यातनाएं दी. शुक्ला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी ही बेटी अपने भाई के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न करने को लेकर मदद की गुहार के लिए आली पहुंची थी.

पूर्व मंत्री की बेटी अपने ही घर में असुरक्षित

चौथी दुनिया ब्यूरो

यूपी में राजनीतिक अपराध या राज–नेताओं की शह पर पलते अपराध की घटनाएं आम हैं. लेकिन बीते दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी जिसके मुख्य अपराधी भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि के हों, लेकिन यह हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था पर एक गहरी चोट दे जाती है. पिछली बसपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले आशीष शुक्ला के तकरीबन चालीस से अधिक समर्थकों ने एक गैर सरकारी संगठन आली की दो लड़कियों अगवा कर लिया. पूर्व मंत्री और उनके चालीस से अधिक समर्थकों ने लड़कियों को शहर के खाटू श्याम मंदिर में कैद कर दिया और तरह–तरह की यातनाएं दी. आशीष शुक्ला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी ही बेटी अपने भाई के द्वारा यौन उत्पीड़न करने के खिलाफ मदद की गुहार के लिए गैर सरकारी संगठन आली पहुंची थी.

इस पूरे मसले को जानने के लिए के लिए घटना को शुरुआत से समझना होगा. 24 अक्टूबर को एक 19 वर्षीय लड़की लखनऊ के प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन आली (एसोसिएशन फॉर एड्वोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव) आई. वह लड़की लखनऊ के ही एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा है और पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल में रह रही थी. उस लड़की को मेडिकल कॉलेज की किसी फैकेल्टी मेंबर ने आली के बारे में बताया. महिला मसलों से जुड़े कई मामलों में आली की तरफ से दायर केस में कोर्ट ने कई चर्चित फैसले दिए हैं जिनमें से लता सिंह का केस बेहद चर्चा में रहा था जिसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अंतर्जातीय विवाहों में शादी–शुदा जोड़ों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए. लड़की ने आली के सदस्यों से बताया कि घर में उसके भाई द्वारा उसका यौन शोषण किया जा रहा है. उस लड़की ने अपने परिचय में बताया कि वह बीएसपी के नेता आशीष शुक्ला की बेटी है और घर में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. आली की तरफ से एसएसपी व संबंधित थानों में यह सूचना भिजवा दी गई कि लड़की हमारे पास है, ताकि गुमशुदगी की सूचना मिलने पर पुलिस को पता रहे कि उक्त लड़की आली के पास है. आली की प्रोग्राम मैनेजर रेनू मिश्रा ने बताया कि हमने पुलिस को बताया कि लड़की कह रही है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां मेरी जान को खतरा है. अगले दिन आशीष शुक्ला उनकी पत्नी व लड़की का भाई जो कि एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ता है और चालीस से पचास लोगों का हुजूम आली के दफ्तर आ पहुंचा. वे अपनी लड़की को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे. आली के सदस्यों ने सुरक्षा की दृष्टि से लड़की को शेल्टर होम में रखा था. आशीष शुक्ला के साथ आए लोगों को जब यह पता चला कि लड़की वहां नहीं है तो उन्होंने आली की दो महिलाकर्मियों को अगवा कर लिया. संगठन के केयर टेकर ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें मारा पीटा और एनजीओ के ऑफिस में तोड़फोड़ की. हालांकि आली के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस आई और यह कहते हुए चली गई कि कोई विशेष बात नहीं है. इस बीच आशीष शुक्ला के लोग उन महिला कर्मियों को अगवा करके पास के ही खाटू श्याम मंदिर ले जाकर वहां बंधक बनाया और तरह–तरह से प्रताड़ित किया. उनके मोबाइल और पर्स छीन लिए और यह धमकी भी दी कि तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे. इसी बीच आली के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी. महानगर थाने की पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर से आशीष शुक्ला की तरफ के सात लोगों को गिरफ्तार किया. रेनू मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन लोगों के पास से तमंचे, बंदूकें व दूसरे धारदार हथियार बरामद हुए.

रेनू मिश्रा के मुताबिक यहां पर पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी महिला कर्मियों को अगवा करने में नेतृत्वकारी भूमिका आशीष शुक्ला ने निभाई है. मुख्य अपराधी तो वे हैं फिर उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया.

आली की प्रोजेक्ट मैनेजर रेनू मिश्रा ने बताया कि उसी रात में एसडीएम के सामने बयान दिलाने का दबाव डाला जबकि ऐसा अपरिहार्य कारणों में ही होता है कि एसडीएम के सामने बयान लिया जाए, नियमत: बयान मजिस्ट्रेट के सामने ही दिया जाता है. बहरहाल एसडीएम के सामने भी पीड़िता ने बयान दिया कि वह अब अपने घरवालों के पास नहीं जाना चाहती.

अगले दिन डिस्ट्रिक कोर्ट में पेशी हुई चूंकि आशीष शुक्ला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी इसलिए 164 के बयान के तहत लड़की को कोर्ट में पेश किया गया ताकि पीड़ित लड़की बताए वह किसके साथ जाना चाहती है. कोर्ट में भी एक बार आशीष शुक्ला के लोगों ने आली की महिला कर्मियों से बद्तमीजी की. साथ ही कोर्ट में यह दलील पेश की कि आली संगठन के लोगों ने पीड़ित लड़की को ड्रग्स दे दिया है जिससे वह होशो–हवाश में नहीं है. पीड़ित लड़की ने अपने बयान में जज के सामने कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से यह फैसला ले रही है कि वह अपने घर वालों पास नहीं जाना चाहती. साथ ही लड़की ने यह भी कहा कि उसे अपने घर वालों से ही अपनी जान को खतरा है इसलिए उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए. उसके इस निवेदन पर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक पीड़ित लड़की लखनऊ में है उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

एक तरफ जब पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित किया जा रहा है और उसके हल तलाशे जा रहे हैं ऐसे में एक परिवार के भीतर अपने सगे भाई द्वारा एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया जाना हमें सोचने को मजबूर करता है.

हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया लेकिन अब पुलिस ने इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए आर–ोपी बसपा नेता आशीष शुक्ला व उनके बेटे आकर्ष की तलाश में टीमें अमेठी समेत अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. साथ ही बसपा नेता के अमेठी स्थित घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है. यह घटना वास्तव में समाज और हमारी पारिवारिक व्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाती है. एक तरफ़ जब पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित किया जा रहा है और उसके हल तलाशे जा रहे हैं ऐसे में एक परिवार के भीतर अपने सगे भाई द्वारा एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया जाना हमें सोचने को मजबूर करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर उठते सवाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

पिछले दिनों युगांडा में भारतीय मूल के हरीश शर्मा की उनके कार्यस्थल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. हरीश मेसर्स बिग बॉस में मुख्य निदेशक के पद पर कार्यरत थे. भारतीय मूल के ही अभय बंसल इस फर्म के मालिक हैं. 29 सितंबर 2013 को अभय बंसल और हरीश शर्मा कंपनी के ऑफिस में अभय बंसल के केबिन में बैठे हुए थे, उसी समय कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम नजीबू बुरहानी था उसने हरीश शर्मा की तरफ बंदूक तान दी और पैसे मांगने लगा. इसके पहले की हरीश शर्मा उसे कोई जवाब देते उस गार्ड ने उन्हें गोली मार दी. जबकि अभय बंसल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा.

अभय बंसल के मुताबिक उन्होंने किसी तरह से अपनी रक्षा करते हुए उस गार्ड को ऑफिस से बाहर निकाला. दरअसल यहीं से इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका नजर आने लगती है. दोषी सिक्योरिटी गॉर्ड नजीबू बुरहानी डेल्टा सिक्योरिटीज का कर्मचारी था. इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह कंपनी के मालिक अभय बंसल हैं और उन्होंने ही इसकी एफआईआर लिखवाई. रिपोर्ट में कहा गया है डेल्टा सिक्योरिटीज 24 घंटे उनकी कंपनी को सुरक्षा प्रदान करती थी और गार्ड की शिफ्ट दिन में दो बार बदल जाती है. जबकि गार्ड नजीबू बुरहानी पिछले तीन दिनों से काम कर रहा था और उसने गॉर्ड के अटेंडेंस रजिस्टर में दस्तख़त भी नहीं किए थे. रिपोर्ट में इस पर बात का भी जिक्र किया गया है कि नजीबू बुरहानी उस व्यक्ति का असली नाम था भी या नहीं. हालांकि इस हादसे के बाद डेल्टा सिक्योरिटी ने मेसर्स बिग बॉस से नाता तोड़ लिया है.

युगांडा में छपी खबरों के अनुसार अभय बंसल ने क्षेत्रीय पुलिस को बताया उनकी जान को अल्ताफ और तरुण कपूर नाम के दो बिजनेसमैन से डिफरेंसेज की वजह से जान का खतरा है. अभय बंसल ने रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया है कि उन्होंने व हरीश शर्मा ने पुलिस में इन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि अल्ताफ और तरुण ने बिजनेस के सिलसिले में 20 मिलियन शिलिंग का एक चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था. और जब यह हादसा हुआ तो इन दोनों ही पार्टियों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे.

इस पूरे मसले को लेकर युगांडा सरकार हीलाहवाली के रवैये पर है. सरकार कुछ भी नहीं बता रही है और न

स्व. हरीश शर्मा

ही इसकी कोई जिम्मेदारी ले रही है. चूंकि डेल्टा सेक्योरिटीज एक नामी सुरक्षा एजेंसी है इसलिए उस एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने सुरक्षा कर्मियों के नाम पते का पूरा डेटा रखे. दूसरे अभय बंसल कंपनी के मुख्य निवेशक हैं, जबकि हरीश शर्मा मात्र एक कर्मचारी, इसलिए उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी हरीश शर्मा को क्यों निशाना बनाएंगे. एक और बात जो खटकने वाली है कि अगर आरोपी ने पैसे मांगे तो उसने पैसे हरीश शर्मा से क्यों मांगे? उसे तो बंसल से पैसे मांगने चाहिए थे क्योंकि कंपनी के ऑनर तो वही हैं. साथ ही अगर बंसल यह साफ कह रहे हैं कि अल्ताफ और कपूर से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वे व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी थे तो उनको गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं की गई.

भारत सरकार ने अपनी तरफ से इस मामले में पूरी तत्परता दिखाई है, लेकिन युगांडा सरकार की तरफ से इस मसले को अलग–अलग तरह से पेश किया जा रहा है और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया. अभी तक कि जो जांच युगांडा पुलिस कर रही है वह केवल अभय बंसल के बयान के आधार पर है जो कि मात्र खानापूर्ति हैं क्योंकि अगर पुलिस और भी आधारों पर जांच करे तभी वास्तविकता सामने आएगी. युगांडा की बड़ी अर्थव्यस्था भारतीयों द्वारा संचालित की जाती है.

ऐसे में अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाती और अगर वहां की सरकार ही ऐसे मसलों को लेकर गंभीर नहीं होती तो फिर विदेशों में व्यापार या नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं में भय का माहौल बनता जाएगा. स्व. हरीश शर्मा के परिवार वालों की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेयर्स में सलमान खुर्शीद के नाम पत्र लिखकर भी इस मामले को संज्ञान में लेकर युगांडा पर दबाव बनाने की बात की गई है. यह बात केवल इस प्रकरण या युगांडा सरकार तक ही सीमित नहीं है. यह देश के उन लाखों लोगों से जुड़ा है जो नौकरी या व्यापार के सिलसिले में विदेशों में है. यह दो तरफा प्रक्रिया है इसका लाभ वहां की अर्थव्यवस्था को ही मिल रहा है. अगर ऐसे मसलों को दोनों ही देशों की सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया तो जाहिर तौर पर देश का कोई भी नागरिक नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने से पहले हिचकिचाएगा जरूर. ■

feedback@chauthiduniya.com

नया मीडिया और जन संवाद का सम्मान

चौथी दुनिया ब्यूरो

मीडिया के वेब अवतार को अपार लोकप्रियता हासिल हो रही है. ब्लॉगर, लेखक और विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने विचार लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं. मीडिया के इस अवतार को नई पीढ़ी ने हाथों हाथ लिया है, स्मार्ट फोन के बढ़ते प्रचलन ने वेब मीडिया के दायरे को और बड़ा कर दिया है. हर कोई दुनिया की हर एक छोटी बड़ी खबर अपनी मुट्ठी में रखता है. खबर या लेख पर अपनी मुखर प्रतिक्रिया सबके सामने रखता है. लोगों के बीच इसी तरह के बेहद लोकप्रिय वेब पोर्टल प्रवक्ता डॉट कॉम ने हाल ही में अपनी स्थापना के पांच वर्ष पूरे किए. इस अवसर पर एक नया मीडिया और जन संवाद विषय पर संगोष्ठि आयोजित की गई और वेब मीडिया के क्षेत्र के विकास में कार्य करने वाले देश–विदेश के 16 लेखकों और पत्रकारों का सम्मान किया. पुरस्कार पाने वालों में ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक नरेश भारतीय, अमेरिका के युनिवर्सिटी ऑफ मॅसाच्युसेटस, निर्माण अभियांत्रिकी के प्रोफेसर मधुसूदन व हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी से जुड़े डॉ कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक समन्वय डॉ मनीष कुमार, प्रो. जगदीश्वर चतुर्वेदी (पश्चिम बंगाल) गिरीश पंकज (छत्तीसगढ़), संजय द्विवेदी (मध्य प्रदेश), आर. सिंह (नई दिल्ली), डॉ. राजेश कपूर (हिमाचल प्रदेश), डॉ. पुरुषोत्तम मीणा निरंकुश' (राजस्थान), विपिन किशोर सिन्हा (उत्तर प्रदेश), राकेश कुमार आर्य (नई दिल्ली), सुरेश चिपलूनकर (मध्यप्रदेश), राजीव रंजन प्रसाद (छत्तीसगढ़), पंकज कुमार झा (छत्तीसगढ़) और मो. इकबाल हिंदुस्तानी (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. प्रवक्ता के संपादक संजीव सिन्हा के अनुसार जिन लेखकों का सम्मान किया गया है उनकी खासियत है कि उनकी लेखनी में जबरदस्त जान है, उनके लिखे पर अच्छी टिप्पणियां आती हैं, उनके लेखों को पढ़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है और वे दबाव और प्रभाव में आए बिना अपने स्वभाव के अनुसार लेखन करते हैं. इसके साथ ही वे सब प्रवक्ता से भावनात्मक स्तर पर भी जुड़े हुए हैं.

संजीव सिन्हा ने यह भी बताया कि, जब प्रवक्ता डॉट कॉम की शुरुआत हुई थी तब हमारे सामने प्रश्न आया कि लेखक तो अपने संपर्क हैं ही नहीं? इसके बाद हमने लेखकों की एक सूची बनाई और उनसे सबसे आग्रह किया कि प्रवक्ता के लिए अपने लेखकों की एक सूची बनाई और उनसे अनुरोध किया कि हमें अपने लेख भेजें. हर्ष का विषय है कि उनमें से अधिकांश लेखकों का सहयोग हमें मिला. हालांकि हमारी निरंतरता और गुणवत्ता को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से गत पांच वर्षों में लेखकों की संख्या 500 को पार कर गई. प्रवक्ता की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साइट पर अभी तक विभिन्न विषयों पर 9,000 से अधिक हिन्दी के लेख उपलब्ध हैं.

वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव से प्रवक्ता सम्मान प्राप्त करते डॉ. मनीष कुमार

वास्तव में इंटरनेट सभी को अपनी जद में लेता जा रहा है. लेकिन इसी के साथ यहां पुष्ट और गंभीर खबरों की कमी भी दिख रही है. प्रवक्ता डॉटकॉम के मुतबिक जिन वेब पत्रकारों का सम्मान किया गया है उन्होंने इस माध्यम की गंभीरता को समझा है और उसे आगे बढ़ाने में गंभीर भूमिका निभाई है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पिसते लोग

1925 में गठित हुई संस्था के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जो राजनीति के अलावा अन्य गतिविधियों में समय की कसौटी पर खरी उतरी है. इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है यदि कोई संस्था हिंदू पुनरुत्थानवाद, हिंदू संस्कृति के संरक्षण, हिंदू परंपरा, वेदों और उपनिषदों के लिए समर्पित है, लेकिन यह बात बिल्कुल अलग हो जाती है, जब यह सब मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध वैमनस्यता का हथियार बन जाता है. वे कहते अलग हैं और करना अलग चाहते हैं.

देश में राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार वास्तविकता में तो पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जिस तरह सार्वजनिक रूप से बहस कर रहे हैं, उससे यह साफ़ हो गया है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है. लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी न तो देश के सामने मौजूद समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, न ही यह बता रहा है कि अगर वे प्रधानमंत्री बन गए तो इन समस्याओं के निदान के तौर पर क्या करेंगे. दोनों एक–दूसरे पर हमला कर रहे हैं. एक–दूसरे की ख़ामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. यह सब कुछ इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को अब इस ओछेपन पर हंसी भी नहीं आती. इन सबके बीच एक और हास्यास्पद घटना यह सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाह रही है. इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं हो सकती. वास्तव में इतिहास को झूठा साबित करना बेहद आसान होता है और भारतीय जनता पार्टी नेहरू कुछ और थे और पटेल कुछ और, कहकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है.

कोई भी दो समझदार व्यक्ति हर बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं, उनके बीच मतभेद होंगे ही. लेकिन उनके बीच मतभेद बेहद कम थे जो कि ध्यान देने योग्य भी नहीं हैं. उन्होंने एक बेहतर कुशल और मज़बूत टीम की तरह काम किया. सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. पटेल को आरएसएस के प्रति उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की वजह से सहानुभूति थी. सरदार पटेल आरएसएस से राजनीति में नहीं आने और सांस्कृतिक मामलों तक सीमित रहने का हलफ़नामा भरवाकर लगे प्रतिबंध को हटा लेने के पक्षधर थे. उन्होंने ऐसा किया और प्रतिबंध हटा लिया गया. यह अलग मसला है कि आरएसएस हमेशा तीखी ज़बान में बात करती है. वह एक बात कहते हैं और ठीक उसके उलट करते हैं.

पिछले कुछ सालों में उन्होंने मुख्य रूप से राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया. जनसंघ उनकी राजनीतिक शाखा थी. 1977 में जयप्रकाश नारायण के दबाव में उन्होंने सभी पार्टियों के साथ जनता पार्टी में विलय कर लिया. लेकिन आरएसएस काडर इस निर्णय से ख़ुश नहीं था. वे इस बात से भी ख़ुश नहीं थे कि वाजपेयी, आडवाणी और अन्य लोग मंत्री बनें. वे लोग उन्हें केवल आरएसएस की संपत्ति बने रहने देना चाहते थे. इसलिए सन 1980 में बंबई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ. आज भाजपा 33 साल की हो चुकी है, अपने वजूद के तौर वह जनसंघ के उत्तराधिकारी के अलावा और कुछ नहीं है. यह आरएसएस की राजनीतिक शाखा है.

आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक ने अब खुले तौर पर यह कहकर कि अब आरएसएस राजनीति में हस्तक्षेप करेगा और राजनीति में शामिल होगा, एक ऐसे संगठन जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत रही है उसको चोट पहुंचाई है.

1925 में गठित हुई संस्था के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जो राजनीति के अलावा अन्य गतिविधियों में समय की कसौटी पर खरी उतरी है. इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है यदि कोई संस्था हिंदू पुनरुत्थानवाद, हिंदू संस्कृति के संरक्षण, हिंदू परंपरा, वेदों और उपनिषदों के लिए समर्पित है, लेकिन यह बात बिल्कुल अलग हो जाती है, जब यह सब मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध वैमनस्यता का हथियार बन जाता है. वे कहते अलग हैं और करना अलग चाहते हैं. यह बहुत ही शर्मनाक है कि अब वे पटेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि 2500 करोड़ रुपये की लागत से पटेल की मूर्ति बनाने का क्या औचित्य है? अन्य मसलों की तुलना में इसे वरीयता देने का क्या कोई आधार है? गुजरात जैसे राज्य में भी ग़रीबी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है. यहां अभी भी ग़रीबी है, यहां एक मूर्ति स्थापित करने के बजाए बहुत से अन्य बेहतर कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है. हालांकि, एक बात यहां साफ़ हो जानी चाहिए एक मूर्ति के निर्माण में अथाह पैसा ख़र्च करके सरदार पटेल का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है और इस हक़ीक़त पर परदा नहीं डाला जा सकता है कि पटेल, नेहरू के एक प्रमुख सहयोगी और कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख स्तंभ थे. बीजेपी इस तथ्य को कभी नहीं बदल सकती है. उसे यह बात भूल जानी चाहिए.

एक दूसरा सवाल जो कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, वह है बेलगाम होती महंगाई. यह तब तक ठीक है जब तक रीयल एस्टेट और अन्य चीज़ों के दाम बढ़ें, लेकिन जब बात रोजमर्रा की चीज़ों की क़ीमतें बढ़ने पर आ जाए और उस पर रोक न लगाई जा सके तो ग़रीब और आम आदमी दबाव में होता है. प्याज को ही ले लें, लेकिन अंततः प्याज की खपत बहुत ज्यादा नहीं है. इसलिए जब इसकी क़ीमतें बढ़ती हैं, तब ज़ेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है. लेकिन मैंने सुना है कि कोलकाता जैसी कुछ जगहों से आलू ग़ायब हो गया है. अब आलू एक प्रमुख भोजन है, जो लोग हरी सब्ज़ियां नहीं ख़रीद सकते हैं, वे कम से कम आलू तो खा सकते हैं.

यदि आलू और प्याज जैसी चीज़ें भी बहुत ऊंची दरों पर मिलने लगें तो ग़रीब आदमी के पास कुछ भी नहीं बचेगा. यहां क्रांति की जगह भुखमरी होगी. मैं नहीं जानता कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि बेशक अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने की प्रमुख ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन राज्य सरकारों के हाथ में नागरिक आपूर्ति विभाग की कमान होती है. यदि व्यापारी चीज़ों की जमाख़ोरी कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ छापेमारी की जानी चाहिए और डर का माहौल बनाना चाहिए. उस दौर को याद करिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब व्यापारियों को छापे पड़ने और जेल जाने का डर रहता था. मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि आप एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएं, लेकिन व्यापारी और व्यावसायिक समुदाय भी अपनी सीमा में रहे. वे आम आदमी की ज़ेब पर डाका डालकर हद से ज्यादा मुनाफ़ा नहीं बना सकते. संबंधित सरकारों को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए. नागरिक आपूर्ति विभाग के पास आवश्यक वस्तु क़ानून जैसा ताक़तवर हथियार है. यदि कुछ गोदामों में जहां चीज़ों की जमाखोरी की जा रही है, वहां छापेमारी करके उदाहरण पेश किए जा सकते हैं और सारे बाज़ार को संदेश भेजा जा सकता है. मुझे आशा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जल्दी ही इस दिशा में कार्य करेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार जन–जीवन को खोखला बना रहा है

ठाकुर दास बंग

शिक्षा सरकारी व व्यावसायिक नियंत्रण तथा डिग्रियों व प्रमाणपत्रों के बंधन से मुक्त होनी चाहिए. शिक्षण में प्रमुख भूमिका शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक की होनी चाहिए कि बालक–बालिकाओं को लोकतंत्रीय व सहयोगी समाज–जीवन का व्यावहारिक अनुभव मिले, उनमें आत्मनिर्भरता जगे तथा स्वतंत्र विचार और विवेक पर आधारित उनका नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके. शिक्षा में व्याप्त सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल आदि विषमताएं समाप्त होने चाहिए.

जाति संप्रदाय, लिंग भाषा, ऊंच–नीच आदि के भेद–भाव और झगड़ों से जनता की शक्ति टूटती है, राष्ट्रीय एकात्मता खंडित होती है और जन–जीवन में राज्य का अनावश्यक दखल बढ़ता है. वास्तव में तो जनता के लिए सहजीवन ही उसकी नियति है. अतः संकुचित भेदभाव मिटे, हरिजन, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकों पर अन्याय, अत्याचर व दमन बंद हों, स्त्रियों को समानता का दर्जा मिले, दहेज की कुप्रथा समाप्त हो और वे समाज में आदरपूर्वक एवं सुरक्षित रह सकें. ऐसा वातावरण बनना चाहिए. अत्याचार और गुंडागर्दी का हर स्तर पर संगठित मुकाबला करना चाहिए.

व्यापक भ्रष्टाचार आज जन–जीवन को खोखला बना रहा है, गरीब की रोटी छीन रहा है और समाज के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध कर रहा है. अतः लोगों को संगठित होकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना चाहिए. भ्रष्टाचार में संलग्न व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में सम्मान

व स्थान न दिया जाए. हर व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं रिश्वत देने से बचें. संगठित प्रयत्न से ऐसे अवसर बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं.

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम मनुष्य के गौरव और मानवीय मूल्यों को समाज में व निजी जीवन में किस हद तक स्थापित कर पाते हैं. गलती वहां हुई, जहां हमने समाज के व्यापक हितों की अपने स्वार्थों के लिए बलि चढ़ा दी. भारत की सांस्कृतिक विरासत हमें प्राणीमात्र के लिए श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है और हर किस्म के बंधनों को पार कर सच्ची एकता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है. उसका आधार नहीं छोड़ना चाहिए.

नया संकल्प

इस आरोहण के लिए एक नए संकल्प, नई कोशिश और वाता–वरण की जरूरत है. जनता की चेतना को जगाने तथा संगठित करने के लिए समर्पित लोकसेवकों की एक बड़ी जमात आवश्यक है. ये सेवक गांव–गांव और मोहल्ले–मोहल्ले में संपूर्ण क्रांति के लिए जनता की शक्ति को संगठित करके उसे उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण और निहित स्वार्थों द्वारा हो रहे अन्यायों के खिलाफ शुद्ध व शांतिमय साधनों से सत्याग्रह के लिए प्रेरित करें.

हम क्या करें?

इस महान कार्य के लिए–

- आप जहां कहीं हो, अपने विचार से सहानुभूति रखनेवाले लोगों की तलाश करें और उन्हें संगठित करें.
- इस काम के लिए अपना एक निश्चित समय दें–दिन में एक घंटा या सप्ताह में एक दिन.
- स्वदेशी का आग्रह रखें तथा शोषक और भ्रष्ट व्यवस्था से असहयोग करें.
- सरकार या दूसरे किसी का इंतजार न करते हुए स्थानीय स्तर पर काम शुरू करें. काम एक जगह भी सही दिशा में प्रारंभ होगा तो वह दूसरे इलाके में भी फैल जाएगा.
- नागरिक के नाते अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ–साथ कर्तव्यों के पालन की ओर भी ध्यान रखें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.

आज की परिस्थिति का तकाजा है कि इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ें. हमें विश्वास है कि आज के अंधकार को चीरकर देश को फिर से प्रकाश की ओर ले जाने की यह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी और जनता अपनी मुक्ति की इस लड़ाई में उत्साहपूर्वक भाग लेगी.

राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण इस युग का एक सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्य है. राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीकरण के सहवर्ती रूप में राष्ट्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया भी केंद्रित है. निर्णय की यह केंद्रित पद्धति अपने निर्णयों को लागू करने के लिए आमलोगों की सहमति के बदले नौकरशाही पर निर्भर होती जा रही है. इसके कारण नौकरशाही तंत्र अकड़बाज और दमनात्मक हो गया. बढ़ते केंद्रीकरण के कारण ही भारत जैसे देशों में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ती जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यापक भ्रष्टाचार आज जन–जीवन को खोखला बना रहा है, गरीब की रोटी छीन रहा है और समाज के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध कर रहा है. अतः लोगों को संगठित होकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना चाहिए. भ्रष्टाचार में संलग्न व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में सम्मान व स्थान न दिया जाय.

पाठकों की दुनिया

नेहरू गांधी परिवार

50 वर्ष से अधिक राज करने वाली कांग्रेस जनता के पैसे से अपने नेताओं की छवि चमकाने और चुनावी लाभ हासिल करने में लगी है. केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर करने का मन बना लिया है. जिससे आने वाले चुनावों कांग्रेस को वोट का फायदा मिल सके. 80 करोड़ लोगों के लिए यह योजना लाभार्थी को एक पैकेट के रूप में मिलेगी जिससे उन्हें लगेगा कि नेहरू गांधी परिवार की ओर से यह उदार भेट है. उक्त पैकेट पर हो सकता है कि इंदिराम्मा अन्न योजना बड़े अक्षरों में लिखा हो. देखा जाय तो भारत में अभी तक कुल मिलाकर लगभग 450 से अधिक केंद्रीय और प्रादेशिक परियोजनाओं और संस्थाओं का नामकरण देश की नामी गिरामी पुरानी कांग्रेस पार्टी के तीन नेताओं के नाम पर है. आश्चर्य तो यह है कि अभी तक किसी भी अधिसत्ता या एजेंसी ने सार्वजिनक धन के इस अजीबो–गरीब दुरुपयोग पर एक प्रश्न उठाना मुनासिब नहीं समझा. हालांकि मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में दिए गए राहुल गांधी के भाषण में खुफिया विभाग अधिकारी से मिली जानकारी के जिक्र पर बवंडर जरूर खड़ा किया. अपने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास घटा है. जहां तक सम्मान का प्रश्न है तो हमारे देश के महान लोगों में शामिल भाभा, सी.वी.रमन, श्रीनिवास रामानुजन हरगोविंद खुराना, डॉ अब्दुल कलाम भी इसके हकदार हो सकते हैं. हर चीज का नामकरण परिवार के नाम पर, क्या यह कांग्रेस का परिवारवाद नहीं है.

अशोक निर्मोही, *दरभंगा*

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर

ईश्वर जिसने इस धरती को बनाया, स्वर्ग को बनाया सब कुछ उसी का है. क्या उसे कुछ कमी है? हम भारतीयों में ईश्वर के प्रति अपार आस्था है. भक्ति है कट्टरपंथ भी है तो धर्म के नाम पर लोग मरने–मारने पर ऊतारू हो जाते हैं. हम बहुत भोले हैं, जो सांप्रदायिकता के नाम पर राजनेता अपना स्वार्थ भुनाने लगते हैं. हम अंधविश्वासी भी हैं और थोड़े नासमझ भी क्योंकि हमें जो भी करने को कहा जाए हम बिना कहे सोचे समझे करने को तैयार रहते हैं. इससे फायदा किसी को नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है. यह धर्म है अज्ञानता धर्म के नाम पर मार–काट किसी भी सूरत में सही नहीं है, क्योंकि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. धर्म के नाम पर हम लोग कितनी आसानी से ठग लिए जाते हैं.

हममें से अधिकतर लोग पाप और पुण्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं. इसलिए बहुत सा धन, सोना चांदी मंदिरों में चढ़ा देते हैं. यहीं नहीं हम अपने फायदे और दिखावे के लिए भी दान करते हैं, लेकिन ऐसे दान का कोई फायदा नहीं. दान करना अच्छी बात है दान करना भी चाहिए. पर किसे और कहां यह हमारे लिए समझना जरूरी है. आज हमारे देश का सोना मंदिरों में जमा है. क्या भगवान को धन की जरूरत है. सच्ची पूजा है कर्म और सेवा. ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं. वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए दीन–दुखी लोगों की सेवा कर हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं. आज देश में गरीबी है, लोग भुखों मर रहे हैं. ऐसे में कितान अच्छा होता कि हम जिस धन को ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं उसे दीन–दुखियों की सेवा में लगाएं.

विकास कुमार *पाटनी, झुमरी तलैया*

बढ़ती महंगाई

महंगाई दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सरकार केवल वादों से लोगों को सांत्वना देती रहती है. महंगाई के इस दौर में खासकर पहले प्याज में ही आग लगी थी, लेकिन अब टमाटर में भी आग लग गई है धीरे–2 आलू भी इनकी राह पर चल पड़ा है. महंगे प्याज की मार से लोग अभी उबर भी नहीं पाये थे कि टमाटर 100 रुपये किलो के भाव से बिकने लगा. हरी सब्जियों का तो भाव पूछिए ही मत उनका भाव तो पहले से ही चढ़ा है. लोग आलू से ही काम चला रहे थे कि आलू भी इन्हीं के भाव चल पड़ा है. अगस्त में प्याज का भाव जब 70 के पार हो गया तो नाबार्ड के एक अध्यन में पता चला कि अप्रैल–मई में किसानों से केवल 8 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदे गए. व्यापारियों ने किसानो से सस्ते दामों पर प्याज खरीद कर अपने गोदामों में जमा कर लिए. ऐसे ही प्याज की दिखावे की कमी से व्यापारियों ने करोड़ों का वारा न्यारा किया. अब वह टमाटर और आलू का भी वहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानते हुए भी अनजान क्यों बनी है. सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है?

राकेश, *वाराणसी*

नेताओं का गिरता स्तर

नेताओं का स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है इसे राजनीति में दुर्भाग्य कहें या राजनीति में एक चलन चल पड़ा है. नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते–उछालते कब कीचड़ में चले जाते है उन्हें पता ही नहीं चलता. कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने ऐसी टिप्पणी की कोई समाचार चैनल और समाचार पत्रों ने प्रकाशित नहीं किया. मायावती के ऊपर सपा के नेताओं बेतुके बयान भी सामने आते रहते हैं, मायावती और बसपा भी पीछे नहीं है. कांग्रेस, जेडीयू के नेताओं ने तो इसमें सारे रिकार्ड तोड़ रहे हैं. हो सकता है नेताआ कों समाचार में बनने के लिए यह एक नया विचार हो.

अखिलेश, *गोरखपुर*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

ई–मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

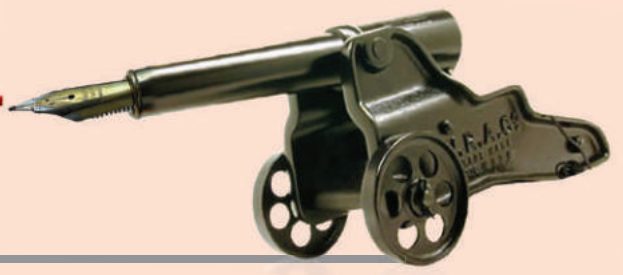

जनता के सामने कई बड़े ख़तरे पैदा हो रहे हैं

इस चुनाव में जनता या तो फुटबॉल बनने जा रही है या तो दर्शक. सड़क के किनारे खड़ा होकर कोई भी आदमी कुछ भी बेचने की कोशिश करे, डमरू बजाने लगे, अजीब वेश–भूषा बना ले, तो उसे उसे कुछ ही देर में पांच सौ या एक हज़ार दर्शक मिल ही जाते हैं. ठीक वैसा ही काम राजनीतिक दल अपने देश की जनता के साथ करने जा रहे हैं. अब तो वे सपने भी नहीं बेचते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान के लोगों को सपने बेचकर बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है. यहां पर तो लोग मुर्गे की लड़ाई दिखाकर भी बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं. दिल्ली की गद्दी के प्रमुख दावेदार हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी. दोनों ने मिलकर देश में चुनाव की लड़ाई को दो व्यक्तित्वों की लड़ाई में बदल दिया है. नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी. राहुल गांधी नौजवानों की आकर्षित करते हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के कपड़े कैसे हैं और राहुल गाधी के कपड़े कैसे हैं? नरेंद्र मोदी की बोलने की कला कैसी है और राहुल गांधी के बोलने की कला कैसी है? बस इन्हीं सवालों के इर्द–गिर्द यह चुनाव हो रहा है और इसमें जिन्हें मदद नहीं करनी चाहिए, वे आगे बढ़–बढ़ कर मदद कर रहे हैं. मेरा मतलब देश के मीडिया से है. लेकिन मीडिया को ही दोष क्यों दे? देश की जनता जब ख़ुद अपनी आखों पर पट्टी बांधने के लिए तैयार हो तो कोई उनकी पट्टी कैसे खोले? किसी ने ज़बदरस्ती पट्टी बांधी हो तो दूसरा पट्टी खोलने की कोशिश भी करे.

देश में महंगाई चरम सीमा पर है. भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क़दर बढ़ रहा है कि लोग अब उस पर बात ही नहीं करना चाहते. देश के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बेरोज़गारी को लेकर है. लेकिन नेताओं के लिए यह चिंता का विषय नहीं है. नेताओं के लिए तो यह भी चिंता का विषय नहीं है कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश में न तो सड़कें हैं, न बिजली है और सबसे बड़ी बात कि जीने का सबसे बड़ा साधन पानी भी नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार या सड़क, बिजली और पानी चिंता का विषय नहीं हैं. दोनों में से कोई भी यह नहीं बता रहा है कि इन समस्याओं का कोई समाधान उनके पास है या नहीं. गांवों में किसानों की ज़मीन उनके हाथों से निकलती जा रही है. हाल में एक क़ानून बनाया गया जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि किसानों की ज़मीनों की बिक्री पर थोड़ी–सी रोक लगेगी. लेकिन इस क़ानून में इतने लूप होल हैं जिनके चलते यह क़ानून किसानों से उनकी ज़मीन बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जाने से कितना रोक पाएगा, कहा नहीं जा सकता. अगर यह सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चिंता का विषय नहीं है, तब उनके ऊपर भारत की जनता क्यों ध्यान नहीं दे रही, यह भी समझ में नहीं आ रहा. चूंकि जनता ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए यह सवाल कभी भी हल होने की दिशा में बढ़ते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये सवाल, सवाल ही बने रह जाते हैं. कहा यह जा रहा है कि भारत में इस बार बड़ी संख्या में लगभग बीस करोड़ के आसपास नौजवान वोट डालेंगे. ये नौजवान भी इसी तमाशे के दर्शक बनते दिखाई दे रहे हैं. अगर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, अगर लोगों को महंगाई में इसी तरह से पिसना पड़ेगा, तो क्या हम मानें कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की वफ़ादारी ऐसे ही बनी रहेगी. अब सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र से विश्वास उठता है, तो उसकी जगह कौन आएगा? दो ही ताकते हैं, जो लोकतंत्र का स्थान लेती हैं. एक फासिस्ट ताक़तें और दूसरी अधिनायकवादी ताक़तें. फासिस्ट ताक़तें दुनिया की बहुत सारी जगहों पर नहीं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि तीसरी दुनिया के देशों की ज़मीन फासीवादी ताक़तों के पैदा होने के लिए काफ़ी उपजाऊ है. हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो फासिज्म पर भरोसा करते हैं और अफ़सोस की बात यह है कि सांप्रदायिकता का अगला क़दम फासिज्म होता है.

क्या यह मानें की भारत के सारे राजनीतिक दल लोकतांत्रिक विकास को आवश्यक नहीं मानते. दिल्ली में 30 अक्टूबर को गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों की बैठक हुई. यह बैठक हुई तो सांप्रदायिकता का विरोध करने के लिए लेकिन अख़बारों में माहौल बना कि यह तीसरे मोर्चे के बनने की शुरुआत है. वहां जो भाषण हुए, जिस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखीं, उसने कोई भी उत्साह नहीं पैदा किया और न ही यह बताया कि उनके सामने विकास का कोई एकीकृत कार्यक्रम है और चूंकि कार्यक्रम नहीं है, इसलिए यह मानना कि देश इनके पीछे चलेगा या ये इकठ्ठे हो पाएंगे, अभी बहुत साफ़ नहीं है. हालत यह है कि सर्वे आ रहे हैं और सर्वे भी स्पॉन्सर्ड सर्वे हैं. बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पीछे निहित विचार होते हैं और बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं जिनके पीछे पैसा होता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी सर्वे 160–170 से अधिक सीटें बीजेपी को देने को तैयार नही है और कांग्रेस 80 से 120 के बीच में झूल रही है. तब फिर बाक़ी सीटें कहां जाएंगी? यह बाक़ी सीटें जहां भी जाएंगी, एक ख़तरे की तरफ़ इशारा करती हैं. अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग कोई एक दल या कई दल स्पष्ट एजेंडा जनता के सामने नहीं रखते हैं, तो फिर जनता शायद इधर–उधर बिखरकर वोट दे और तब जो लोग जीतकर आएंगे वो लोकतंत्र की मंडी में एक नए तरह का बाज़ार सजा देंगे.

देश के सामने मौजूद इन ख़तरों को देखने का नज़रिया और महसूस करने की क्षमता देश की जनता में है. बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि देश की जनता कभी ग़लत फ़ैसले नहीं करती. लेकिन सड़क पर चलते-चलते दुर्घटना तो होती ही है न. कहीं यह दुर्घटना लोकतंत्र के रास्ते में चलते हुए न हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी. कोशिश करनी होगी कि मौजूदा बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था की जगह पर जनाभिमुख अर्थव्यवस्था लाने का दबाव बनाया जाए. राजनीति में कौन-सा दल यह करेगा पता नहीं, लेकिन अगर कोई दल बाज़ार आधारित अर्थवस्यवस्था की जगह पर हिंदुस्तान के लोगों के हाथों में रोज़गार, पेट में रोटी, पीने के लिए पानी और जीने के लिए दवाइयां मुहैया कराने का वादा करे तो शायद यह आज की विच-ारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है.

इसका मतलब देश की जनता के सामने कई बड़े ख़तरे पैदा हो रहे हैं. अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है या कांग्रेस को वोट देती है तो वही आर्थिक नीतियां लागू रहेंगी, जिन आर्थिक नीतियों के चलते देश इस जगह पर पहुंच गया है जहां देश के सामने न पानी है, न बिजली है और न सड़के हैं. बेरोज़गारी बढ़ रही है. ग़रीबी बढ़ रही है. महंगाई बढ़ रही है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही तरह की अर्थनीति में विश्वास करते हैं. भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के ऊपर यह आरोप है कि उसने इस अर्थनीति को जिसे बाज़ार आधारित अर्थनीति कह सकते हैं, उसे ठीक से लागू नहीं किया. बीजेपी का दावा है कि वह उसे ठीक से लागू करेगी. मतलब अगर पानी उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, तो अब बिल्कुल नहीं मिल पाएगा. बेरोज़गारी जितनी है उससे भी ज्यादा बढ़ेगी. महंगाई जितनी बढ़ी है, उससे भी ज्यादा बढ़ेगी. इसलिए मुझे यह लगता है कि इस अर्थव्यवस्था के लिए ख़िलाफ़ होने की बात जो लोग कर रहे हैं, वे सचमुच इसके ख़िलाफ़ हैं ही, यह बात स्पष्ट नहीं है. मेरा मानना है कि देश के सामने मौजूद इन ख़तरों को देखने का नज़रिया और महसूस करने की क्षमता देश की जनता में है. बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि देश की जनता कभी ग़लत फ़ैसले नहीं करती. हम भी यह मानते हैं कि देश की जनता कभी ग़लत फ़ैसले नहीं करती, लेकिन सड़क पर चलते–चलते दुर्घटना तो होती ही है न. कहीं यह दुर्घटना लोकतंत्र के रास्ते में चलते हुए न हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी. और इस बात की कोशिश लोगों को करनी होगी कि मौजूदा बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था की जगह पर जनाभिमुख अर्थव्यवस्था लाने का दबाव बनाया जाए. राजनीति में कौन–सा दल यह करेगा पता नहीं, लेकिन अगर कोई दल बाज़ार आधारित अर्थवस्यवस्था की जगह पर हिंदुस्तान के लोगों के हाथों में रोज़गार, पेट में रोटी, पीने के लिए पानी और जीने के लिए दवाइयां मुहैया कराने का वादा करे तो शायद यह आज की विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है. मज़े की बात यह है कि यह विचारधारा नहीं है, लेकिन जब यह चीज़े हैं ही नहीं, तब फिर किसी विचारधारा का मतलब ही क्या है. इसलिए मैं कह रहा हूं इन चीज़ों को ही विचारधारा मानकर अगर कोई वायदा करता है तो उस दल या ऐसे दलों को खड़ा करने का दबाव अगर कहीं खड़ा हो सकता है, तो जनता की तरफ़ से खड़ा हो सकता है. और जनता अगर चाहे तो यह दबाव बनाए बनाए नहीं तो फ़िलहाल जनता के सामने एक मात्र विकल्प अराजकता का है जिस विकल्प को लोग अपनाते जा रहे हैं.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

विरासत पर युद्ध

थॉमस जेफरसन क्रांति के एक प्रणेता थे या पाखंडी दास स्वामी? विंस्टन चर्चिल एक हीरो थे या नस्लवादी? अमेरिकी और ब्रिटिश लोग इस विषय पर हमेशा बहस करते रहते हैं. लेकिन इसके उलट भारतीय अपने हालिया इतिहास जैसे मुद्दों पर बहस करने के मामले में भी शर्म महसूस करते हैं. सत्ताधारी कांग्रेस, जिसके पास आर्थिक और गवर्नेंस के मुद्दे पर बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद परेशान है. पार्टी के सबसे मज़बूत पक्ष को मोदी ने हाल ही में चुनौती दी है. मोदी ने सरदार पटेल को अपना आदर्श बताया है.

कांग्रेस इस बात में विश्वास करती है कि देश का पूरा इतिहास पार्टी ने ही बनाया है. महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की गई, जबकि आज़ादी के बाद नेहरू–गांधी परिवार सत्ता में रहा. लेकिन एकदम से हाल के दिनों में पार्टी के नेता सरदार पटेल की प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं. दुख की बात यह कि ख़ुद के इतिहास के बारे में भी उनका जो ज्ञान है, वह काफ़ी कमज़ोर है. क्योंकि सरदार पटेल को उनके इतिहासकारों ने इतिहास से ही मिटा दिया है. पटेल को अब धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी बताया जा रहा है और संघ के दुश्मन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. लेकिन पटेल के समय के लोगों के लिए इतिहास थोड़ा अलग तरीक़े का है.

कांग्रेस में साल 1885 में स्थापना के बाद से ही प्रमुखता से हिंदू सदस्यों की बहुलता रही. और यह अपरिहार्य भी था, क्योंकि हिंदू संभ्रांत समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर नए व्यवसायों को अपनाया था. इस मामले में मुस्लिम पीछे छूट गए थे. गांधी जी ने ख़िलाफ़त आंदोलन के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की. चौरी चौरा की घटना के बाद जब उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया तो एक तरीक़े से इस फ़ैसले ने मुसलमानों को अलग खड़ा कर दिया.

उसके बाद कांग्रेस मुसलमानों को समर्थन नहीं हासिल कर पाई. मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट ने जिन्ना के सीट बंटवारे के निवेदन को ख़ारिज कर दिया, क्योंकि हिंदू महासभा इसके विरोध में थी. कांग्रेस ने 1937 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग से यूपी में गठबंधन करने का वादा किया. लेकिन जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया तो नेहरू वादे से मुकर गए. इसका परिणाम यह हुआ कि 1947 के संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस को एक भी मुस्लिम सीट नहीं मिली, जबकि उसके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे.

उस समय पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं में ज्यादातर हिंदू समुदाय के थे. नेहरू अकेले ऐसे धर्मनिरपेक्ष उदारवादी नेता थे जिनके पीछे कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमान और समाजवादी थे. इसके अलावा वे गांधी जी की प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद भी थे. उनके अलावा पटेल, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता कट्टर हिंदू परंपरावादी थे. माउंटबेटन ने सबसे पहले पटेल को ही समझाया था कि आख़िर बंटवारा महत्व क्यों रखता है? पटेल ने इसके लिए नेहरू के साथ बातचीत की. दरअसल पटेल पाकिस्तान के निर्माण के नेहरू से ज्यादा विरोधी थे. दोनों में उन भारतीय मुसलमानों की रक्षा को लेकर आपस में बहस हुई, जिनपर पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थी हमला कर रहे थे. कांग्रेस पार्टी जो हिंदू परंपरावादी थे उनका ऐसा मानना था कि संघ और पार्टी को मिल जाना चाहिए, लेकिन नेहरू इस बात के विरोधी थे. इस बीच नेहरू–पटेल झगड़े की वजह से सरकार के बीच में लगभग दरार आ गई थी. उन्होंने गांधी जी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी उसी दिन हत्या कर दी गई, जब वे दोनों का कलह निपटाने जा रहे थे.

इस घटना ने पटेल का हिलाकर रख दिया. गांधी जी सुरक्षा में ढील की वजह से गोडसे को उनके नजदीक तक पहुंच जाने के लिए पटेल पर आरोप लगाया गया. नेहरू उस समय प्रधानमंत्री तो थे लेकिन पार्टी पर उनका बहुत अधिक वर्चस्व नहीं था. टंडन, कृपलानी, पटेल और प्रसाद उस समय ज्यादा ताक़तवर थे. पटेल की दिसंबर 1950 में हुई मौत के बाद ही नेहरू के लिए टंडन को अध्यक्ष पद से हटा पाना मुमकिन हुआ.

पचास के दशक के दौरान जेपी को निष्प्रभावी कर दिया था. इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बिना पर उनको समर्थन देने का फ़ैसला किया कि नेहरू पार्टी में प्रगतिवादी सोच के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतिक्रियावादियों को निष्प्रभावी कर रहे हैं. पटेल जिन हिंदू परंपरावादी नेताओं के नेतृत्वकर्ता थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था. प्रसाद, टंडन और राजाजी जैसे नेताओं को हाशिये पर डाल दिया गया था. केवल नेहरू पार्टी के नेता रह गए थे और गांधी जी.

एकबार जब नेहरू ताक़त में आ गए तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को मज़बूती दी. प्रसाद फिर से बनाए गए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू इस बात पर राजी नहीं हुए क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत था. ये केएम मुंशी ही थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर फिर से बनाकर हिंदू परंपरा को पार्टी में क़ायम करने की कोशिश की. उसके बाद पार्टी में हिंदू पुनरुत्थान गुजरातियों के हाथ में चला गया. सरदार पटेल को भले ही दिल्ली में भुला दिया गया हो, लेकिन वे हमेशा एक गुजराती आदर्श बने रहे.

इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस को बांट दिया था. यह गुजरात ही था जिसने उनके ख़िलाफ़ नवनिर्माण आंदोलन के साथ 1974 में नेतृत्व किया. कांग्रेस से इंदिरा द्वारा निकाले गए मोरार जी देसाई जनता पार्टी के लीडर के रूप में उभरे, जिस पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया. अब यह कांग्रेसी पटेल को अपना नेता बताते हैं. अब पार्टी के लिए ऐसा करने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है.■

कांग्रेस इस बात में विश्वास करती है कि देश का पूरा इतिहास पार्टी ने ही बनाया है. महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की गई, जबकि आज़ादी के बाद नेहरू-गांधी परिवार सत्ता में रहा. लेकिन एकदम से हाल के दिनों में पार्टी के नेता सरदार पटेल की प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं. दुख की बात यह कि ख़ुद के इतिहास के बारे में भी उनका जो ज्ञान है, वह काफ़ी कमज़ोर है.

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

आम आदमी कमज़ोर नहीं है

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई के इस कॉलम के ज़रिए हम अपने पाठकों तक सूचना क़ानून से संबंधित जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अब तक हमने आपको इस क़ानून के बहुत सारे पहलुओं से अवगत करा दिया है. यह अच्छी बात है कि हमें पाठकों के पत्र लगातार मिल रहे हैं सुझाव, समस्या और अनुभव के रूप में. इस अंक में हम अपने कुछ पाठकों के पत्रों को शामिल कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं तो अपने अनुभव भी हमारे साथ बांटे हैं. बिहार से ओमप्रकाश ने डाक विभाग से संबंधित अपना अनुभव भेजा है. यह अनुभव दरअसल आरटीआई की सफलता की कहानी है कि कैसे 4 सालों बाद डाक विभाग को ब्याज सहित मूल रकम लौटानी पड़ी. यह सफलता एक आम आदमी मोहम्मद अली की भी है. वह भूल गए थे कि उनका दस हज़ार रुपया डाक विभाग की लापरवाही के चलते डूब चुका है, लेकिन आरटीआई की बदौलत 4 सालों बाद उन्हें उनका डूबा हुआ पैसा मिल गया. सवाल यह है कि जब मोहम्मद अली को अपना हक़ मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? ज़रूरत बस अपना हौसला बनाए रखने की है. आरटीआई की ताक़त पर भरोसा रखते हुए इसका इस्तेमाल करना है. हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी रिश्वत देने के बजाय आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे. यदि आप आरटीआई से संबंधित कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें. भविष्य में भी हम विभिन्न मुद्दों पर आरटीआई आवेदन के प्रारूप प्रकाशित करते रहेंगे. हमें आपके सुझावों एवं अनुभवों का इंतज़ार रहेगा.

पाठकों की राय और अनुभव

आरटीआई के लिए शहीद हुए लोगों पर एक लेख छापें

आपसे आग्रह है कि आरटीआई के लिए जो लोग शहीद हो गए, उनके बारे में एक लेख छापें. यानी स्वर्गीय शेट्टी एवं ललित मेहता जैसे लोग, जिन्हें आरटीआई की वजह से अपनी जान देनी पड़ी. मैं भी आरटीआई का एक कार्यकर्ता हूं और आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि आरटीआई आवेदकों की सुरक्षा के लिए कोई क़ानून बनाया जाए, नहीं तो लोग इसे इस्तेमाल करने से डरते रहेंगे. मैंने एक बिल्डर को आरटीआई के सहारे सबूत जुटाकर जेल की हवा खिलाई थी. अब उसी बिल्डर ने पुलिस में झूठी शिक़ायत करके मुझ पर मुक़दमा करा दिया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई वकीलों पर ख़र्च कर रहा हूं. मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे, जो आरटीआई के इस्तेमाल की वजह से परेशान किए जाते होंगे.

–राजेश मेहता, दिल्ली.

आपके इस सुझाव के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद. हम शीघ्र ही इस कॉलम में आरटीआई के लिए शहीद हुए लोगों पर लेख प्रकाशित करेंगे.

मूल रकम की ब्याज सहित वापसी

मुंगेर (बिहार) से अधिवक्ता ओमप्रकाश पोद्दार ने हमें सूचित किया है कि आरटीआई की मदद से एक शख्स को डाकघर से 4 सालों बाद उसकी मूल रकम ब्याज सहित वापस मिली. जमालपुर निवासी मोहम्मद अली ने अपने बचत खाते में 22 अगस्त 2006 को एलआईसी से मिला दस हज़ार रुपये का एक चेक जमा किया था, लेकिन यह रकम उनके खाते में दर्ज नहीं की गई. विभागीय लापरवाही की वजह से मोहम्मद अली को दस हजार रुपये का नुकसान हो गया. 2009 में वह ओमप्रकाश के संपर्क में आए और अपनी समस्या बताई. ओमप्रकाश ने आरटीआई क़ानून के तहत इस मामले में डाक अधीक्षक से जानकारी मांगी. आरटीआई के तहत चली इस प्रक्रिया के तहत दुमका डाक विभाग ने बताया कि सितंबर 2006 में ही निबंधित डाक से चेक क्लियरेंस की सूचना मुंगेर डाक विभाग को दी जा चुकी है. इसके बाद 21 फरवरी 2010 को प्रमंडलीय डाक अधीक्षक, मुंगेर ने सूचना क़ानून के तहत जानकारी दी कि ला–परवाह डाककर्मी के ख़िलाफ़ विभागीय जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मोहम्मद अली के खाते में वांछित रकम ब्याज सहित दर्ज कर दी गई ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

इस सप्ताह किसी से आर्थिक लेन देन से बचें अन्यथा बदनामी हो सकती है. परिवार में मतभेद उभर सकते हैं प्रतिक्रिया देने से बचें. दांपत्य जीवन में सुखमय रहेगा. लम्बी दूरी की यात्रा पर न जाएं. भाग्य आपका साथ देगा और कार्यस्थल पर पूर्ण सहयोग मिलेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

इस सप्ताह आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा. स्वास्थ्य का ध्यान दें. नौकरीपेशा वाले लोगों को शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन दांपत्य जीवन में परेशानी हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

इस सप्ताह आपके आय के नए श्रोत बनेंगे. सही फैसला करें नहीं तो धन की हानि हो सकती है. दांपत्य जीवन में तनाव न आने दें. शत्रुओं से सावधान रहें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. पारिवार में शुभ कार्य होने के योग हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

इस सप्ताह आलस्य से दूर रहें. आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकेंगे. व्यापारियों के लिए समय उथल-पथल वाला रहेगा. नौकरीपेशा वाले लोगों को तरक्की की खबर प्राप्त होगी. आपको आपके साथ कार्यरत लोगों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

इस सप्ताह आप भाग्यशाली रहेंगे. आपके कार्य करने के तरीकों भी बदलाव आएगा और बदलाव से आप अच्छा महसूस करेंगे. केवल अपनी रणनीति पर कार्य करने से पहले उसे उजागर न करें. आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आंख बंद कर भरोसा न करें, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

इस सप्ताह आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप कार्य से परेशान नहीं होंगे. व्यस्तता बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. भाग दौड़ रहेगी. परिवार के लोगों से सहायता प्राप्त होगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

इस सप्ताह आपके आय के स्रोत्र में वृद्धि होगी. आपके संपर्क उच्च प्रतिष्ठित लोगों से बनेगें और आपको फायदा होगा. शुभ कार्य होने की संभावना है. संपत्ति और वाहन खरीदने की संभावना है. सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

इस सप्ताह खर्च में वृद्धि होगी, जिसके कारण तनाव रहेगा. पूर्व लंबित कार्य संपन्न होगा. कार से यात्रा करने से बचें. पत्नी और संतान के स्वास्थ्य के कारण चिंता होगी. शत्रुओं से सावधान रहें. क्रोध से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा वाले लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

इस सप्ताह उन्नति से सम्बंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा. व्यय पर नियंत्रण रखें. परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने दें अन्यथा मन विचलित रहेगा. पैसे के लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा धोखा हो सकता है. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

इस सप्ताह क्रोध से बचें. आपको परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा . मानसिक तनाव से बचें. पूंजी निवेश करने से पहले सोच-विचार लें. भावुकता में आकर संपत्ति खरीदने से बचें. नौकरीपेशा और व्यापारियों दोनों अपने साथ कार्य करने वाले लोगों पर ध्यान रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

इस सप्ताह आपके प्रति लोगों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है. कर्ज से देने पहले विचार कर लें. नौकरी पेशा वाले लोग भाग्य से ज्यादा कर्म करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में रखें. कार्य करते रहें फल की चिंता न करें. आप अपनी प्रगति के बारे में किसी को न बताएं, जिससे नए शत्रु बनगें. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजना के अनुसार कार्य करें फायदा होगा.

ज़रा हट के

भारतवंशी ने खोजा जीवन का रहस्य

भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने खोज किया है कि 3.8 अरब वर्ष से अधिक समय पहले धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ. टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के प्रोफेसर और जीवाश्म विज्ञान संग्रहालय के क्यूरेटर, शंकर चटर्जी ने दावा किया है कि उल्काओं और धूमकेतुओं के टकराने से संभवत: ऐसे अवयव आए, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर जीवन योग्य वातावरण तैयार किया. चटर्जी ने कहा है कि लगभग चार अरब वर्ष पहले पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी के सतह पर नियमित तौर पर भारी उल्काओं और धूमकेतुओं की वर्षा होती रही, जिसके चलते विशाल गड्ढे बन गए. इन गड्ढों में न केवल पानी जमा हुआ और जीवन के लिए बुनियादी रासायनिक अवयव निर्मित हुए, बल्कि इसने प्रथम सामान्य जीवों के निर्माण के लिए रसायनों को पकाकर सांद्र बनाने हेतु उपयुक्त क्रुसिबल (शीशे का एक तरह का बरतन) का काम भी किया. ग्रीनलैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में पृथ्वी पर मौजूद प्राचीनतम जीवाश्म युक्त चट्टानों का परीक्षण करने के बाद चटर्जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये सब प्राचीन गड्ढों के अवशेष हो सकते हैं और वे स्थान भी, जहां जीवन का निर्माण गहरे, अंधेरे और गरम वातावरण में शुरू हुआ होगा. चटर्जी ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि कोई 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय यह एक बंजर ग्रह था, जो जीवों के रहने अनुकूल नहीं था. चटर्जी ने कहा है कि सूर्य के साथ पृथ्वी की घनिष्ठता ने यहां जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया. ■

युवक को डसने से सांप मरा

उत्तर प्रदेश के बहराइच में खेत में काम कर रहे युवक को सर्प ने डस लिया, लेकिन आप को जानकर हैरानी होगी कि सांप युवक को डसने के बाद मर गया. युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. यह मामला बहराइच के केशवापुर मुराव गांव का है. युवक खेत में धान की कटाई कर रहा था. इसी दौरान एक सांप ने उसे डस लिया. सांप काटने के बाद वह बेहोस हो गया, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने युवक के शरीर में जहर की पुष्टि की है. इस मामले में परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि चंद्रेश बचपन से ही कई तरह के नशे करता है. नशे के कारण उसके शरीर में जहर फैल गया है, जिसके चलते सर्प भी मर गया. चंद्रेश के शरीर में जहर होने की पुष्टि जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने भी की. जिला अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मलय श्रीवास्तव ने बताया कि सांप का विष ह्यूमो टॉक्सिक और न्यूरो टॉक्सिक दो तरह का होता है. युवक को नागिन के काटने की बात ग्रामीण बता रहे हैं और उसका जहर न्यूरो टॉक्सिक होता है. यह जहर नस के द्वारा दिमाग तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि अफीम, कोकीन ऐसे मादक द्रव्य हैं, जिनका नियमित सेवन करने वाले व्यक्ति के खून में ऑटोमेटिक जहर मिला होता है. ऐसे में हो सकता है, सांप ने जब युवक को डसा हो तो पर्याप्त मात्रा मात्रा में विष उसके शरीर के अंदर न गया हो. उन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरह सांप के जहर का असर मानव शरीर पर होता है, उसी तरह सांप पर भी रिएक्शन हो सकता है. ■

बैलों से कुचलवाने की प्रथा

मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंधविश्वास के नाम पर लोगों का जान पर दांव लगाने की परंपरा अभी तक चली आ रही है. इस बार भी दर्जनों लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से नहीं चुके. पुरानी मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर लोग बैलों के पैरों तले लेटकर लोग अपने आराध्य देव को खुश करने की कोशिश करते हैं. लोगों के मुताबिक पहले वो भगवान शिव की पूजा करते हैं फिर सड़क पर लेट जाते हैं इसके बाद कई बैल इनके ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाते हैं. मंदिर के पुजारी का कहना है कि लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस प्रथा का पालन करते हैं, ये प्रथा काफी सालों से चल रही है. प्रशासन भी लोगों की आस्था के सामने लाचार ही नजर आता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

मिलती-जुलती है इंसान और चूहे की सोच

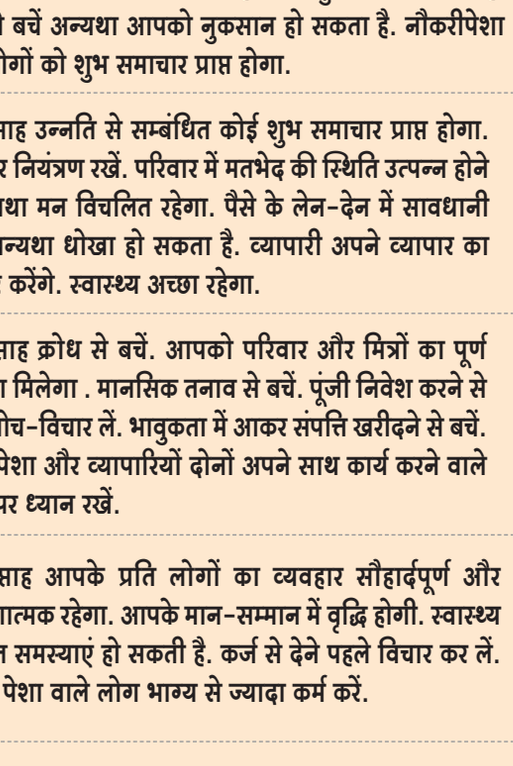

अभी हाल में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि इंसान और चूहे किसी प्रकार की गलती करने के बाद एक जैसे सोचते हैं. इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि ये दोनों ही अपने अनुभवों से सीखते हैं. इस रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट्स की टीम में एक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है. रिसर्चरों ने पाया कि इंसान और चूहे के दिमाग में गलती होने की स्थिति में एक सा बदलाव होता है. इस दशा में वे दिमागी न्यूरॉन्स को संतुलित करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते है. इस खोज की वजह से चूहे के दिमागी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इंसान को होने वाली मानसिक बीमारियों की दशा में अहम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि डिप्रेशन, पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया और दूसरी मानसिक बीमारियों के इलाज में इस रिसर्च की वजह से मदद मिल सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा की दुहाई देता रहा है. भारत ने जिन देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर सख्त विरोध दर्ज कराया, उसमें सबसे प्रमुख श्रीलंका है. यह भारत की मानवाधिकारों को लेकर चिंता ही थी कि उसने अपनी नीति बदली और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका में युद्ध के उपरांत सुलह एवं जवाबदेही के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.

मानवाधिकार हनन के शिकंजे में विश्व

आज पूरा विश्व ही मानवाधिकार उल्लंघन की गिरफ्त में है. कभी ड्रोन हमला तो कभी रॉकेट लॉन्चर, तो कभी विमान हमला मानवाधिकारों की हत्या का ज़रिया बनते रहे हैं और इन सब के बीच जमकर रक्तपात होता है, जिसमें निरीह नागरिक ही मारे जाते हैं. आख़िर कैसे थमेगा मानवाधिकारों का उल्लंघन.

राजीव रंजन

मानवाधिकारों का उल्लंघन एक सार्वभौमिक समस्या बन गई है. विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता. विश्व के लगभग सभी देशों में जातिभेद, घरेलू हिंसा, बालविवाह, दहेज हत्या, ऑनर किलिंग, महिला शिशु और भ्रूणहत्या जैसे अपराध मानवाधिकारों की तिलांजलि की कहानी बयां करते हैं. ये बात और है कि विश्व के लगभग हर देश अपने यहां होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चुप्पी साध लेते हैं, बल्कि ये देश तो साफतौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन से इंकार करते हैं. भारत भी इससे अछूता नहीं है. हालांकि भारत मानवाधिकारों की हिफाजत के प्रमुख पैरोकारों में से एक है. यह भारत ही है कि वह मानवाधिकारों को समर्थन देने को लेकर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह करता रहा है. यह एक साहसिक कदम है, जिससे मानवाधिकारों की दयनीय स्थिति में काफी सुधार किया जा सकता है.

भारत शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा की दुहाई देता रहा है. भारत ने जिन देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर सख्त विरोध दर्ज कराया, उसमें सबसे प्रमुख श्रीलंका है. यह भारत की मानवाधिकारों को लेकर चिंता ही थी कि उसने अपनी नीति बदली और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका में युद्ध के उपरांत सुलह एवं जवाबदेही के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. सीरिया के मामले में भी उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जो वहां बढ़ती हिंसा से संबद्ध थे. भारत ने अमेरिका, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लीबिया, पाकिस्तान, चीन सहित एशिया, यूरोप के अन्य महादेशों में हो रहे अविरल मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर सीधा विरोध दर्ज कराया. भारत के इस विरोध से काफी हद तक भारतीय आर्थिक हित भी प्रभावित हुए, लेकिन भारत ने इंसानियत के खून को रोकने के लिए छोट-बड़े नफा-नुकसान की कभी परवाह नहीं की. आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि कौन-कौन से देश अपने टुच्चे स्वार्थों के कारण इंसानियत का कत्ल कर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं.

सज़ा ही काफ़ी नहीं

भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई. सवाल यह उठता है कि क्या मौत की सज़ा ही इसका जवाब था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इन चार लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने से एक संक्षिप्त अवधि का बदला के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा.

भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में तेजी आई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2012 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुल 205 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2011 में दर्ज 72 मामलों और 2010 में दर्ज 37 मामलों से बहुत अधिक हैं. बिहार हो या गुजरात, दिल्ली हो या असम, हर जगह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मानवाधिकार के मामले सामने आ रहे हैं. इसके अलावे कश्मीर का मामला अलग है, जहां

मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चिंता जताते हुए यूरोपीय संसद का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को इस विवाद को हल करने के लिए बातचीत का सहारा लेना चाहिए. इसके लिए भारत और पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया गया है.

मानवाधिकारों की बलि लेती कश्मीर समस्या

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बारे में कहा गया है कि वहां लोगों को मूलभूत अधिकार ही उपलब्ध नहीं हैं. कहा जाता है कि यहां महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को समुचित अधिकार हासिल नहीं हैं. पिछले साठ सालों से कश्मीर समस्या के कारण मानवाधिकारों की बलि चढ़ाई जाती रही है. इस दौरान क़रीब एक करोड़ 34 लाख कश्मीरियों का दुख-दर्द अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रहा है.

अमेरिका का दामन सबसे काला

लम्बे अरसे से अमेरिका खुद को अन्य देशों से ऊपर समझता आया है और हर साल देशों की मानवाधिकार स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है और अन्य देशों की आलोचना करता है और उन पर कलंक लगाता है, किन्तु वह अपने देश में मानवाधिकार की गंभीर समस्याओं की ओर आंखें मूंदे रखता है. सच मायने में देखा जाए तो अमेरिका में बहुत से पहलुओं की मानवाधिकार स्थिति बेहद खस्ता है, जो विश्व में सबसे गंभीर है. रंगभेद, कैदियों को यातना, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार बड़े पैमाने पर अमेरिका में होता है. वहां नागरिक अधिकारों की स्थिति भी ठीक नहीं है. खासतौर पर जितना बढ़-चढ़ कर वह बताता है. मानवाधिकार पर दोहरा मापदंड अपनाने की अमरीका की हरकत और मिथ्या स्वरूप विश्व के अनेक देशों के विरोध और आलोचना का सामना करता रहा है, फिर भी वह हर साल देशों की मानवाधिकार स्थिति की रिपोर्ट जारी करने से नहीं थकता. अमेरिका भले ही दूसरे को नसीहत देता फिरता हो, लेकिन सत्य यह है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अमेरिका का दामन सबसे काला है. यह वही अमेरिका है, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए पूरे विश्व में घूम-घूम कर आक्रमण करता है. विकीलीक्स ने गोपनीय दस्तावेजों के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका ने बगैर पुख्ता सबूत के कई वर्षों तक गुआंतनामो बे में लोगों को कैद करके रखा, जबकि आगे चलकर गंभीर खतरे पैदा करने वाले लोगों को रिहा कर दिया गया. इतना ही नहीं, आतंकवादियों से संपर्क नहीं रखने के बावजूद भी सैकड़ों लोगों को बिना सुनवाई के कैद में रखा गया. अफगानिस्तान के एक गरीब किसान को बगैर सुनवाई के दो साल तक कैद में रखा गया, जबकि आतंकवादियों के साथ उसका किसी तरह का संबंध नहीं था. तो ये है अमेरिका और उसकी दोगली नीतियां, जो मानवाधिकार को मुंह चिढ़ाती फिर रही हैं.

कट्टरपंथ चरम पर

अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर कट्टरपंथ चरम पर है. उत्तर कोरिया की स्थिति इतनी बदतर है कि कट्टरपंथी सरकार द्वारा मानवाधिकारों के हनन की जांच करने वाले संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग के प्रमुख भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए. इस देश में श्रमिक शिविरों में रहने वाले लोगों की दास्तां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं. कम्बोडिया में भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लोगों को दुखी कर देते हैं. मानवाधिकार टीम की रिपोर्ट में सीरिया में बंदूकों और मोर्टार जैसे पारंपरिक हथियारों के हमले में सर्वाधिक लोगों की मौत होने की बात कही गई है. मरने वालों में बच्चों और महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है.

पाकिस्तान में स्थिति बदतर

पाकिस्तान में मुशर्रफ़ के सत्ता से हटने के बाद ज़रदारी-सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों के बावजूद मानवाधिकारों की स्थिति ख़राब बनी रही. देश के उत्तर-पश्चिम में सैनिक कार्रवाइयों में 1150 हत्याओं, वहां उग्रवादियों के हमलों में 825 ग़ैरसैनिकों के मारे जाने, और आत्मघाती बमविस्फोटों में 970 से अधिक मौतों का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा, उग्रवादियों से जारी संघर्ष में लगभग दो लाख लोगों के विस्थापित होने का ब्यौरा दिया गया है. नेपाल में माओवादी और जातिमूलक संगठनों द्वारा मानवाधिकारों के हनन की बात पूरी दुनिया को पता है. अब बात बांग्लादेश की करें तो इस सत्य को दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में सुरक्षाबलों द्वारा आम नागरिकों पर किस तरह के सितम ढाए जाते हैं और सरकार चुपचाप मानवाधिकारों की हत्या होते देखती रहती है.

चीन में मानवाधिकार उल्लंघन

विश्व समुदाय यह मानता है कि तिब्बतियों की धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत चूंकि बिल्कुल अलग है, इसलिए वह जो मांग कर रहे हैं, वह जायज है. चीन इसे अपना अभिन्न अंग कहकर तिब्बत आंदोलन को खारिज करता रहा है. तिब्बत में जिस तरह से चीन की सेना वहां के निवासियों से सलूक करती है, वह मानवाधिकार का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है. हद तो तब हो जाती है, जब चीन की ज्यादतियों पर प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को चीन अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाता है.

भ्रष्टाचार बड़ी बाधा

अब इन देशों में तेजी से फैल रहे भ्रष्टाचार की बात करें तो यह झकझोरने वाला तथ्य होगा कि भ्रष्टाचार मानवाधिकर को सुनिश्चित करने की राह में एक बड़ी बाधा है. हर वर्ष भ्रष्टाचार की वजह से जितने धन की चोरी होती है, उससे दुनिया भर के ऐसे लोगों को 80 बार खाना खिलाया जा सकता है, जिनके पास अपना पेट भरने के लिए दो जून की रोटी नसीब नहीं होती है. यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? हर दिन लगभग 87 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है. इनमें भारी संख्या बच्चों की है. भ्रष्टाचार की वजह से ऐसे भोजन के लिए उनके मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और कुछ मामलों में तो जीवन अधिकार ही संकट में पड़ जाता है. दुनिया भर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की परियोजनाओं का लगभग 40 प्रतिशत धन रिश्वतखोरी और चोरी की भेंट चढ़ जाता है. यह मानवाधिकार के उल्लंघन का नायाब उदारहण है.

क्या करें

हर देश को चाहिए कि वे अपने यहां प्राथमिक, मध्य और उच्च शिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार से संबंधित पढ़ाई को लागू करे. साथ ही लोक सेवाओं और अन्य केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जाति आधारित भेदभाव से निजात मिल सके. यह सच है कि जाति व्यवस्था मानव जाति की सोच को संकुचित कर देती है. इसलिए जाति व्यवस्था की मानव विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जातीय निष्ठा, जातीय पूवार्ग्रह और जातीय बैर भाव की संविधान विरोधी प्रकृति पर जोर देकर सभी स्तरों पर प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मानवाधिकार शिक्षा शुरू की जानी चाहिए. इससे समाज में फैली बुरी धारणाओं से कुछ हद तक निजात तो मिलेगी और लोगो में एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा मिलेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

साई

साई की भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है. बाबा अपने भक्तों के सदैव समीप रहते हैं. वे किसी न किसी रुप में भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं

एक बार...

साई सदा भक्तों के समीप रहते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

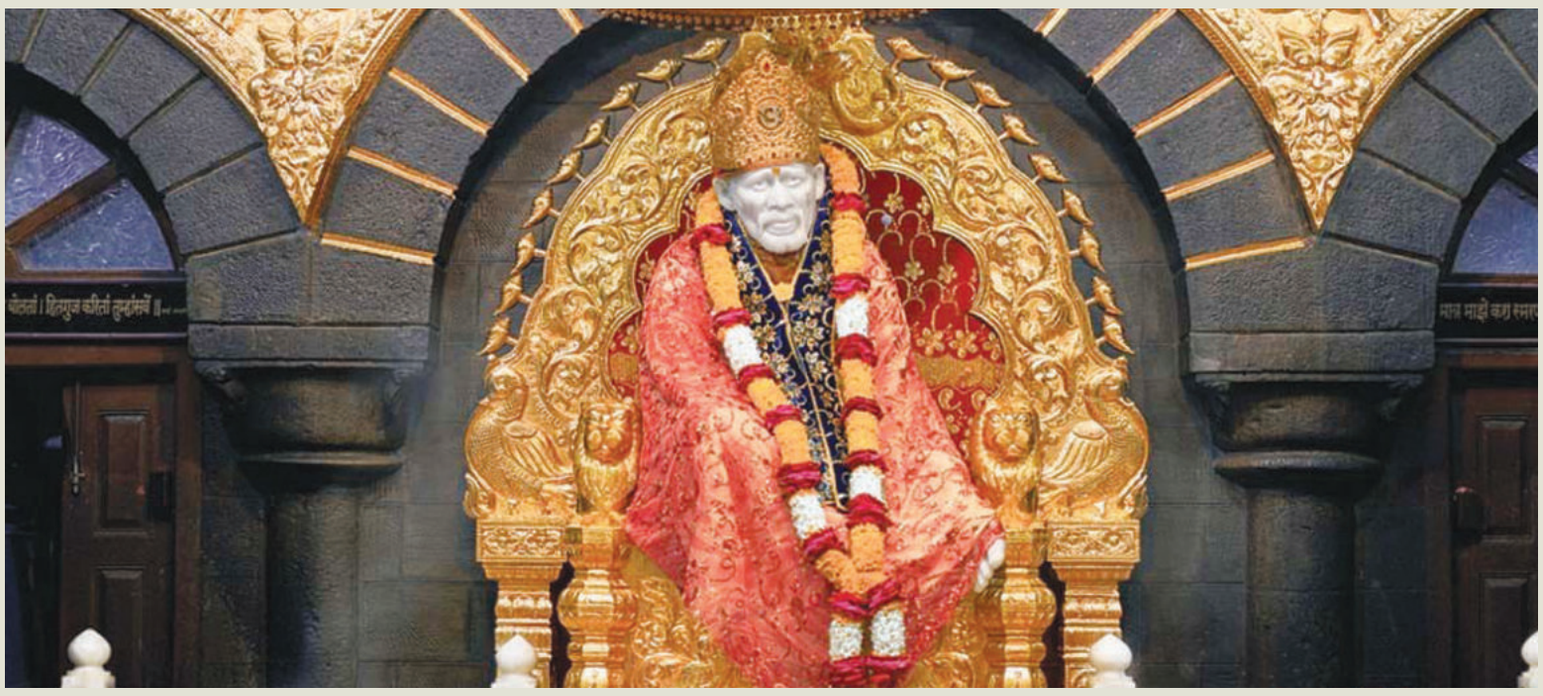

साई का चरण धन्य है और उनका स्मरण कितना सुखदायी है. साई के भयविनाशक स्वरुप का दर्शन भी धन्य है. यद्यपि अब हमें साई सगुण स्वरुप का दर्शन नहीं हो सकता. साई एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता की तरह हृदय से लगाते हैं. साई भक्त नहीं जानते कि उनका निवास कहां है, लेकिन साई इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते है, जिसके परिणामस्वरूप भासित होने लगता है कि साई का अभय हस्त उनके सिर पर है और यह साई की ही कृपा–दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है. अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन साई केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबारकर उनकी रक्षा करते हैं. दिखाई न देते हुए भी साई ही तो सब न्याय कर रहे हैं. फिर भी साई ऐसा अभिनय करते हैं, जैसे उनसे साई का कोई सम्बन्ध ही न हो. कोई भी साई की संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका. इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से साई चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र साई का ही नाम स्मरण करते रहें.

साई अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानन्द की प्राप्ति करा दिया करते हैं. केवल साई मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यन्त सुगम पथ है. इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी. तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना. इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है. इस भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है. यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, लेकिन वे तो किसी न किसी रुप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं.

एक बार जब बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा. उनमें से दो बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया. बाबा ने जाकर प्रेम–से उनके शरीर पर अपना हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपये में खरीद लिया. बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3–4 रुपये से अधिक न था और वे दो बकरे अधिक से अधिक आठ रुपये में प्राप्त हो सकते थे.

अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन साई केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबारकर उनकी रक्षा करते हैं. दिखाई न देते हुए भी साई ही तो सब न्याय कर रहे हैं. फिर भी साई ऐसा अभिनय करते हैं, जैसे उनसे साई का कोई सम्बन्ध ही न हो. कोई भी साई की संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका. इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से साई की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र साई का ही नाम स्मरण करते रहें.

उन्होंने बाबा को कोसना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन बाबा शान्त बैठे रहे. जब शामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा कोई घर या स्त्री तो है नही, जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखना है. फिर उन्होंने चार सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई. जब उन्हें खिला–पिला चुके तो उन्होंने पुनः उनके मालिक को बकरे लौटा दिए. तत्पश्चात ही उन्होंने उन बकरों के पूर्वजन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई .शामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूं. लेकिन ऐसा नहीं, इनकी कथा सुनो. गत जन्म में ये दोनों मनुष्य थे और सौभाग्य से मेरे निकट संपर्क में थे और मेरे पास बैठते थे. ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए. बड़ा भाई आलसी था, किन्तु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा. इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय सम्बन्ध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे. बड़े भाई ने अनेक प्रत्यन किए, लेकिन वह छोटे भाई की हत्या में असफल रहा. तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए. एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया. तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरुप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई.

फिर अपने कर्मों के अनुसार इन दोनों को अगले जन्म बकरे की योनि को प्राप्त हुए. जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई. इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने–पिलाने तथा सुख देने का विचार किया. यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए, जो तुम्हें मंहगे प्रतीत हुए हैं. तुम लोगों को यह लेन–देन अच्छा नहीं लगा, इसलिये मैंने उन बकरों को गड़ेरिये को वापस कर दिया है. सचमुच बकरे जैसे सामान्य प्राणियों के लिये भी बाबा को बेहद प्रेम था. इसलिए साई सबको एक समान प्रेम करते थे.■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

भावनाएं तूफान बन जाती हैं

डॉ. अभय बंग

मेरे मन की गाड़ी कैसे चलती है? बाहर से तो मन नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरा व्यवहार, कृति, दिखाई देते हैं. इस कृति के बनाने का काम सहसा भावनाएं करती हैं. मैं गुस्से से चिल्लाता हूं. इस प्रकार चिल्लाने से पहले मेरे मन में क्रोध आ चुका होता है. क्रोध की यह भावना अथवा विकार या पंतजलि के शब्दों में चित्तवृत्ति, शरीर की संवदेनाओं के रूप में अनुभव की जा सकती है. कनपटियां गरम होना, सांस तेजी से चलना, सारे शरीर में कंपकंपी, सिर ठनकना इत्यादि शारीरिक प्रतिक्रियाओं से क्रोध की भावना अनुभव की जा सकती है. पहचानी जा सकती है, लेकिन क्रोध की भावना कैसे उत्पन्न होती है? एक–एक क्षण पीछे लौटते हुए घटना के मूल तक जाने पर हम पाते हैं कि क्रोध के आवेग के पीछे एक छोटी सी चिनगारी कारणीभूत होती है. यह चिनगारी होती है मन में कौंधा हुआ एक विचार; अथवा मानसशास्त्र की भाषा में कहें, तो स्वयं से बातचीत अर्थात सेल्फ टॉक. जब कोई व्यक्ति मेरे मन के विरुद्ध आचरण करता है, तब उसके व्यवहार से सीधे मेरा क्रोध सहसा नहीं जाग उठता. उसके व्यवहार से मेरे मन में कोई वाक्य अथवा वाक्यांश उभरता है, किसी स्वगत कथन की तरह–यह मनुष्य मुझे इतना तुच्छ समझता है? यह वाक्य चिनगारी का काम करता है. मन में बारूद भरा हुआ होता ही है.

इस वाक्य से (अथवा कभी–कभी मन में उभरने वाली एकाध स्मृति अथवा दृश्यप्रतिमा से) यह बारूद सुलग उठता है एवं मेरे क्रोध का विस्फोट चीखने–चिल्लाने के रूप में लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इस विस्फोट के होने से पहले इतनी सारी घटनाओं की श्रृंखला एक क्षण में मेरे मन में घटित हुई होती हैं.

बाह्य घटना–मन में विचार–भावना/वृत्ति–बाह्य कृति

इस श्रृंखला के बीच की दो कड़ियां–मन के विचार एवं भावना अथवा वृत्ति–इन्हें महत्वपूर्ण मानकर, योग एवं मानसशास्त्र में इन्हें बदलने पर, नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है. यह सब किस प्रकार हो सकता है इसे समझने का मैं प्रयत्न करने लगा. पंतजलि ने कहा–योग यानी चित्तवृत्तियों का निरोध. मन में जो वृत्तियां अथवा भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उभरती हैं, उनसे मुक्ति अर्थात योग, लेकिन यह मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए? भावनाओं को दबाकर, उनका दमन करके यह संभव नहीं है. ऐसा करने से तो मन में और अधिक तनाव और दबाव का निर्माण होगा और कभी–न–कभी उसका विस्फोट होगा ही. फिर यह मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए?

भावनाओं के उद्वेग का अनुभव हमे शरीर की संवेदनाओं के रूप में होता है. क्रोध, भय, कामभावना–इन सबके साथ शरीर पर तदनुरूप प्रतिक्रियाएं उभरती हैं. ये प्रतिक्रियाएं अतिशय प्रामाणिक होती हैं. कभी–कभी मन की भावनाओं के दब जाने के कारण उनके सच्चे स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते. क्रोध बुरा माना जाता है. अतः मैं नहीं मानना चाहता कि मुझे क्रोध आया. मन को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन शरीर से उठने वाली संवेदनाएं बड़ी इमानदारी से मन का हाल सामने रख देती हैं. सेन्सिटिविटी ट्रेनिंग, नामक एक अमेरिकन पद्धति में अपनी

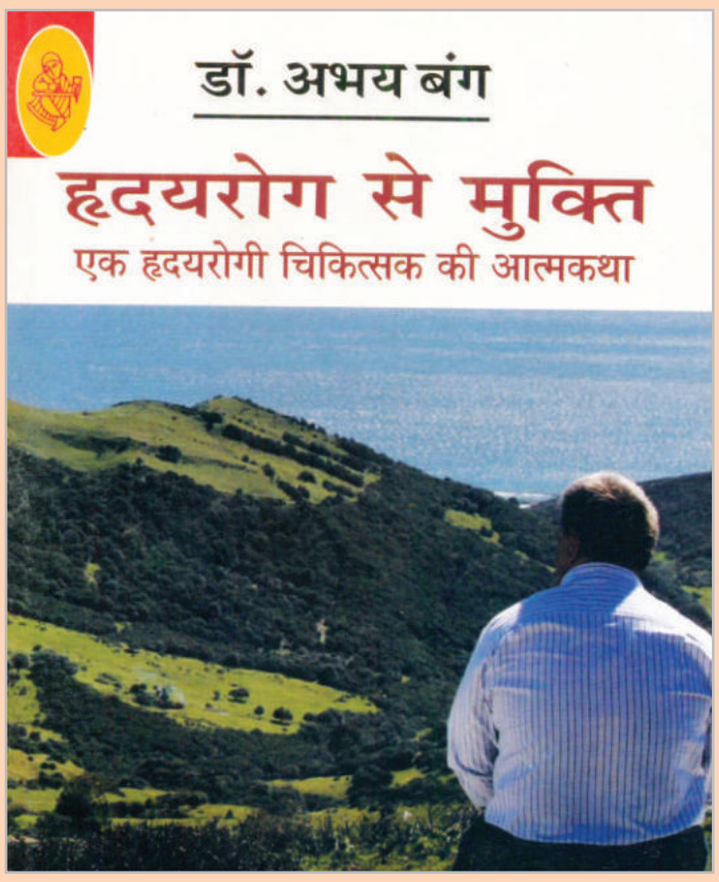

असली भावनाओं को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है. कुछ वर्ष पूर्व इस प्रशिक्षण के तीन सत्रों में मैंने भाग लिया था. यदि हम अपनी शारीरिक संवेदनाओं एवं मन में उठने वाले विचारों की ओर बारीकी से ध्यान दें, तो मन की असलियत सामने आ जाती है. मान लीजिए की एक घटना घटने पर मुझे डर लगता है, लेकिन डरना कमजोरी की निशानी माना जाता है, अतः मै स्वयं भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन पेट में पढ़ने वाला गड्ढा और त्वचा पर उभरी पसीने की बूंदें मन की असलियत जाहिर कर ही देती हैं. मन की भावनाएं तूफान बन जाती हैं और उनके कारण घातक आवेग और कृति घट जाते हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिले?

मैंने दोबारा विपश्यना शिविर में भाग लिया. इस बार पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी लगा. कुछ नए अर्थ मिले–

मन=(विचार)+(प्रतिक्रिया)

=(शब्द, वाक्य, प्रतिमा)+(सांस, कंपकंपी, धड़कन आदि संवेदनाएं)

मन का इस प्रकार से विश्लेषण करने से एवं उसे ध्यानपूर्वक देखने से मन को समझ लेना संभव हो जाता है. शरीर से उठने वाली संवेदनाओं को अनुभव करने का, उन्हें देखने का अभ्यास विपश्यना में करवाते हैं. यह एक प्रकार से सेन्सिटिविटी ट्रेनिंग ही हुई. अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाएं (रोमाच, कंपकंपी, थरथराहट, गर्मी, पसीना) एवं सांस में होने वाले परिवर्तनों के रूप में हम भावना अथवा चित्तवृत्ति का अनुभव करते हैं. उन्हें दबाना नहीं, उलटे संवेदनशील होकर उन्हें तुरन्त देखना है, लेकिन उन्हें केवल देखना उनमें उलझना नहीं. उन्हें बढ़ने अथवा स्नोबॉल नहीं होने देना है. उनका मन से जुड़ा हुआ रिश्ता तोड़कर उन्हें सिर्फ देखते रहना है. ऐसा करने से संवेदनाओं के साथ निर्मित होने वाली भावना के आवेग व उसके परिणाम–स्वरूप होने वाली क्रिया थमेगी.

भावना अथवा संवेदना का निर्माण होने के क्षणांश पहले मन में स्वगत (सेल्फ टॉक) उभरता है. यही इस वृत्ति का मूल है. क्षण भर के लिए उठने वाले इस वाक्य के प्रति हम जाग्रत नहीं होते हैं. तकरीबन अचेतन के स्तर पर ही वह घटित होता है. इसी कारण वाक्य अथवा दृश्य के मन में उठते ही उसकी प्रतिक्रिया कब हो जाती है, यह हम सब समझ नहीं पाते. ध्यान के अभ्यास में, फिर वह चाहे विपश्यना का आनापन हो या कि योगाशास्त्र का ध्यान हो–इसी अर्ध–अचेतन स्तर पर उभरने वाले विचारों को चेतन स्तर पर जागरूकता से पहचानने का प्रशिक्षण होता है. ध्यान का अभ्यास अर्थात अचेतन के प्रति संवेदनक्षम बनकर उसे जाग्रत रूप से पहचानना वाह!

मन में आए विचार को. सेल्फ टॉक को यदि मैंने दबाया नहीं. उलटे समझते–बूझते हुए उसे तुरन्त पहचान लिया तो, उस वाक्य के कारण उठने वाली आगे की प्रतिक्रियाएं रुक जाएंगी. वह वाक्य आएगा और चला जाएगा. मैं तटस्थ ही रहूंगा.

बड़ा मजा है मन की सेल्फ टॉक और शरीर से उठने वाली भावनाओं की प्रतिक्रिया (संवेदना)–इन दोनों प्रकार की लहरों में न डूबते हुए एक बार अगर तटस्थापूर्वक साक्षी भाव से देखना सीख लिया, तो उनकी विनाशकारी तूफानी शक्ति से मुक्ति मिल जाती है. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

घंटी का महत्व

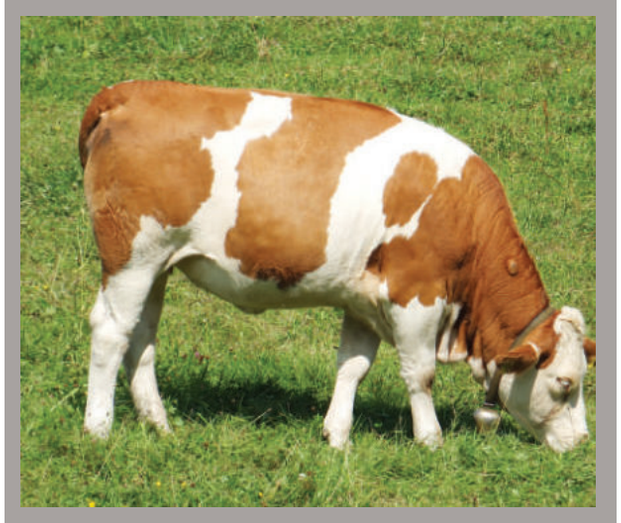

रामदास एक ग्वाले का बेटा था. रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता. हर गाय के गले में एक–एक घंटी बंधी थी. जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी.

एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था. वह उस गाय को देखकर रामदास के पास आया, यह घंटी बड़ी प्यारी है. क्या कीमत है इसकी ?

बीस रुपये. रामदास ने उत्तर दिया.

बस, सिर्फ बीस रुपये. मैं तुम्हें इस घंटी के चालीस रुपये दे सकता हूं.

सुनकर रामदास प्रसन्न हो उठा. झट से उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए. अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी. घंटी की टुनक से उसे अन्दाजा हो जाया करता था. अतः अब इसका अन्दाजा लगाना रामदास के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहां चर रही है. जब चरते–चरते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया. वह गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा.

तभी रामदास ने उसे देखा. वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई. उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वह अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देकर ठग ले जाएगा.

पिता ने, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है. पहले वह हमें प्रसन्नता देता है, फिर दुःख अतः हमें पहले ही से उसका सुख नहीं उठाना चाहिए.

शिक्षा–लालच में आकर कोई कार्य न करें

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

स्मृति

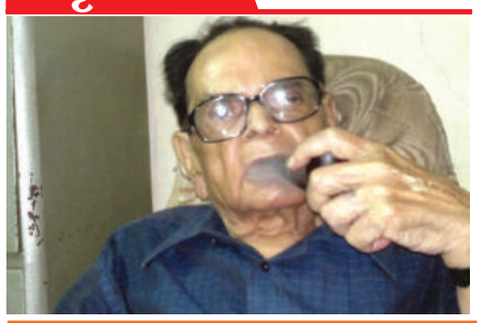

> राजेन्द्र यादव ने दलित विमर्श के माध्यम से जिस तरह से समकालीन हिंदी साहित्य में हस्तक्षेप किया, उसका मूल्यांकन होना भी शेष है. यादव जी के स्त्री विमर्श पर भी देह विमर्श का आरोप लगा. मुझे लगता है कि यादव जी का स्त्री विमर्श जर्मन ग्रीयर और सिमोन द बुआ के स्त्री विमर्श के बीच का रूप था, जहां वो परिवार के विघटन और यौन स्वच्छंदता के अलावा आपसी समझदारी की बात भी करते चलते हैं.

हम न मरैं मरिहै संसारा

अनंत विजय

एक साहित्यकार थे राजेन्द्र यादव. बेहद जीवंत और ज़िंदादिल. 28 सितंबर की देर रात वो है से थे हो गए. जिनकी ज़िंदादिली से हिंदी साहित्य गुलज़ार रहा करता था, जिनके ठहाकों की गूंज हिंदी जगत में लगभग छह सात दशक तक गूंजती रही थी, जिनकी प्रेरणा से सैकड़ों लेखक तैयार हुए, जिनके विचारों ने लंबे समय तक हिंदी जगत को झकझोरा, जिनकी लेखनी ने सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिन्होंने अट्ठाइस साल तक बगैर किसी संस्थागत पूंजी के हंस पत्रिका का निर्बाध संपादन किया, जिन्होंने हंस के मंच का उपयोग सामाजिक आंदोलन को उभारने में किया, जिन्होंने अपने विचारों से दलित साहित्य को हिंदी साहित्य के केंद्र में ला दिया, जिन्होंने हंस के माध्यम से हिंदी में स्त्री विमर्श को एक नई धार दी, जिन्होंने साठ के दशक में हिंदी कहानी को मनोरंजन के चौखटे बाहर निकाल कर हिंदी साहित्य को चौंकाया, जिनमें चौरासी साल की उम्र के बावजूद किशोरों जैसी चपलता और उम्र के इस पड़ाव पर किसी भी जवान से ज्यादा रोमांटिक. यह सूची बहुत लंबी हो सकती है. लेकिन अब ये सारी बातें इतिहास हो गईं. हिंदी साहित्य के सबसे लोकतांत्रिक लेखक राजेन्द्र यादव के निधन के बाद उनके ठहाके को अब सिर्फ़ याद किया जा सकता है, उनके पुराने संपादकीयों को पढ़कर अब सिर्फ़ उनका मूल्यांकन किया जा सकता है. उनका किशोरोचित स्वभाव और रोमांटिक व्यक्तित्व अब कहानियों में याद किए जाएंगे. लेकिन यादव जी बहुत दृढ़ता से कहते थे कि–अतीत मेरे लिए कभी पलायन, प्रस्थान की शरणस्थली नहीं रहा. वे दिन कितने सुंदर थे...काश वही अतीत हमारा भविष्य भी होता– की आकांक्षा व्यक्ति को स्मृति–जीवी निठल्ला बनाती है. लेकिन साहित्य में तो अतीत को ही कसौटी पर कस कर लेखक का मूल्यांकन करने की परंपरा रही है. सो यादव जी के साथ भी यह होना तय है. उनके निधन के बाद हिंदी जगत को उनके योगदान से लेकर उनकी रचनात्मकता को कसौटी पर कसा जाना शेष, लेकिन तय है. राजेन्द्र यादव की रचनात्मकता के अलावा उनके व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन भी हमारे युग के आलोचकों के लिए बड़ी चुनौती है. दरअसल, उनके व्यक्तित्व के बिना उनकी रचनात्मकता का मूल्यांकन अधूरा सा लगेगा. उनकी पत्नी और मशहूर कथाकार मन्नू भंडारी ने अक्तूबर 1964 में औरों के बहाने में लिखा था– मैं आजतक यह नहीं समझ पाई कि इस व्यक्ति को पति–रूप में पाना मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है, अथवा सबसे बड़ा दुर्भाग्य. कई बार लगता है, मेरी छुपी हुई प्रतिभा को कितने यत्न से उन्होंने तराशा है. प्रशंसा और प्रेरणा दे–देकर, कुछ कर डालने के लिए कितना उत्साहित किया है और इतनी ही तीव्रता के साथ इस बात का बोध भी होता है कि इस व्यक्ति ने मेरी सारी प्रतिभा का हनन कर डाला. दरअसल, यादव जी की रचनात्मकता और व्यक्तित्व के अनेक छोर हैं, इतने कि एक पकड़ो तो दूसरे के छूटने का ख़तरा पैदा हो जाता है. लेकिन मुख्यतया यादव जी के लेखकीय और संपादकीय जीवन में को हम चार खांचे में बांटकर देख सकते हैं. पहला एक कहानीकार के तौर पर, जब उन्होंने मोहन राकेश और कमलेश्वर के साथ मिलकर हिंदी कहानी की चौहद्दी को तहस–नहस कर दिया. दूसरा साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक के रूप में हिंदी के नए लेखकों की कई पीढ़ी तैयार करने की भूमिका. तीसरा–अपने विचारों से कट्टरपंथियों पर लगातार हमले करते रहना और उनके ख़िलाफ़ वैचारिक जंग छेड़ना और चौथा साहित्य में हाशिए पर पड़े दलित और स्त्री लेखन को साहित्य के केंद्र में ला देना.

साठ के दशक में राजेन्द्र यादव की कहानियों में दिखाई देने वाला अंतर्विरोध कहानी की स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त कर रहा था, समाज के पवित्र समझे जानेवाले रिश्तों पर हमले कर रहा था. लेकिन उस दौर में भी आलोचक राजेन्द्र यादव की कहानियों के अंतर्विरोध के आधार पर उसे अपने औज़ारों से ख़ारिज नहीं कर

पा रहे थे. एक आलोचक ने लिखा भी था– राजेन्द्र यादव का लेखन बहुत उलझा हुआ होता है. नामवर जी ने भी अपने एक लेख में कहा था कि प्राय: वो चक्करदार शिल्प गढ़ने के चक्कर में रहते हैं और उनकी भाषा की पेचीदगी भी इसी का परिणाम है. इन तमाम अंतर्विरोधों और कमज़ोरियों के बावजूद राजेन्द्र यादव की कहानियों ने उस वक्त की कहानी को एक नई राह दिखाई थी, जिसकी हिंदी कहानी की विकासयात्रा में एक अहमियत है, अपना स्थान है. दरअसल, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं– राजेन्द्र यादव की कहानियों में जो पेचीदगी दिखाई देती है वो उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है. याद कीजिए टी एस इलियट ने कहा था कि– लेखन अपने व्यक्तित्व से पलायन का दूसरा नाम है– शायद विरोध का भी. लेकिन बाद के दिनों में राजेन्द्र यादव और उनके नई कहानी के साथी एक सीमित दुनिया की वास्तविकता में उलझ कर रह गए, जिससे कि न सिर्फ़ नई कहानी आंदोलन का विकास अवरुद्ध हो गया, बल्कि आंदोलनों के अगुआ के लिए भी रचनात्मक लेखन असंभव होता चला गया. राजेन्द्र यादव भी इसके शिकार हुए.

जब राजेन्द्र यादव ने देखा कि कहानियों में उनका हाथ तंग होता जा रहा है तो उन्होंने साहित्यिक पत्रिका निकालने का जोख़िम उठाया. यह वो दौर था जब एक–एक करके हिंदी की पत्रिकाएं बंद हो रही थीं, तब हंस के प्रकाशन का जुआ (राजेन्द्र यादव के ही शब्द) यादव जी ने खेला. पिछले अट्ठाइस साल से राजेन्द्र यादव ये जुआ जीतते जा रहे थे, लेकिन काल से वो जीत नहीं पाए. नामवर सिंह तो कहते हैं कि राजेन्द्र यादव का नाम हिंदी साहित्य जगत में इस वजह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि उसने अट्ठाइस वर्षों तक हंस का संपादन किया. नामवर जी के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो सिर्फ़ हंस संपादन के लिए याद किए जाएंगे. नामवर जी का अभिप्राय यादव जी के इस अहम यो–गदान को भी रेखांकित करना है. हंस में अपने संपादकीय के माध्यम से राजेन्द्र यादव ने सांप्रदायिकता की राजनीति पर जमकर प्रहार किया. उन संपादकीयों की वजह से देश के कई हिस्सों में उनपर केस भी हुए. हंस की प्रतियां जलाई गईं और उनके दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी हुए. एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि लगने लगा था कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन तमाम दबावों के बावजूद राजेन्द्र यादव के रुख़ में ज़रा भी बदलाव नहीं आया और वो इस मोर्चे पर अंत तक डटे रहे. हालांकि कुछ दिनों पहले उन्हें वामपंथी कट्टरतावाद का भी शिकार होना पड़ा और हंस के सालाना जलसे में वरवरा राव की वादाख़िलाफ़ी से वो आहत थे.

राजेन्द्र यादव ने दलित विमर्श के माध्यम से जिस तरह से समकालीन हिंदी साहित्य में हस्तक्षेप किया, उसका मूल्यांकन होना भी शेष है. यादव जी के स्त्री विमर्श पर भी देह विमर्श का आरोप लगा. मुझे लगता है कि यादव जी का स्त्री विमर्श जर्मन ग्रीयर और सिमोन द बुआ के स्त्री विमर्श के बीच का रूप था, जहां वो परिवार के विघटन और यौन स्वच्छंदता के अलावा आपसी समझदारी की बात भी करते चलते हैं. जर्मन ग्रीयर की तरह यादव जी मानते थे कि स्त्रियां अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण में लगें और संबंधों को बाधा नहीं बनने दें, लेकिन उनके लेखन से यह साफ़ नहीं होता है कि वो परिवार के विघटन की शर्त पर ये करने की सलाह देते हैं. हालांकि राजेन्द्र यादव ख़ुद कहा करते थे कि वो किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं. किया भी नहीं. सिर्फ़ मित्रता की डोर को वो टूटने नहीं देते थे. राजेन्द्र यादव ने कई नए तरह के प्रयोग किए. उन्होंने ख़ुद ही लिखा था– अचानक ख़्याल आया कि अगर क़ानून रूप से अग्रिम जमानत ली जा सकती है तो अग्रिम श्रद्धांजलि क्यों नहीं लिखी जा सकती. आज ज़िंदा बने रहना भी तो अपराध ही है. मरने के बाद लोग दिवंगत के बारे में क्या–क्या लिखते और बोलते हैं, वह बेचारा न उसका प्रतिवाद कर सकता है और न उसमें कुछ घटा बढ़ा सकता है. दरअसल, मेरे ये संस्मरण उसी लाचार आदमी के प्रतिवाद हैं. इसी प्रतिवाद में उन्होंने ख़ुद और अपने साथियों के जीवित रहते ही उनपर श्रद्धांजलि लेख लिख डाले थे. उसी में एक जगह यादव जी ने लिखा है– मझे सबसे ईमानदार आत्मकथा ग़ालिब की ये पंक्तियां लगती हैं जहां वह कहता है कुछ अपनों की प्रिय तस्वीरें और कुछ सुंदरियों के पत्र– यही तो मरने के बाद मेरी अपनी कहानी है. राजेन्द्र जी यही आपकी भी कहानी है. अलविदा दोस्त. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

आज फिर क्यों

इन्दुमति सरकार

बंद ज़ुबां ख़ामोश नज़र
मन भीतरी झंझावातों से
उलझा हुआ
महसूस करता है कैसा दर्द
ये कैसी तड़प
मन को बेचैन किए है
आज फिर क्यों
ढूंढती हूं मैं
अपना अस्तित्व, अलग वजूद
छोड़कर कारवां इस वीराने में
आज फिर क्यों
किस राह की तलाश है मुझे
विमूढ़ शिथिल पड़े मस्तिष्क में
अनिष्ट की छाया पड़ने लगी है
आज फिर क्यों
हलचल–सी हो रही है
दिल में तूफान के आने का
संकेत दे रहे हैं बादल
रह–रह कर
एक अंजान–सा डर
धडकनों की रफ्तार
बढ़ा रहा है क्यों
आज फिर क्यों

किताब मिली

पुस्तक यहां एक गांव था	लेखक जयदीप हर्डीकर
प्रकाशक पेंगुइन बुक्स	मूल्य 199 रुपये

पत्रकार जयदीप हर्डीकर ने एक क़िताब लिखी है *यहां एक गांव था.* बांधों और अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के बीच जाकर पड़ताल के बाद लिखी गई इस किताब में उन्होंने बहुत बारीकी से बताया है कि किस तरह से विकास की अंधी दौड़ में आदिवासी और ग़रीब जनता को दरकिनार किया जाता है. जिन लोगों की ज़मीनों पर हम बड़ी–बड़ी परियोजनाएं संचालित करते हैं, उन्हें उखाड़ देते हैं और जीवन की न्यूनतम गारंटी तक नहीं देते. जयदीप के इस प्रयास को वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने जनमाध्यमों को जनता से जोड़ने की एक मिसाल कहा है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

मीडिया के मौजूदा परिदृश्य की एक पड़ताल

कृष्णकांत

भारतीय पत्रकारिता का इतिहास भले ही लगभग ढाई सौ पुराना हो चुका हो, लेकिन इसकी प्राचीनता के मुताबिक इस विषय में अभी साहित्य और शोधकार्यों की बेहद कमी है. पश्चिम में काफ़ी कुछ हो चुका है लेकिन भारत में अभी भी इस क्षेत्र में गंभीर चिंतन और लेखन का अभाव है. मीडिया और संचार सिद्धांतों के मामले में तो भारतीय पत्रकारिता के छात्र पूरी तरह पश्चिम पर निर्भर हैं. इस विषय पर अभी मौलिक चिंतन किया जाना बाक़ी है. तमाम विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के संस्थान खुल गए हैं लेकिन एक विषय के तौर पर अभी पत्रकारिता बेहद अनआर्गेनाज्ड, बिखरा हुआ विषय है. भारत में पत्रकारिता चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन का कारगर हथियार बनी इसलिए इतिहासकारों ने इसमें दिलचस्पी ली, लेकिन कंम्प्यूटर, टेलीविज़न और इंटरनेट आने के बाद मीडिया का जो मिला–जुला स्वरूप विकसित हुआ और बहुत तेज़ी से दिन–ब–दिन बदल रहा है, उसे लेकर अध्ययन, शोध और लेखन संतोषजनक नहीं है. हालांकि, संतोष की बात यह है कि अब बहुत सारे विद्वानों ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की है.

हाल ही में पत्रकार और लेखक प्रांजल धर की वाणी प्रकाशन से किताब आई है–समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में अख़बार. यह क़िताब मौजूदा दौर पूरी दुनिया में मीडिया, ख़ासकर अख़बारों की स्थितियों–परिस्थितियों की पड़ताल करती है. प्रांजल धर ख़ुद पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, इसलिए तमाम चुनौतियों और परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं. वे मीडिया के सरोकारों से लेकर उसकी व्यावसायिकता तक से बख़ूबी परिचित हैं. अपनी इस क़िताब में उन्होंने वैश्विक पत्रकारिता की प्राचीनता से लेकर आधुनिक तकनीक और बाज़ार की गहन पड़ताल की है. विश्व पत्रकारिता पर बात करते हुए वे पत्रकारिता की शुरुआत से लेकर क़रीब चार सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करते हैं. दुनिया भर के देशों में पत्रकारिता की शुरुआत के ज़िक्र के बीच वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि 'वैश्विक पत्रकारिता में अख़बारों का अध्ययन करते हुए एक बात साफ़ तौर पर हमारे सामने आती है कि अख़बारों का वर्गीकरण अलग–अलग देशों में अलग–अलग तरीक़े का है. भारतीय पत्रकारिता–शास्त्र के अध्ययन और शोध के मद्देनज़र यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां की पत्रकारिता को यहां के संदर्भ में समझा जाए और उसके तौर–तरीक़ों को भारत की क्षेत्रीय ज़रूरतों के लिहाज से स्थापित किया जाए.

समकालीन अफ़्रीकी और एशियाई पत्रकारिता शीर्षक से एक अध्याय में प्रांजल धर अफ़्रीकी और एशियाई देशों में पत्रकारिता की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल करते हैं. अभी भी अफ़्रीकी महाद्वीप में कई ऐसे देश हैं, जहां कोई अख़बार नहीं हैं और कई देश ऐसे हैं जहां नाम मात्र के अख़बार हैं. इन देशों की प्रेस संबंधी नीतियां और पत्रकारिता की दशा–दिशा पर यह अच्छा अध्याय है. दुनिया के ताक़तवर देशों के बारे में तो हम अक्सर जानते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सूचना तंत्र पर उनका कब्ज़ा है. लेकिन तीसरी दुनिया के सबसे ग़रीब देशों के बारे में पत्रकारिता का क्या हाल है, यह जानना दिलचस्प है. मसलन, अस्सी लाख की आबादी वाले रवांडा में कोई भी दैनिक अख़बार नहीं है. सत्तर लाख से अधिक आबादी वाले देश बेनिन में सर्वाधिक प्रसार वाले अख़बार ला नेशन की प्रसार संख्या मात्र पांच हज़ार है. हालांकि, अफ़्रीका में ही ऐसा क़ानून भी है जो मीडिया पर प्रतिबंधों का निषेध भी करता है. इसी तरह कांगो, इरीट्रिया, मलावी, नाइजीरिया, मोजाम्बिक आदि देशों में भी पत्रकारिता की दशा–दिशा पर निगाह डाली गई है. लेखक के मुताबिक, भारत जैसे चंद अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो एशियाई पत्रकारिता में तमाम रूढ़ियां और पश्चगामी शक्तियां दिखाई देती हैं. कहीं नृजातीय संघर्षों का बोलबाला है तो कहीं लोकतंत्र पर ही संकट के बादल मंडराते रहे हैं. इस कड़ी में प्रांजल धर श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, जहां पर हाल के वर्षों में कई पत्रकारों की हत्या कर दी गई. क़िताब में हवाला दिया गया है कि साउथ एशियन मीडिया कमीशन के अनुसार 2009 में दक्षिण एशिया में क़रीब एक दर्जन पत्रकार मारे गए थे, जिनमें नौ अकेले पाकिस्तान के थे. कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 2010 में मीडिया की दुनिया में पत्रकारों के लिए पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक इलाका रहा. अनेक मीडिया विश्लेषक मानते हैं कि नवा–ए–वक्त अख़बार उन अख़बारों में अग्रणी था जिसे अहमदियों के खिलाफ जनता का आक्रोश भड़काने के लिए पैसे मिले थे. आज पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने न सिर्फ़ एक तरीक़े का मीडिया मंच बना लिया है, बल्कि यह मंच इतना अधिक ताक़तवर है कि कई बार मुख्यधारा के अख़बारों में ख़बरों की प्राथमिकता तय करने की कोशिशें भी करता है.

समीक्ष्य पुस्तक	समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में अख़बार
लेखक	प्रांजल धर
प्रकाशक	वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य	350 रुपये

किताब में अतिवादियों द्वारा अपना समानांतर मीडिया उद्योग चलाने का विवरण भी महत्वपूर्ण है, मसलन–छह प्रमुख जिहादी संगठन अकेले पचास से अधिक अख़बारों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं. यह जनसंचार माध्यमों की ताकत का उपयोग कर जनता में अपना एजेंडा फैलाने अथवा दुराग्रहपूर्ण प्रचार का प्रमाण है. लेखक ने अगला अध्याय खाड़ी देशों की पत्रकारिता पर केंद्रित किया है, जिसमें मिस्र, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सउदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों को शामिल किया गया है. विभिन्न देशों में मीडिया की स्थितियों–परिस्थियों पर चर्चा करते हुए कुछ जानकारी देने वाली रोचक घटनाएं भी बीच–बीच में शामिल की गई हैं, जिससे क़िताब दिलचस्पी के साथ पढ़ी जा सकती है. अरब देशों में चल रहे फिल्म कारोबार की भी क़िताब में चर्चा है, जिसपर अक्सरहां काफ़ी खींचतान चलती रहती है.

पिछले क़रीब एक डेढ़ दशक में कई देशों में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर क्रांतियां हुईं. 2000 में सर्बिया की क्रांति, 2003 में जार्जिया की गुलाबी क्रांति, 2005 में यूक्रेन की नारंगी क्रांति, 2005 मे ही किर्गिस्तान की ट्यूलिप क्रांति या फिर ट्यूनीशिया की जैस्मिन क्रांति आदि. इन आंदोलनों में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई. लेखक ने संसार के आंदोलनों में वैश्विक पत्रकारिता की भूमिका अध्याय में इन क्रांतियों में मीडिया की उपादेयता पर चर्चा की है. लेखक ने भारतीय संदर्भों में कब–कब मीडिया ने जनांदोलनों को हवा दी, की भी पड़ताल की है.

मौजूदा सूचना विस्फोट के दौर में अख़बारों की साख़ बहुत अहम मसला है. हालांकि, भारत में आज भी छपे हुए प्रमाण माना जाता है, लेकिन अब भारतीय पत्रकारिता भी पेड न्यूज़ के चंगुल में है. ज्यादातर अख़बार अपने पारंपरिक तेवरों को त्याग कर व्यावसायिक रवैया अपना रहे हैं. समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में अख़बारों की साख़ अध्याय में अख़बारी साख़ पर चर्चा है. प्रांजल धर लिखते हैं–मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ी महिमा साख़ की है. विरोधाभास यह है कि विश्वसनीयता की ज़रूरत जितनी ही बढ़ती जा रही है, विज्ञापनबाज़ी और यशलोलुपता का प्रकोप भी उतना ही बढ़ता जा रहा है.

क्रास मीडिया मिल्कियत का प्रभाव और इसके चलते सत्ता को प्रभावित करने के मद्देनज़र चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं– ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें बनाना और बिगाड़ना एक बिल्कुल लग चीज़ है लेकिन जनता में खो चुकी अपनी साख़ को वापस लाना एक बिल्कुल दूसरी बात है. साख़ के इस सवाल को कोई भी बड़ा या छोटा व्यवसायी इतनी आसानी से नहीं हल कर सकता. वे इसका उपाय भी सुझाते हैं–अख़बारों या मीडिया को अपनी साख़ बनाने के लिए समतामूलक समाज के निर्माण का काम करना पड़ेगा. हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को उठाना पड़ेगा. साख़ की महिमा को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है.

क़िताब में समाचारों के वैश्विक असंतुलन पर भी चर्चा की गई है. समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में नवाचार अध्याय में पत्रकारिता में तेज़ी से बदलते तकनीकी और प्रस्तुतीकरण संबंधी ट्रेंड की चर्चा है. इसमें बदलते के प्रभावों पर भी दिलचस्प टिप्पणी है. आने वाले कल की पत्रकारिता और इसकी भाषा कैसी होगी, यह भी लेखक के चिंतन में शामिल है. पत्रकारिता की बदलती भाषा, उस पर बाजार का प्रभाव, मीडिया में भाषा की मानकता का संकट, हिंदी–उर्दू और अंग्रेज़ी का करीब करीब भद्दा घालमेल भी एक संकट है, जिसपर लेखक ने खुलकर लेखनी चलाई है. इंटरनेट के बाद वजूद में आया सोशल मीडिया, न्यू मीडिया पर भी इस क़िताब में पर्याप्त सामग्री है. मीडिया एजेंडा और पब्लिक एजेंडा पर लेखक का विश्लेषण बेहतर है. रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि पर एक–एक अध्याय हैं जो कि पठनीय हैं.

इस क़िताब में सबसे ख़ास बात यह है कि मीडिया जगत की वैश्विक स्तर पर समय–समय पर चलने वाली बहसों और इसमें शामिल विद्वानों पर अच्छी चर्चा है. यह आम पाठकों के अलावा मीडिया के छात्रों के लिए ख़ास उपयोगी है. इस क़िताब को पढ़ते हुए लेखक प्रांजल धर से यह आशा की जाती है कि भारतीय पत्रकारिता, ख़ासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो अच्छी क़िताबों और बेहतर कंटेंट का टोटा है, उसे दूर करने वे काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत में गूगल नेक्सस 5 और गूगल नेक्सस 7 (2013) भी जल्द ही आने वाले हैं. भारत में 16 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 28,999 रुपये और 32 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 32,999 रुपये है. 3 जी और 4 जी एलटीई सपोर्ट वाले गूगल नेक्सस 7 (32 जीबी मॉडल) की कीमत 25,999 रुपये है.

जल्द आएगी भारत में बीएमडब्ल्यू की नई बाइक

एक वर्ष पहले बीएमडब्ल्यू ने विदेश में अपनी दो नई बाइक एफ 700 और एफ 800 को लॉन्च किया था. भारतीय स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर है कि बीएमडब्ल्यू एफ 700 को भारत में लॉन्च करने जा रही है.

बीएमडब्ल्यू मोटोरॉड भारत में दिसंबर में एफ 700 बाइक लॉन्च कर सकती है. यह एफ 650 का ही नई वर्जन होगी.■

- रग्ड डिजाइन एलीमेंट्स के कारण माचो लुक
- फ्रंट फेंडर, ट्विन हेडलाइट्स, बीफी एक्जास्ट
- वाटर–कूल्ड, 4 स्ट्रोक, पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन
- इंजन की क्षमता –798 सीसी
- अधिकतम पावर आउटपुट –75बीएचपी
- 6 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन
- अधिकतम रफ्तार–192 किमी प्रति घंटे
- माइलेज–25.64 किमी प्रति लीटर
- स्टैंडर्ड एबीएस प्रणाली, रेड, ग्रे और सिल्वर रंगों में मौजूद होगी.
- एफ 700 की कीमत –13 लाख रुपए

भारत आएगा गूगल नेक्सस 10 टैबलट

भारत में गूगल नेक्सस 5 और गूगल नेक्सस 7 (2013) भी जल्द ही आने वाले हैं. भारत में 16 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 28,999 रुपये और 32 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 32,999 रुपये है. 3 जी और 4 जी एलटीई सपोर्ट वाले गूगल नेक्सस 7 (32 जीबी मॉडल) की कीमत 25,999 रुपये है.

भारत में जल्द ही गूगल नेक्सस 10 टैबलट आने वाला है. इस टैबलट में 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज है और यह केवल वाई–फाई वर्जन है.

भारत में गूगल नेक्सस 5 और गूगल नेक्सस 7 (2013) भी जल्द ही आने वाले हैं. भारत में 16 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 28,999 रुपये और 32 जीबी वाले गूगल नेक्सस 5 की कीमत 32,999 रुपये है. 3 जी और 4 जी एलटीई सपोर्ट वाले गूगल नेक्सस 7 (32 जीबी मॉडल) की कीमत 25,999 रुपये है. गूगल नेक्सस 10 टैबलट को कंपनी ने पिछले ही साल लॉन्च किया था, हालांकि अभी तक इसे भारत में नहीं उतारा गया. इस टैबलट में 2560 X 1600 पिक्सल्स रेजॉल्यूशन और 300 पीप–ीआई (पिक्सल्स/इंच) वाला 10 इंच का डिस्प्ले है, जो कॉर्निंग गरिला ग्लास 2 से बना है. इसमें 1.7 गी–गाहर्ट्ज ड्यूल–कोर कोर्टेक्स ए15 प्रोसेसर, मालि–टी604 जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) और 2 जीबी रैम है. इसमें 16 जीबी और 32 जीबी इंटरनल स्टॉरेज ऑप्शन हैं. इसमें मेमरी कार्ड स्लॉट नहीं है. इसमें पीछे की तरफ 5 मेगापिक्सल्स और आगे की तरफ 1.9 मेगापिक्सल्स कैमरा है. इसमें 9000 एमएच की बैटरी है.■

सैमसंग का लचीली स्क्रीन वाला स्मार्टफोन

सैमसंग ने पिछले महीने कर्व्ड डिस्प्ले वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन पेश किया था, लेकिन इस स्मार्टफोन को बहुत वाह–वाही नहीं मिली. इसके बावजूद कंपनी डिस्प्ले के साथ ऐसे प्रयोग जारी रखेगी. अब सैमसंग की योजना लचीले और मुड़ने वाले डिस्प्ले पेश करने की है. सैमसंग ऐनालिस्ट डे पर कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ ओ–ह्युन क्वॉन ने आगे के कुछ सालों के लिए कंपनी के रोडमैप का खुलासा किया.

इस इवेंट में कंपनी ने जिन 2 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज्यादा बात की, उनमें बेंडेबल (लचीले) और फोल्डेबल (पूरी तरह मोड़े जा सकने वाले) डिस्प्ले शामिल है. प्लान के मुताबिक, कंपनी अगले साल तक लचीली स्क्रीन्स पेश कर सकती है, जबकि पूरी तरह मोड़े जा सकने वाले डिस्प्ले कंपनी 2016–17 तक ला सकती है. हालांकि कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि लचीली स्क्रीन्स पर सबसे पहला डिवाइस कौन सा आएगा, लेकिन अगले साल सैमसंग गैलक्सी एस5 आने वाला है और यह उम्मीद की जा रही है कि उसमें यह स्क्रीन होगी.■

कम दाम में बेहतरीन फीचर्स के साथ ज़ोलो ए-600 लॉन्च

इसकी कीमत कम बजट के लोगों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. आप इसे 8,199 रुपये में खरीद सकते हैं. इस कीमत में चार इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले कम ही फोन बाजार में उपलब्ध हैं.

भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ज़ोलो ने अपना नया स्मार्टफोन ए–600 लॉन्च किया है. इसमें कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसका प्रोसेसर, बड़ी स्क्रीन और कीमत, इसे दूसरे फोन्स से अलग करती है.

इसकी कीमत कम बजट के लोगों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. आप इसे 8,199 रुपये में खरीद सकते हैं. इस कीमत में चार इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले कम ही फोन बाजार में उपलब्ध हैं. जोलो ए–600 में 1.3 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर एमटी 6572 डब्ल्यू प्रोसेसर है. इस प्रोसेसर की मदद से कई सारे एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी एप्लीकेशन आराम से रन करते हैं. ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 1.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होता है. इस फोन की स्क्रीन 4.5 इंच साइज है, जो आईपीएस डिस्प्ले के साथ क्यू एचडी भी है. रिजोल्यूशन 960X540 पिक्सल है. इसके अलावा फोन में दो सिम कार्ड स्लॉट हैं. माइक्रो यूएसबी, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट और 3.5 एमएम का ऑडियो जैक है. ■

अन्य फीचर्स

ऑपरेटिंग सिस्टम – 4.2 जेली बीन
रैम– 512 एमबी
इंटर्नल स्टोरेज – 4 जीबी
कैमरा – 5 मेगापिक्सल रियर, फ्रंट वीजीए
बैटरी – 1900 एमएएच
इसके अलवा फोन में
वीडियो कॉलिंग, एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, ब्लूटूथ, वाईफाई, एफएम रेडियो है.

एम-पासपोर्ट सेवा अब फोन पर

एम–पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप्लिकेशन अब विंडोज व एप्पल के आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा. विदेश मंत्रालय द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया है. मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा 21 मार्च, 2013 को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर शुरू किया था

पायलट परियोजना के अच्छे नतीजे मिलने के बाद अब इसे विंडोज

व एप्पल के आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी शुरू किया गया है. सरकार एम–पासपोर्ट सेवा को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भागीदारी मॉडल के तहत संचालित कर रही है. यह ऐप्लिकेशन स्मार्टफोन पर पासपोर्ट संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और यह पासपोर्ट सेवा परियोजना की विस्तारित सेवा है. एम–पासपोर्ट सेवा के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं एवं जानकारी अपने स्मार्टफोन पर उपलब्ध होती है. यह ऐप्लिकेशन कई प्रकार की सेवाएं मसलन पासपोर्ट की स्थिति, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और जिलों में पासपोर्ट प्रकोष्ठ को ढूंढ़ने में मदद के अलावा अन्य सामान्य जानकारियां उपलब्ध कराती हैं. आवेदन के बाद लोग इस ऐप्लिकेशन की मदद से अपने पासपोर्ट की स्थिति का पता फाइल नंबर तथा जन्मतिथि बता कर लगा सकते हैं. यदि पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट भेज दिया गया है तो इस ऐप्लिकेशन की मदद से डिलिवरी की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है. अब बार–बार पासपोर्ट ऑफिस जाकर पता करने जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगी.■

हार्ले डेविडसन हुआ मेड इन इंडिया

अमेरिका की लग्जरी स्पोर्ट बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन पहले कई मॉडल्स को पूरी तरह आयातित करती थी. इसके बाद कंपनी ने भारत में संयंत्र असेंबलिंग की शुरुआत की. हार्ले डेविडसन की देश में कई नई बाइक असेंबल होना शुरू हो गईं हैं और कंपनी ने अब एक नई शुरुआत भी की है.

हार्ले डेविडसन की बाइक को भारत में इंपोर्ट और असेंबल किया जाता था. कंपनी अब भारत में बाइक बनाएगी और विदेशों में एक्सपोर्ट करेगी. अमेरिका की मोटरसाइकिल बनाने वाली प्रमुख कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में मोटरसाइकिल का निर्माण शुरू करेगी. साथ ही कंपनी भारत से यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों को निर्यात भी करेगी.

कंपनी ने कहा कि वह अगले साल की पहली तिमाही में दो नये मॉडल का निर्माण शुरू करेगी. कंपनी ने हाल ही में दो मॉडल हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट 500 पेश किया है. हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ मैथ्यू लेवाटिक ने कहा कि हम भारत में अपने संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट मॉडल बनाने के लिए करेंगे, जो न सिर्फ यहां के बाजार की जरूरत पूरी करेगा, बल्कि यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को भी आपूर्ति करेगा. ■

नई होंडा सिटी की ग्लोबल लॉन्च

25 नवंबर को भारत में नई होंडा सिटी का ग्लोबल लॉन्च करने की तैयारी है. नई होंडा सिटी पेट्रोल के साथ-साथ डीजल इंजन में भी होगी. नई होंडा सिटी की डिलीवरी जनवरी 2014 से शुरू होगी.

होंडा ने नई होंडा सिटी को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी अगले महीने नई होंडा सिटी का भारत में ग्लोबल लॉन्च करने जा रही है. सूत्रों का ये भी कहना है कि होंडा अगले महीने से नई सिटी की बुकिंग भी शुरू कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, 25 नवंबर को भारत में नई होंडा सिटी का ग्लोबल लॉन्च करने की तैयारी है. नई होंडा सिटी पेट्रोल के साथ–साथ डीजल इंजन में भी होगी. नई होंडा सिटी की डिलीवरी जनवरी 2014 से शुरू होगी.

सूत्रों की मानें तो होंडा ने डीलर्स को पुरानी होंडा सिटी की सप्लाई बंद करने को कहा है. फिलहाल डीलर्स होंडा सिटी का पुराना स्टॉक बेच रहे हैं. हालांकि वेटिंग कम करने के लिए होंडा अमेज के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की जा रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बनने से महज चंद कदम दूर हैं. कोहली ने अब तक 119 एकदिवसीय मैचों में 4919 रन बनाए हैं. अभी तक यह रिकॉर्ड सर विवियन रिचर्ड्स के नाम दर्ज है. उन्होंने यह उपलब्धि 126 मैचों में हासिल की थी. विराट कोहली एकदिवसीय मैचों में 17 शतक लगा चुके हैं. इस मुकाम तक पहुंचने में सचिन ने विराट से ज्यादा वक्त लिया था.

भारतीय क्रिकेट में एक दौर था, जब परफॉर्मेंस को अनुभव से जोड़कर देखा जाता था. कई बार ऐसे मौके आए, जब कहा गया कि फलां सीनियर खिलाड़ियों के बाद क्या नई पीढ़ी भारतीय क्रिकेट के मौजूदा मुकाम को कायम रख पाएगी. आशंकाएं लाजिमी थीं, क्योंकि मुहावरों की भाषा में परफेक्शन उसी के पास होता है, जिसने अपने बाल धूप में सफेद किए हों. यह दौर बदला और नई पौध ने अपने प्रदर्शन से इन सभी आशंकाओं पर विराम लगाया और यह साबित किया कि प्रतिभा अनुभव की मोहताज नहीं होती. उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, जो इन नई पीढ़ी के धुरंधरों में स्पष्ट दिखती है

नई पीढ़ी के धुरंधर

बदले बदले रोहित (रोहित 2.0)

जब से आईपीएल में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन की कमान संभाली है, तब से रोहित के लिए सब कुछ बदला-बदला नज़र आ रहा है. पिछले कुछ महीने रोहित के लिए बतौर खिलाड़ी और कप्तान उपलब्धि भरे रहे हैं. सबसे पहले तो रोहित ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई को आईपीएल चैंपियन बनाया. इसके बाद चैपियंस लीग का खिताब भी जितवाया. वह यहीं नहीं रुके, बल्कि भारतीय टीम में शानदार वापसी भी की और बतौर ओपनर भारतीय टीम के लिए शानदार पारियां खेलीं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई एकदिवसीय सीरीज उनके अंतरराट्रीय करियर के लिए यू-टर्न साबित हुई. इस सीरीज में सचिन, सहवाग के बाद एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में वे दोहरा शतक(209 रन) बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने. इस सीरीज में उन्होंने पांच मैचों में दो शतकों और एक अर्धशतक की मदद से कुल 491 रन बनाए. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह बनाने वले रोहित ने अपने पदार्पण मैच में शतक बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं. जिस तरह रोहित ने एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया और उसमें 16 छक्के लगाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया उससे तो यह बात सिद्ध हो गई कि रोहित 2015 के विश्वकप में धोनी के तरकश में सबसे महत्वपूर्ण तीर होंगे, जिसका तोड़ विपक्षी टीमों को तलाशना होगा. जिस तरह से रोहित और शिखर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे टीम को सहवाग और गंभीर जैसे धुरंधरों की कमी महसूस नहीं हो रही है. नई पीढी के ये बल्लेबाज उनसे ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं.

नवीन चौहान

सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज के पहले भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया, उससे सचिन के लिए क्रिकेट को अलविदा कहना और आसान हो गया. विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और कप्तान महेंद्र सिह धोनी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो यह साबित हो गया है कि भारतीय टीम का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है. सचिन की विरासत को संभालने वाले खिलाड़ी टीम इंडिया को मिल गए हैं. इनमें से अधिकांश खिलाड़ी वे हैं, जिन्होंने सचिन के क्रिकेट में बढ़ते कद के साथ क्रिकेट का ककहरा सचिन को खेलता देखकर सीखा और उनके साथ क्रिकेट खेलने का सौभाग्य पाया. दो दशक तक भारतीय क्रिकेट की धुरी रहे फेबुलस फाइव क्लब (सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, कुंबले) के सचिन आखिरी स्तंभ हैं, जिन्होंने मिलकर भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा बदल दी, लेकिन इन खिलाड़ियों ने जाते-जाते भारतीय क्रिकेट को इतना कुछ दे दिया है, जिसे याद करके हमें सदैव गर्व होगा कि भारतीय क्रिकेट की सेवा इस तरह के महान खिलाड़ियों ने की थी.

सचिन का उत्तराधिकारी

विराट कोहली ने पिछले तीन साल में जैसी बल्लेबाजी की, उससे यह तो साफ हो गया था कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने जिस तरह की आक्रामक और कंसिसटेंट बल्लेबाजी की है, उससे तो सचिन के उत्तराधिकारी के रूप में केवल वही नज़र आते हैं. कोहली अभी 24 साल के हैं, लेकिन उनका बल्ला ऐसा जलवा बिखेर रहा है कि सचिन का जादू भी फीका पड़ता दिखाई पड़ रहा है. कोहली एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बनने से महज चंद कदम दूर हैं. कोहली ने अब तक 119 एकदिवसीय मैचों में 4919 रन बनाए हैं. अभी तक यह रिकॉर्ड सर विवियन रिचर्ड्स के नाम दर्ज है. उन्होंने यह उपलब्धि 126 मैचों में हासिल की थी. विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में 17 शतक लगा चुके हैं. इस मुकाम तक पहुंचने में सचिन ने विराट से ज्यादा वक्त लिया था. सचिन ने एकदिवसीय करियर का 17 वां शतक 196 वें मैच में लगाया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई हालिया एकदिवसीय सीरीज में विराट ने लगातार दो आक्रामक शतक लगाए, जिसमें 52 गेंदों में लगाया शतक किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाया सबसे तेज शतक है. इन पारियों ने लोगों को 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन के लगाए शतकों की याद ताजा कर दी. कोहली ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई, वह सचिन के आक्रामक अंदाज से कतई उन्नीस नहीं था. कोहली सचिन की तरह एकदिवसीय मैचों में पारी की शुरुआत नहीं करते हैं. बावजूद इसके मैच दर मैच शतक लगाए जा रहे हैं. उन्हें रनों का पीछा करने के मामले में चैंपियन ऑफ चेज़ कहा जाने लगा है. जिन मैचों में कोहली शतक लगाए हैं, उनमें एक को छोड़कर भारतीय टीम को सभी में विजयश्री हासिल हुई है. तीन साल से कोहली हर साल लगभग 1000 रन बनाने मे कामयाब रहे हैं. अपने छोटे से करियर में कोहली दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सभी टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ एकदिवसीय मैचों में शतक लगा चुके हैं. उन्हें अपने बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम भी मिला और वह आईसीसी की हालिया वन-डे रैंकिग में पहले पायदान पर पहुंच गए. वह सचिन और धोनी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय हैं. विराट टेस्ट मैचों में भी सफलता अर्जित कर रहे हैं, अब तक वह 18 टेस्ट मैचों में 4 शतक बना चुके हैं. अगर अब उन्हें सचिन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है तो यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. सचिन भी यह कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह की क्रिकेट विराट खेल रहा है, उनके रिकॉर्डों तक पहुंचने और तोड़ने में वह सफल हो सकता है.

शिखर छूते शिखर

शिखर धवन ने जिस आक्रामक तरीके से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की और इस सिलसिले को एक दिवसीय क्रिकेट में भी जारी रखे हुए हैं, यह भारतीय क्रिकेट की बदलती तस्वीर को दिखाता है. लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते रहने वाले शिखर को एक मौके के तलाश थी. खराब फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे सहवाग और गंभीर के टीम से बाहर जाते ही शिखर को बुलावा मिला और उन्होंने ऐसी गार्ड ली की सहवाग और गंभीर के लिए टीम में वापसी करना मुश्किल कर दिया. सहवाग जिस शैली के बल्लेबाज हैं, शिखर धवन भी उसी शैली के बल्लेबाज हैं. वह गेंदबाजों को मौका नहीं देते हैं, न ही आसानी से अपनी विकेट गंवाते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर जो बेहतरीन शुरुआत दी, उसी की बदौलत टीम इंडिया दो बार 350 रनों से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करने में कामयाब रही और दो बार ऑस्ट्रेलिया को तीन सौ से ज्यादा रनों का पीछा करने की चुनौती पेश की. धवन इतनी सहज और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है, जैसे वह सालों से टीम के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हों. शिखर जिस तरह की बल्लेबाजी का मुज़ाहिरा पेश कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वह लंबे समय तक टीम इंडिया की मजबूत कड़ी बने रहेंगे.

धोनी की करिश्माई कप्तानी

धोनी को अब लोगों ने किस्मती कप्तान कहना बंद कर दिया है. धोनी ने अपनी कप्तानी के बल पर जो विजयगाथा लिखी है, वह दुनिया के अच्छे से अच्छे कप्तान नहीं लिख सके. धोनी चुपके-चुपके मिशन 2015 की तैयारी में जुटे हैं और वो क्लाइव लॉयड और रिकी पोंटिंग के बाद विश्वकप खिताब को बचाने वाले कप्तान बनने की फिराक में हैं. उन्होंने अपने जिस ठंडे-चपल दिमाग और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है, वह काबिलेतारीफ है. दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी धोनी की कप्तानी का कायल है. धोनी ने सामने से मोर्चा संभालते हुए आसानी से हार न मानने का जो जज्बा टीम इंडिया के खिलाड़ियों में पैदा किया है, वह उनकी उपलब्धियों में चार चांद लगाता है. जिस भी खिलाड़ी को मौका मिलता है, वही अकेला टीम की डूबती नैया को पार लगा देता है. खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की चिंगारी पैदा करना धोनी की सबसे बड़ी उपलब्धि है. उनकी यही कला उन्हें क्रिकेट के महानतम कप्तानों में जगह दिलाती है.

गेंदबाजी अब भी सबसे कमजोर कड़ी

भारतीय टीम की गेंदबाजी अब भी सबसे कमजोर कड़ी है. कोई भी गेंदबाज लंबे समय तक अपनी लय और फॉर्म बरकरार रखने में नाकामयाब रहे हैं. टीम को जहीर के अनुभव की कमी खल रही है, लेकिन फिटनेस और फॉर्म की समस्या से जूझ रहे जहीर की वापसी होती दिखाई नहीं पड़ रही है. भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी ने अपनी गेदबाजी से आशाएं तो जगीं हैं, लेकिन वे भी लगातार टीम में बने रहने में असफल रहे है. भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है. जडेजा कुछ समय के लिए एकदिवसीय रैंकिंग में नंबर एक पर बने रहे. उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी के लिए इंग्लैड के खिलाफ हुई सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया था. कई गेंदबाज पाइपलाइन में हैं. उमेश यादव, वरुण एरोन, इशांत शर्मा, अमित मिश्रा, प्रज्ञान ओझा, इरफान पठान सभी खिलाड़ी टीम में आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी गेंदबाज लगातार बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है. गेंदबाजों को रास्ता दिखाने के लिए एक अनुभवी गेंदबाज की उपस्थिति मैदान में जरूरी हो जाती है, यह काम टीम इंडिया के लिए जहीर खान ही कर सकते हैं, जो भूमिका जहीर ने 2011 के विश्वकप में अदा की थी, वैसी ही अपेक्षा उनसे अभी भी है. जहीर यदि टीम इंडिया में वापसी करने में कामयाब होते हैं तो यह टीम के लिए संजीवनी साबित होगी.

सफलता हर बार तुक्के से नहीं मिलती है. यदि हिम्मत, जज्बा और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की हिम्मत हो तो कोई भी किला फतह किया जा सकता है. और जब सेना में एक से बढ़कर एक वीर हों तो अनहोनी को होनी में बदला जा सकता है. और ऐसा ही कुछ धोनी के धुरंधर करते दिखाई पड़ रहे हैं. आजकल जिस आक्रामक अंदाज में टीम इंडिया खेल रही है. ऐसे में उन्हें एकबार फिर 2015 में दुनिया फतह करने से कोई नहीं रोक सकेगा. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
18 नवंबर–24 नवंबर 2013

भारत और पाकिस्तान के कलाकार जब 1980 के दशक में एक–दूसरे के यहां अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तब रेशमा ने भारत में लाइव परफॉर्मेन्स दिया था. फिल्म निर्माता सुभाष घई के उस गीत...चार दिनों दा प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई...ने रेशमा की गायिकी को पूरी दुनिया में खुशबू की तरह फैलाया. फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उनकी आवाज को अपनी फिल्म हीरो में इस्तेमाल किया था, जिसे आज भी श्रोता पसंद करते हैं. लोक स्वर ऐसा, जिसे सुनते ही बंजारों की रगों में दौड़ती मस्ती पूरी शिद्दत से महसूस होती थी.

रेशमा : जादुई आवाज़ की
लंबी जुदाई

हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा और अंखियां नू रहने दे अंखियों दे कोल कोल, जैसे गीत रेशमा की आवाज में सज मानो खुद पर इठलाते थे. उनकी आवाज में अलग ही तरह की क़शिश थी, जो उनको सबसे अलग पहचान देती थी. इस गाने के बारे में रेशमा का कहना था कि हीरो में गाया हुआ मेरा यह गाना सचमुच मेरे ऊपर फिट हो गया.

एम. एच. पाशा

अपने पीछे छोड़ गईं बहुत सारी आवाज़ों के वो सुर, जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक बंधन में बांधने की लोक गाथायें गाते–सुनते रहेंगे. रेशम जैसी आवाज़ की मल्लिका रेशमा का 3 नवंबर को 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से गले के कैंसर से पीड़ित थीं. उनके परिवार में उनका पुत्र उमैर और पुत्री खदीजा हैं. दमादम मस्त कलंदर...और लंबी जुदाई...जैसे असरन्दाज गीतों की अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. रेशमा का जन्म राजस्थान में बीकानेर के एक बंजारा परिवार में 1947 को हुआ था. रेशमा की शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी गायिकी ने ये साबित कर दिया कि कलाकार की कला ही सबसे बड़ी तालीम है. शुरू में वह दरगाह पर गाती थीं. ऐसे ही शहबाज कलंदर की दरगाह पर 12 साल की नन्हीं रेशमा को गाते सुन कर एक टीवी एवं रेडियो प्रोड्यूसर ने पाकिस्तान के सरकारी रेडियो पर चर्चित गीत लाल मेरी रेशमा से गवाने की व्यवस्था की. यह गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और रेशमा पाकिस्तान के लोकप्रिय लोक गायकों में शामिल हो गईं. 1960 के दशक में रेशमा का जादू सिर चढ़ कर बोला और उन्होंने पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

भारत और पाकिस्तान के कलाकार जब 1980 के दशक में एक–दूसरे के यहां अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तब रेशमा ने भारत में लाइव परफॉर्मेन्स दिया था. फिल्म निर्माता सुभाष घई के उस गीत...चार दिनों दा प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई ने रेशमा की गायिकी को पूरी दुनिया में खुशबू की तरह फैलाया. फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उनकी आवाज को अपनी फिल्म हीरो में इस्तेमाल किया था, जिसे आज भी श्रोता पसंद करते हैं. लोक स्वर ऐसा, जिसे सुनते ही बंजारों की रगों में दौड़ती मस्ती पूरी शिद्दत से महसूस होती थी. रेशमा स्टूडियो में जाने से घबराती थीं. इसलिए उनके अनुरोध पर लंबी जुदाई...गाना दिलीप कुमार के घर पर रिकॉर्ड हुआ था. रेशमा उन चंद पाकिस्तानी कलाकारों में थीं, जिन्हें पाकिस्तान ने समझा और उनकी कद्र भी की. उन्हें कॉमेडियन बब्बू बराल और गजल गायक मेहदी हसन जैसे फनकारों की तरह इलाज के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा. यह कहना हालांकि बहुत रवायती होगा, लेकिन सच यही है कि सांस्कृतिक संदर्भों में रेशमा भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल की तरह थीं. खुद रेशमा का कहना था कि भारत और पाकिस्तान उनके लिए दो आंखों की तरह हैं. उनका कहना था कि कलाकारों के लिए देश की सीमाएं कभी बाधा नहीं बनतीं और भारत में उन्हें हमेशा बेहद प्यार और सम्मान मिला है. रेशमा चाहती थीं कि भारत–पाकिस्तान अमन–चैन से रहें.

रेशमा की आवाज में कोई चुलबुला गीत सुन कर ऐसी चुलबुलाहट महसूस होती है, जो घोर उदासी के बाद आती है. ऐसा उनके गीत, मेरी हमजोलियां, कुछ यहां कुछ वहां... को सुनते हुए महसूस किया जा सकता है. रेशमा की यह खूबी रही कि वे उस कराची में रहकर भी अपनी संवेदनशीलता बरकरार रख पाई, जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा था. यहां के मच्छर डीटीटी से नहीं, कव्वालों की तालियों से मरते हैं. हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा और अंखियां नू रहने दे अंखियों दे कोल कोल, जैसे गीत रेशमा की आवाज में सज मानो खुद पर इठलाते थे. उनकी आवाज में अलग ही तरह की क़शिश थी, जो उनको सबसे अलग पहचान देती थी. इस गाने के बारे में रेशमा का कहना था कि हीरो में गाया हुआ मेरा यह गाना सचमुच मेरे ऊपर फिट हो गया. उस गीत ने मुझे जितनी प्रसिद्धि दिलाई, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. इसी की बदौलत मैं रातों–रात स्टार बन गई. उनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया, जब रेशमा आर्थिक परेशानियों में घिर गईं थीं. तब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और संगीत प्रेमी परवेज मुशर्रफ ने उन्हें दस लाख रुपये दिए ताकि वह अपना क़र्ज़ा चुका सकें और बाद में मुशर्रफ ने रेशमा के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की सहायता राशि भी तय की.

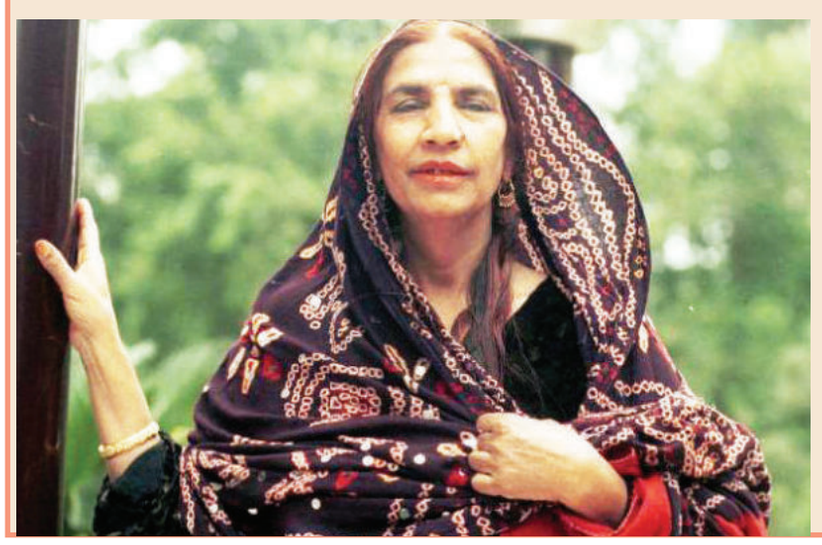

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें सितारा ए इम्तियाज और लीजेंड्स ऑफ पाकिस्तान सम्मान प्रदान किया था. उन्हें और भी कई राष्ट्रीय सम्मान मिले थे, लेकिन प्रसिद्धि से बेपरवाह रेशमा हमेशा परंपरागत कपड़ों में ही नजर आईं.

हीरो फिल्म के निर्देशक सुभाष घई सहित तमाम हस्तियों ने रेशमा के निधन पर शोक जताया है. सुभाष घई ने कहा कि रेशमा जी आज भी हमारे दिल में हैं. मैं जब भी सूफी गानों के बारे में सोचता हूं तो रेशमा जी याद आ जाती है.■

प्रीव्यू

गोरी तेरे प्यार में

निर्देशक	पुनीत मल्होत्रा.
प्रोड्यूसर	करन जौहर.
संगीत	विशाल–शेखर.
कलाकार	इमरान खान, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, अनुपम खेर.
कहानी लेखन	अरशद सैय्यद, पुनीत मल्होत्रा.

बॉलीवुड में हास्य और रोमांस पर आधारित फिल्मों की भरमार है, लेकिन गोरी तेरे प्यार में उन फिल्मों से अलग है. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाया है अभिनेता इमरान खान और करीना कपूर ने. इसके अलावे फिल्म में श्रद्धा कपूर का भी अभिनय देखने लायक है. फिल्म के निर्देशक हैं पुनीत मल्होत्रा. संगीत विशाल–शेखर का है. यह फिल्म एक ऐसे युवक श्रीराम वेंकट (इमरान खान) की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका दीया शर्मा (करीना कपूर) को मनाने के लिए शहर से गांव आ जाता है. इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे एक शहरी लड़का समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही एक सामान्य लड़की के प्यार में पड़ जाता है. फिल्म में इमरान एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जिसे परिवार, घर, दोस्तों और रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं है. करीना कपूर इस फिल्म में दीया नाम की ऐसी गोरी के किरदार में हैं, जो गांव की न होकर भी गांवों से प्यार करती हैं. फिल्म में करीना ने एक तेज–तर्रार लड़की का किरदार निभाया है. यह फिल्म सचमुच एक मजेदार और मनोरंजक फिल्म है. बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर अपनी नई फिल्म गोरी तेरे प्यार में का फिल्मांकन गांव में होने से काफी रोमांचित हैं. करीना के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उन्होंने असली गांव में फिल्मांकन किया है. करीना कहती हैं कि मेरे लिए यह बहुत बड़ा रोमांच था कि हम अपने फिल्म के लिए गांव गए. उन्होंने कहा कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी फिल्म करूंगी, जिसमें मैं सच में गांव जाऊंगी. फिल्मों से मिटते गांवों को इस फिल्म में नये अंदाज में प्रस्तुत किया गया है. करीना इस फिल्म में सूती और बंधिनी कपड़ों में नजर आएंगी, जिन्हें डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है. करीना का इमरान खान के साथ यह दूसरी फिल्म है. इससे पहले इस जोड़ी ने एक मैं और एक तू में साथ काम किया था. फिल्म में एक जबरदस्त आइटम नंबर भी है, जिसे अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने पर छोटी स्कर्ट में फिल्माया गया है. यह आइटम नंबर काफी जोशीला है. ■

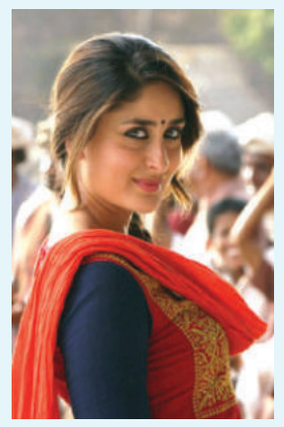

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉस

मशहूर कहावत है कि जब आदमी के दिन बुरे आते हैं तो उसे ऊंट पर भी कुत्ता काट लेता है और जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं तो सबसे पहले कुत्ता रास्ता से हट जाता है. यानी मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना हो जाती है. आज कल यही हाल है बॉलीवुड स्टार खिलाड़ी कुमार का. अक्षय कुमार की कुंडली में राजयोग है. इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए कि पिछले 5 साल में लगातार फ्लॉप और सुपर फ्लॉप फिल्में चांदनी चौक टू चाइना, 8–18 तस्वीर, कमबख्त इश्क़, ब्लू, दे दना दन, हाउसफुल, खट्टा मीठा, एक्शन रिपले, तीस मार खां, पटियाला हाउस, थैंक यू, देसी बॉयज, हाउसफुल 2, रावडी राठोड़, जोकर, खिलाड़ी 786, स्पेशल 26, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और अब बॉस जैसी फिल्में देकर भी अक्षय कुमार अपने पायदान पर जमे हैं. इसके कई समीकरण हैं, जिसको फिल्मी पंडित ही जानते हैं. बस आप ये समझ लें कि खिलाड़ी कुमार किसी भी हाल में नुकसान में नहीं. ताज़ा ताज़ा उनकी फ्लॉप फिल्म बॉस आई है. हालांकि इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 55 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था.

ग्रांड मस्ती

उम्मीदों से परे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी ग्रांड मस्ती ने छठे हफ्ते में भी लगभग 50 लाख का बिजनेस किया. ये ऐसी फिल्म है, जिसको हर आदमी अकेले में देखना चाहता है और देख रहा है. इसका वयस्क कॉमेडी का जवान और रसीला तड़का लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इसलिए हर आदमी मज़ा भी ले रहा है और बुराई भी कर रहा है .

शाहिद

फिल्में समाज का आईना है. अगर आप मानते हैं तो फिर आपको ये शाहिद नाम की फिल्म का आईना ज़रूर देखना चाहिए. अपने पहले ही हफ्ते में इस फिल्म ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था. फिल्म शाहिद ये साबित करती है कि फिल्में स्टार नहीं, दर्शक ही चलाते हैं.

वार छोड़ ना यार

फिल्म वार छोड़ ना यार ने अपने पहले ही हफ्ते मे 4.5 करोड़ का कारोबार किया. अपनी पहली फिल्म का निर्देशन कर रहे फराज़ हैदर भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर संघर्ष जैसे मुद्दों को बहुत ही हास्य और व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया है और दर्शकों के लिए सही मनोरंजन देने वाली फिल्म बनाई है. ये फिल्म काफी कम बजट में बनी है, लेकिन ह्यूमर के साथ सरहद पर मोहब्बतों का नया पैग़ाम देकर दिलों के दरमियान वार की जगह प्यार भरने की कोशिश की है.

मिक्की वाइरस

सौरभ वर्मा द्वारा निर्मित फिल्म मिकी वायरस में साइबर क्राइम पर आधारित कहानी फिल्माई गई है. मिकी वायरस में मनीष पॉल मुख्य किरदार में हैं, जो दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहे हैं. इंस्पेक्टर के रोल में वरुण बडोला ने दमदार अदाकारी की है. मनीष चौधरी अपने किरदार में फिट रहे. पूजा गुप्ता, एली अवराम, नितेश पांडे ने ठीक–ठाक अदाकारी की है . कामयानी के किरदार में एली को करने को कुछ खास नहीं रहा. हां, इतना ज़रूर है कि ये वाइरस बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया और फिल्म ने पहले ही हफ्ते मे 7.75 करोड़ का कारोबार भी किया .

इश्क़ एक्चुअली

लव स्टोरी हमेशा कामयाब रहे, ये ज़रूरी तो नहीं. राजीव खंडेलवाल अभिनीत ये फिल्म रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इससे पहले इनकी फिल्म टेबल नंबर–21 आई थी, जो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही. इश्क़ एक्चुअली ने अपने पहले ही हफ्ते में लगभग 7 करोड़ का कारोबार किया है, जो अपनी कुल लागत से बहुत कम है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर सनी शर्मा, डायरेक्टर अनीश खन्ना हैं और कलाकारों में राजीव खंडेलवाल के अलावा रायो बख़िरता, नेहा आहूजा, अन्न मिथचई आदि हैं. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

18 नवंबर–24 नवंबर 2013

बिहार–झारखंड

यादवों पर चढ़ा मोदी का रंग

पांच राज्यों के चुनाव के बाद बाबा रामदेव बिहार में कैंप कर यादवों को गोलबंद करने का काम करेंगे. बिहार में वैसे तो हर समाज में रामदेव की पैठ है लेकिन यादवों में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है. बताया जाता है कि रामदेव बिहार में यादव बहुल इलाकों में कैंप लगाकर समाज के लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे. इसकी शुरुआत दिसंबर में पटना या फिर मनेर से होगी.

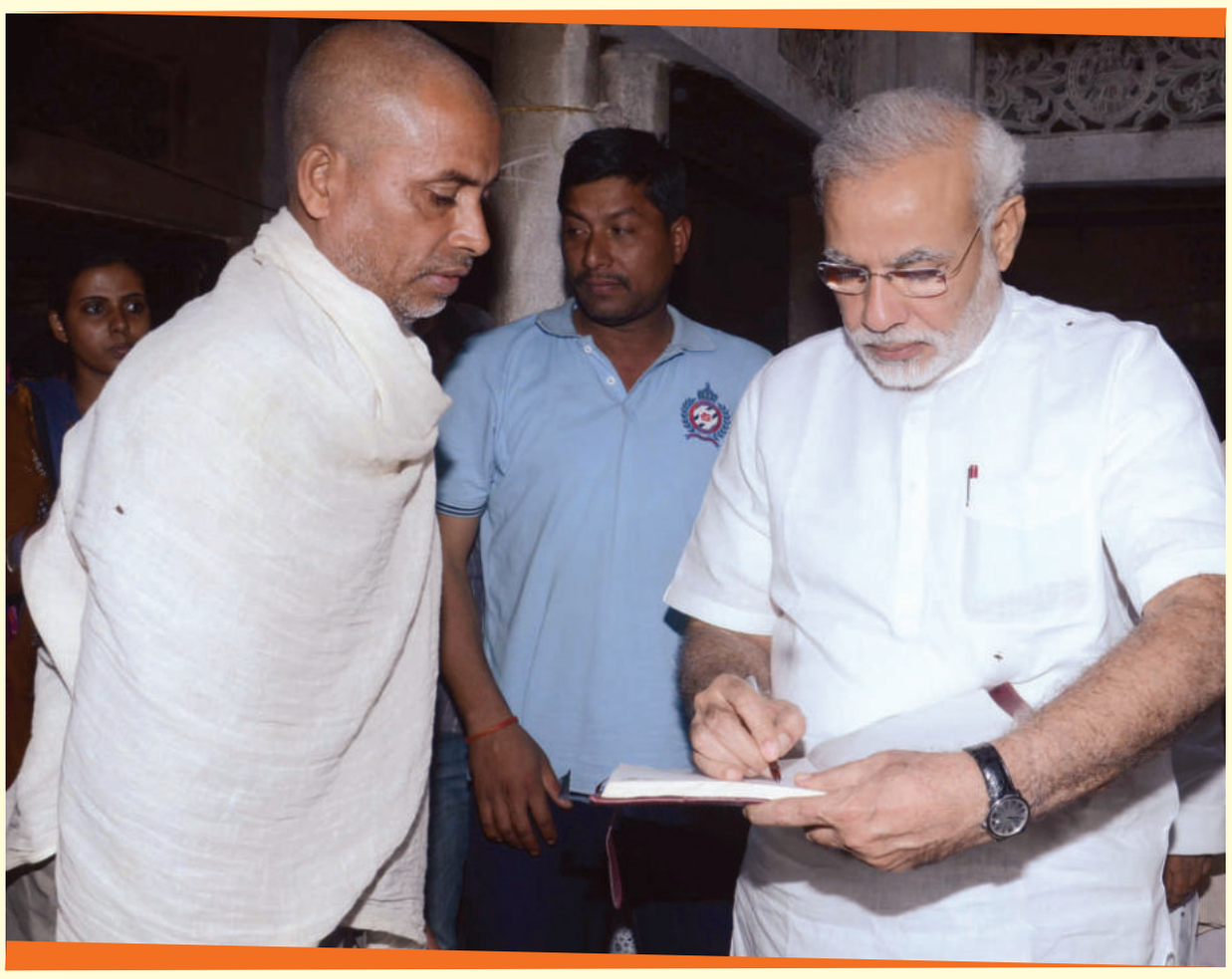

सरोज सिंह

विकास के लाख दावों के बीच बिहार की चुनावी लड़ाई की कड़वी सच्चाई आज भी यही है कि यहां जातीय आधार पर चुनावी बिसात बिछाई जाती है और शह और मात के खेल में बाजी उसी के हाथ लगती है जो जातीय आंकड़ों का ख्याल रख अपनी चाल चलता है. बिहार की चालीस लोकसभा सीटों के लिए नरेंद्र मोदी की रणनीति का लब्बोलुआब भी यही है कि अब तक पार्टी से पूरी या आंशिक तौर पर दूर रही जातियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनका हित भाजपा के साथ रहने में है और नमो नमो का जाप ही उन्हें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सत्ता तक पहुंचा सकता है. इसी कवायद के तहत नरेंद्र मोदी की टीम लालू यादव को कमजोर करने के लिए यादवों को, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए अतिपिछड़ों को और दोनों को एक साथ नुकसान पहुंचाने के लिए उहापोह में फंसे राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है.

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से यदुवंशियों को न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी. नरेंद्र मोदी के यदुवंशियों को दिए न्योते का असर ऐसा हुआ कि पूरे सूबे में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई. दरअसल लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद से ही यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि इतने बड़े यादव वोट बैंक की विरासत को आखिर कौन संभालेगा. लालू के दोनों पुत्रों के बीच आपसी खींचतान और

दल के वरिष्ठ नेताओं के मन में इन शहजादों का नेतृत्व स्वीकार करने की दुविधा ने यादवों के नेतृत्व को लेकर एक शून्य की स्थिति पैदा कर दी. इस शून्य को भरने के लिए सभी दलों ने कोशिश शुरू की पर भाजपा इसमें सबसे आगे निकल गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी पार्टियां केवल कहती रहीं पर भाजपा ने नंदकिशोर यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपने यादव पटाओ अभियान की शुरुआत कर दी. अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाबा रामदेव, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने बिहार की सभी चालीस सीटों के जातीय समीकरण का गहन मंथन शुरू कर दिया. इनमें यादव बहुल इलाकों की सीटों पर खास ध्यान दिया गया. मौटे तौर पर तय हुआ कि लोकसभा की आठ से नौ सीटें यादवों को दिया जाए ताकि इस समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि भाजपा इसके साथ पूरी तरह खड़ी है. गांधी मैदान में युदुवंशियों को नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया न्योता इसी कवायद की कड़ी थी. सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पांच राज्यों के चुनाव के बाद बाबा रामदेव बिहार में कैंप कर यादवों को गोलबंद करने का काम करेंगे. बिहार में वैसे तो हर समाज में रामदेव पैठ है पर यादवों में उनकी के बहुत ही तगड़ी पकड़ है.

बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव बिहार में यादव बहुल इलाकों में कैंप लगाकर समाज के लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे. इसकी शुरुआत दिसंबर में पटना या फिर मनेर से होगी. विधान पार्षद नवल यादव ने बाबा रामदेव की सलाह पर इस मिशन का खाका तैयार किया है. इस दौरान बाबा रामदेव के साथ बिहार के कई दिग्गज यादव नेताओं की मुलाकात होगी. इनमें पूर्व सांसद चुनचुन यादव, रामदेव यादव, बीरबल यादव, विजय यादव, ओमप्रकाश यादव और महेश्वर यादव शामिल हैं. इसके अलावा मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, वैशाली, पटना और नवादा के कई बड़े दिग्गज यादव नेता बाबा रामदेव से मिलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान बाबा रामदेव यादव नेताओं को यह बताएंगे कि इस समाज को अब लालू और नीतीश से आगे देखना चाहिए. नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में यदुवंशियों को लेकर जो वादा किया है उसे वह अंतिम दम तक निभाने को तैयार हैं. इसलिए एक बार यादव समाज को नरेंद्र मोदी को सेवा का मौका जरूर देना चाहिए. यादव बहुल इलाकों में यादव उम्मीदवार का भरोसा भी रामदेव समाज के लोगों को देने वाले हैं. पूरी कोशिश है कि नीतीश सरकार में लगभग हाशिये पर चले गए इस समाज को सत्ता की राजनीति में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भाजपा में दी जाए. बाबा रामदेव, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी ने बिहार में तीस से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. इसलिए इन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय यादव समाज को जोड़े बिना बिहार में उनका मिशन पूरा नहीं होने वाला है. इस तिकड़ी का आंकलन है कि नीतीश कुमार ने यादवों को हाशिये पर धकेल दिया है इसलिए नीतीश कुमार को हाशिये पर धकेलने के लिए लोकसभा चुनाव में यह समाज जरूर भाजपा के साथ जुड़ना चाहेगा. बाबा रामदेव इस मिशन में निकल चुके हैं. बड़े–बड़े यादव नेता बाबा रामदेव के आमंत्रण को हाथों हाथ ले रहे हैं. इसे देखकर लगता है कि बिहार के चुनावी जंग में यादव समाज एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है.■

feedback@chauthiduniya.com

राजपूत और कुशवाहा भी हो रहे गोलबंद

नरेंद्र मोदी की टीम बिहार को लेकर ताबड़तोड़ फैसले बिना समय गंवाए ले रही है. नीतीश सरकार से खार खाए राजपूत व कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बहुत सारे निर्णयों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है. सारण के मजबूत राजपूत नेता तारकेश्वर सिंह को भाजपा में शामिल करने का फैसला किया गया है. तारकेश्वर सिंह महाराजगंज लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरेंगे. गौरतलब है कि हाल ही में यही सीट उपचुनाव में राजद के प्रभुनाथ सिंह ने जीती थी. तारकेश्वर सिंह अपनी जाति के अलावा दूसरे समुदायों में भी खासे लोकप्रिय हैं. सूत्रों पर भरोसा करें तो लवली आनंद और पुतुल सिंह को लेकर भी पार्टी ने फैसला ले लिया है. तारीख की घोषणा जल्द हो सकती है. भाजपा ने तय किया है कि अपने–अपने क्षेत्रों में बड़ी सभा कर ये नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे. बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजकुमार सिंह को भी सुपौल के

लिए टटोला जा रहा है. पटना ब्लास्ट को लेकर राजकुमार सिंह ने बिहार पुलिस की जमकर आलोचना की थी. इसके बाद से ही इस तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा था कि राजकुमार भी नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कर सकते हैं. लेकिन राजकुमार सिंह ने खुद इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं. भाजपा के सूत्र बताते हैं कि राजपूत वोटों को पार्टी के लिए पूरी तरह गोलबंद करने के लिए आठ से नौ टिकट इस जाति से दिए जा सकते हैं. ठीक उसी तरह की कोशिश कुशवाहा वोटों के लिए भी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह अब ठोस आकार लेने लगा है. अभी हाल ही में आयोजित अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी को अतिपिछड़ा का सच्चा नुमांइदा बताते हुए इस समाज से नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं इसलिए उन्हें हर कदम पर दबाने की कोशिश की गई पर यह आप लोगों की ताकत ही थी कि भाजपा को भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा. सूत्रों पर भरोसा करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने एनडीए का घटक बनने का फैसला किया है और इसके लिए पांच सीटों की मांग की है. लेकिन बताया जा रहा है कि तीन सीटों पर लगभग बात बन गई है. जिन पांच सीटों की मांग की गई थी इनमें इजियारपुर, नवादा , सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस आशय की घोषणा हो सकती है. तय किए गए तीनों स्थानों पर बड़ी सभा होगी और इसी में तालमेल का ऐलान किया जाएगा.

भाजपा के रणनीतिकार यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर राजपूत व कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी भाजपा के साथ सौ फीसदी हो गई तो फिर नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार सौ फीसदी सफल रहेगा इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए हर दिल को टटोला जा रहा है और राजनीतिक हैसियत के हिसाब से उससे बात भी की जा रही है. अंदरखाने जो प्रयास चल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं.■

» एक नज़र «

कलकत्ता बाजार शुरू

सीतामढ़ी शहर के सिनेमा रोड में पिछले दिनों सूबे के पूर्व पर्यटन मंत्री व नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने कलकत्ता बाजार का फीता काट कर उद्घाटन किया. मौके पर पिंटू ने कहा कि जिलावासियों के लिए बाजार पर्व के मौके पर उपहार है. कहा कि सभी प्रकार की जरूरत का सामान लोगों को बाजार में उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रसाद सर्राफ, अनिल कुमार मंटू, मंजू देवी, प्रमोद सर्राफ, कैलाश कुमार हिसारिया, संतोष कुमार सर्राफ, आतिश शंकर, राजू पाल, विश्वनाथ सिंह, संजीव कुमार समेत अन्य मौजूद थे. **– ब्रजेश कुमार**

इंदिरा गांधी को नमन

जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित आश्रम में सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की 29 वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138 वीं जयंती भी मनाई. मौके पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, उपाध्यक्ष सीताराम झा, अमित कुमार टुन्ना, सत्येंद्र कुमार तिवारी, डॉ.भुवनेश्वरी मिश्र, मो. परवेज आलम, मो. असद, विजेंद्र यादव, रामबली महतो, महेश मांझी, रंधीर प्रसाद सिंह, सीमा गुप्ता, वीरेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश, मणी भूषण, महेश्वर गिरी, ताराकांत झा, मोबिनुल हक, मंजू कुमारी समेत अन्य ने दोनों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. **– वाल्मीकी प्रसाद**

धरना आयोजित

गन्ना किसानों की समस्या का निदान एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. पिछले दिनों रीगा में गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान समेत 6 सूत्री मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. रीगा मिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शिवहर की भाजपा सांसद रमा देवी व रीगा विधायक मोतिलाल प्रसाद ने भी भाग लिया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने किसानों की समस्या का निदान नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी. मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पारसनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. आनंद किशोर, जिलाध्यक्ष राम तपन सिंह, रमेश प्रसाद, रंधीर प्रसाद सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार, करुण कुमार, नंद किशोर सिंह, विजय कुमार सिंह, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर, चंदेश्वर नारायण सिंह, चंदेश्वर पूर्वे, संजय कुमार, प्रो. त्रिपुरारी मोहन शर्मा, रामेश्वर प्रसाद, विजय कुमार सिंह व कौशल किशोर सिंह समेत अन्य मौजूद थे. **– नीरज**

पूर्वी चम्पारण के समस्त नागरिकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व अधिवक्ताओं को लोक आस्था का महापर्व छठ व गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं
Enjoy with Nature MOULDED FURNITURE NATURE 1 YEAR GUARANTY Contact : 9386595926, 9334115955
गर्भावस्था में रखें पोषण का ध्यान ariskon Pharma Pvt.Ltd. ACOBA CAP/SYP/INJ Carbo-XT AREX ASRFEN-P ECTALOPAM SILIPLEX NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma
समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

राजनीति का अखाड़ा बनी जमुई जिला परिषद

राजेश/मनोज

जिला परिषद जमुई लगातार चर्चा में रही है. लेकिन फिलहाल मामला यह है कि जिला परिषद जमुई ऐसे भंवर जाल में फंस गई है कि यहां से त्रिस्तरीय पंचायती राज के सपने का पूरा होना मुश्किल ही लग रहा है. यहां के पार्षदों के बीच नूरा–कुश्ती का खेल लगातार चलता रहा है. इसी खेल की वजह से ब्रह्मदेव रावत की लालबत्ती भी छिन गई.

लालबत्ती छिनने के बाद रावत चैन से बैठे नहीं. इन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक मामला दायर किया कि अविष्वास प्रस्ताव के दौरान किये गये वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है. रावत का कहना है कि वोटिंग में सदस्यों द्वारा टिक मार्क का प्रयोग किया जाना था जिसे प्रचारित–प्रसारित भी किया गया था. लेकिन ऐन वक्त पर वोटिंग का तरीका सदन में बदल दिया गया और क्रॉस वोटिंग प्रणाली अपनाई गई. उनका आरोप है कि 20 सदस्यों वाले इस सदन में दर्जन भर महिलाएं हैं जिन्हें इस बदले हुए पैटर्न को समझने में दिक्कत हुई और रिजल्ट उनके खिलाफ चला गया. हाईकोर्ट ने वादी की इस दलील सीडब्लूजेसी सं. 18029/2013 के आलोक में आईए नम्बर 6553/2013 के तहत जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु आयोजित की जानेवाली 18 सितम्बर 2013 की बैठक को स्थगित कर दिया.

बैठक स्थगन के बाद उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बतौर कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से उप विकास आयुक्त को दो बार पत्र लिखकर जिला परिषद की सामान्य बैठक आहूत किए जाने का अनुरोध किया. लेकिन डीडीसी देवेंद्र कुमार सविता को इस संवैधानिक सच की जानकारी नहीं है कि जिला परिषद की सामान्य बैठक तीन महीने में बुलाई जानी चाहिए. पिछली बैठक के 6 महीने हो गए हैं. इस मामले में डीडीसी के खिलाफ अधिकांश जिप सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है. कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र यादव का कहना है कि बैठक नहीं बुलाया जाना डीडीसी की मनमानी को दर्शाता है. पिछले 6 महीनों से जिप की बैठक नहीं होने से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी तरह बाधित है. नौकरशाहों के रवैये से लगता है कि 36 विभागों की समीक्षा करनेवाले इस सदन को शक्तिहीन बनाने की कोशिश की जा रही है.

जिले की तमाम विकास योजनाओं के कैनवास पर स्वीकृति के रंग यहां भरे जाते हैं. जिप की बैठक को बाधित रखने के पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश की भी बात सामने आ रही है. इसके बारे में डीडीसी श्री सविता ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव से पहले बैठक बुलाई गई थी. फिलहाल अध्यक्ष नहीं हैं और न ही कोई एजेंडा है. उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है. अगले महीने जिप सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी. फिलहाल जिप की बैठक स्थगित रखने तथा निर्वतमान अध्यक्ष ब्रह्मदेव रावत द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर किए जाने को पूरी तरह जनता के खिलाफ बताते हुए जिप अध्यक्ष के दावेदार विकास प्रसाद सिंह बताते हैं कि सभी सदस्यों द्वारा मिल–बैठकर जिप अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा. पूर्व अध्यक्ष ने सदन के साथ विश्वासघात किया तो उनकी कुर्सी गई, लेकिन जिले की जनता की बेहतरी के लिए जिप अध्यक्ष पद पर कोई अच्छा व्यक्ति ही चुना जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का चुनाव करना सदस्यों का कार्य है. इस मामले में किसी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए और न ही राजनीतिक हस्तक्षेप की यहां कोई जगह है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चलाचली की बेला में हरिहर क्षेत्र का मेला

सुनील सौरभ

भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराएं हमेशा से पश्चिमी देशों के लिए कौतुहल का विषय रहे हैं. यह देखा जा रहा है कि पाश्चात्य देशों का आकर्षण भारतीय संस्कृति की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन धीरे–धीरे हमारे लोक उत्सव और हमारी परंपराएं भी आधुनिकता की भेंट चढ़ने लगे हैं. कुछ इसी प्रकार हरिहर क्षेत्र का मेला भी धीरे–धीरे आधुनिकता की भेंट चढ़ रहा है. इसे सोनपुर मेला, छतर मेला या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है. प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक माह तक लगने वाले इस मेले को कथित विकास और बदलाव की बयार का शिकार होना पड़ा है. इस मेले मे जाने के लिए लोग महीने पूर्व तैयारी शुरू कर दिया करते थे और राज्य सरकार के महकमे और आयोजनकर्ताओं को छह माह पहले से ही काफी कसरत करनी पड़ती थी. लेकिन आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है. मेले के सरकारी–गैरसरकारी समारोह और आयोजनों की तैयारी को देखकर लगता है कि महज खानापूर्ति की जा रही है. आज सोनपुर मेले में भारतीय संस्कृति, संस्कार, लोक कथाएं, लोक उत्सव से जुड़ी चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती है. ऐसा लगता है जैसे इस मेले पर भी आधुनिकता का आवरण चढ़ा दिया गया हो. कभी इस मेले में लोक और उससे जुड़ी परंपराओं का ही ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब स्थिति भिन्न है. अब तो लोक नाटक, लोक संगीत की मंडली इस आयोजन में दिखती ही नहीं है. लोक कलाकारों का स्थान अब ऑर्केस्ट्रा ने लिया है. यह भी बताते चलें कि ऑर्केस्ट्रा और थियेटर के जरिये अश्लीलता परोसने की सारी हदें पार कर दी जाती हैं. यही वजह है कि धीरे–धीरे इस मेले का आकर्षण कम होते जा रहा है.

इस मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है. कभी यहां सभी प्रकार के पशुओं की खरीद–ब्रिकी के लिए सिर्फ राज्य के ही नहीं देश के कोने–कोने से लोग आते थे. इस मेले की खास बात यह है कि यहां गाय–बैल, हाथी, घोड़े तथा अन्य जानवरों के लिए अलग–अलग स्थान निर्धारित हैं. लेकिन अब इस मेले में जानवरों का आना भी कम हो गया है. सबसे बड़े पशु मेले में पशुओं की जगह अब ट्रैक्टर व पावर टिलर के शो रूम नजर आते हैं. पहले मेले में हाथियों की बड़ी संख्या रहती थी, घोड़ों की विभिन्न नस्लें यहां मिल जाती थी. लेकिन अब न तो राजस्थान की बकरियां रहती हैं और न ही काबूल के घोड़े. असम के हाथी पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया है. बताया जाता है कि पहले मेला क्षेत्र के एक–एक इंच पर दुकानें सजी रहती थीं लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है. अब इस मेले मे भूमि को नीलाम किया जाता है. ठेकेदार अधिक से अधिक कमाने के लिए किराया अधिक वसूलते हैं. यही कारण है कि मेला क्षेत्र पूरी तरह

भर भी नहीं पाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पौराणिक मेले में लोग स्नान करने भी आते हैं. परन्तु गंगा व गंडक नदी के तटों पर समुचित घाटों का निर्माण तक नहीं कराया जा सका है.

सोनपुर मेले का प्रारंभ कब हुआ, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. लेकिन विभिन्न जनकथाओं एवं धार्मिक विश्वास के अनुसार यह उत्सव पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है. इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व कहीं से भी कम नहीं है. पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में हरिहर क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि गंगा और गंडक दोनों पुण्यदायिनी धाराओं का अविरल प्रभाव लोक ही नहीं परलोक में भी सब सुख देने वाला है. इस बारे में राजा पृथु से नारद ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर मनुष्य अवश्य पुण्य का भागी होता है. उसी के मध्य हरिहर नामक क्षेत्र है. जहां स्नान कर और जल पीकर मनुष्य नारायण तुल्य हो जाता है. इसी तरह कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में हरिहर क्षेत्र के मेले की चर्चा मिलती है. धार्मिक आख्यानों के अलावा यह भी निर्विवाद तथ्य है कि कालान्तर में देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां लगातार विकसित होती गईं. लेकिन आज इस विश्वविख्यात मेले के अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में काफी बदलाव आ गया है. मेले में पहले ईमानदारी होती थी, सेवा भाव होता था, लोक की भावनाओं के अनुरूप इसका आयोजन होता था. लेकिन पिछले ढाई तीन दशक से हरिहर क्षेत्र मेले का स्वरुप और इसकी मूल भावना ही विकृत हो गई है. हर कोई इस मेले में अधिक से अधिक कमाने और लूटने की होड़ में लगा नजर आता है. यही कारण था कि नब्बे के दशक के आरंभ में 'अश्लील कैबरे' का अयोजन इस मेले में होने लगा. तब बहुत हंगामा हुआ था. बाद में जिला प्रशासन को कैबरे पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था. लेकिन आज भी मेले में लगने वाले थियेटर में किसी न किसी रूप में 'अश्लील कैबरे' का दृश्य दिखाया जाता है. सड़कों की सफाई, जल–छिड़काव के साथ–साथ मेले में शौचालय–मूत्रालय की व्यवस्था की भी खानापूर्ति ही की जाती है. सच कहा जाए तो स्वर्णिम अतीत वाले सोनपुर मेले के दुखद वर्तमान के लिए सरकार और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है. विश्व प्रसिद्ध इस मेले को आज तक भारतीय व्यापार मेला या भारतीय मेला विकास प्राधिकारण से नहीं जोड़ा जा सका है. लेकिन हर वर्ष इस मेले के उद्घाटन और समापन पर सफेदपोशों की ओर से लम्बे चौड़े वादे किए जाते हैं. लेकिन इस पर अमल आज तक नहीं हुआ है. आज भी इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में नब्बे फीसदी ग्रामीण क्षेत्र के ही होते है. जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है. धर्मपरायण लोग कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व चतुर्दशी से ही सोनपुर और हाजीपुर में गंगा–गंडक नदी के संगम स्थित घाटों पर डेरा डाल देते हैं. प्रसिद्ध कोनहरा घाट से लेकर नेपाली मंदिर और पूल घाट तक मेले में भारतीय ग्रामीण संस्कृति का अद्भूत नजारा थोड़ा बहुत अब भी देखने को मिलता है. मेले के आसपास मिथिलांचल और बज्जिकांचल की महिलाएं समुह में 'गंगा मैय्या' का गीत गाती नजर आती हैं तो कहीं ढोल व मांदर की थाप पर झूमते लोग, कहीं टोना–टोटका करते ओझा–गुनी खुद में व्यस्त नजर आते हैं. बाजार के हावी होने के बाद भी लोकपरंपराएं कहीं–कहीं दिख जाती हैं. 'जट–जटिन', 'सामाचकेवा' जैसी नृत्य नाटिका आज भी मेले में आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. अर्थ की बढ़ती प्रधानता के बीच बदलते परिवेश और उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच भी इस मेले का पारंपरिक ग्रामीण परिदृश्य आज भी देखने को मिलता है. यही इस मेले की सार्थकता और आकर्षण है. लेकिन जिस तरह से मेले पर बाजार हावी हो रहा है ऐसा लगता है कि लोक परंपराएं ज्यादा दिन तक यहां टिक नहीं पाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजद नेताओं ने भरी हुंकार

नन्द किशोर शर्मा

[illegible]

feedback@chauthiduniya.com

लखीसराय में कमर कस तैयार है राजद

सीतेश सुधांशु

बहुचर्चित चारा घोटाला में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली कैद से लखीसराय जिले में राजद कार्यकर्ताओं के बीच बेचैनी बढ़ सी गई है. उनके अंदर ही अंदर उबाल उमड़ रहा है. राजद कार्यकर्ताओं व समर्थकों के बीच यह चर्चा आम है कि लालू प्रसाद यादव को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. कभी यहां राजद की तूती बोलती थी, लेकिन वर्तमान में बोलती बंद हो गई है. एक समय था कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र क्रमश: लखीसराय व सूर्यगढ़ा में से एक पर राजद का कब्जा रहता था. लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलीं कि दोनों जगह पर एक साथ भाजपा काबिज है. हालांकि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की स्थिति परिवर्तनशील रही है और इतिहास बताता है कि जनता ने जिस व्यक्ति को नकार दिया वह दोबारा स्वीकार नहीं किया गया.

सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राजद का एकछत्र राज हुआ करता था. इस विधानसभा क्षेत्र के चानन अंचल में तो राजद की तूती बोलती थी और इस क्षेत्र की जनता हमेशा राजद के पक्ष में बहुमत से खड़ी रही है. लेकिन वर्तमान में यह तिलिस्म भी टूट सा गया है. 1995 में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रहलाद यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगाड़े की चोट पर विधायक बने और राजद में शरण लेने के बाद से राजद के टिकट से ही चुनाव लड़ते रहे. 1995 से लेकर 2005 तक लगातार तीन बार जीत हासिल करने वाले श्री यादव 2006 के उपचुनाव में नीतीश की लहर में काफी कम मतों के अंतर से जीतते–जीतते हार गए. बताया जाता है कि इसमें चानन की जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. तब से लेकर दो बार लगातार काफी मतों के अंतर यादव चुनाव हार चुके हैं. लोगों की माने तो उनकी हार अपनों के कारण ही हुई क्योंकि उनके कार्यकर्ता बेलगाम हो चुके थे, जो आम जनता के आंखों की किरकिरी बने हुए थे. जनता को निष्पक्ष व स्वच्छ मताधिकार का मौका मिला तो उसने यादव को चारो खाने चित कर दिया और बाहरी व्यक्ति के रूप में भाजपा उम्मीदवार प्रेमरंजन पटेल सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए. वहीं दूसरी तरफ लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में नीतीश की लहर के बावजूद 2006 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा काफी कम मतों के अंतर से राजद के फूलैना सिंह से हार गए. बावजूद इसके वे जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे और इसी सक्रियता की वजह से 2010 के चुनाव में काफी अधिक मतों के अंतर से उन्होंने विजयश्री हासिल की. 2010 में चुनाव हार जाने पर कुछ समय तक राजनीति से तौबा करने वाले फूलैना सिंह वर्तमान में सक्रिय हो चुके हैं.

लालू प्रसाद यादव को मिली सजा के मामले में राजद जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव कहते है कि यह संकट की घड़ी है तथा अभी हमारे संयम की परीक्षा है. इससे पहले भी कई आफत आईं लेकिन कार्यकर्ताओं ने मनोबल नहीं तोड़ा जिस कारण पार्टी सुप्रीमो को बल मिला. आज भी जरूरत है कि राजद के सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी से काम करें तो उनकी जीत हो सकती है. वहीं दूसरी ओर राजद नेता व पूर्व विधायक फुलैना सिंह को लालू प्रसाद की सजा में षड़यंत्र भी नजर आता है. वे कहते हैं कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया गया है. सच तो यह है कि

फुलेना सिंह

प्रहलाद यादव

लालू प्रसाद यादव को मिली सजा के मामले में राजद जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव कहते है कि यह संकट की घड़ी है तथा अभी हमारे संयम की परीक्षा है. इससे पहले भी कई आफत आईं लेकिन कार्यकर्ताओं ने मनोबल नहीं तोड़ा जिस कारण पार्टी सुप्रीमो को बल मिला. आज भी जरूरत है कि राजद के सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी से काम करें तो उनकी जीत हो सकती है.

मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद ने ही चारा घोटाले को उजागर किया. सीबीआई कोर्ट के जज जदयू के एक मंत्री के संबंधी हैं. लालू यादव ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी, बावजूद इसके जज को बदला नहीं गया और साजिश के तहत लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया. इस षड़यंत्र का खुलासा शीघ्र ही हो जाएगा. वर्तमान समय में राजद के बीच अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही है. इसी कारण से कार्यकताओं को संयम व धैर्य की नसीहत दी जा रही है. राजद नेतृत्व सही समय पर जबाव देने का इंतजार कर रहा है. लेकिन इस सही समय के लिए राजद को काफी मशक्कत भी करनी होगी क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं के बीच फूट की स्थिति है और विगत आठ वर्षो से सत्ता से दूर रहने के कारण अन्यत्र जाने की स्थिति में हैं. कई कार्यकर्ता तो जदयू और भाजपा के सदस्य बन भी चुके हैं तो कई बनने वाले हैं. हालांकि इनमें अधिकतर अभिकर्ता किस्म के हैं जो सत्ता पक्ष के साथ रहकर कुछ कमाने की फिराक में लगे रहते हैं. वर्तमान समय में राजद के लिए संकट की घड़ी है. जानकार बताते हैं कि विकट स्थिती के बाद भी राजद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय रहे हैं. हां बिमारी के दिनों में थोड़े कम सक्रिय जरूर थे. जिलाध्यक्ष की महत्ता पिछले दिनों हुए राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई पर चुका है. सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने काफी इत्साह के साथ भाग लिया था.

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समय में लखीसराय जिला परिषद पर प्रहलाद यादव का ही कब्जा है. वजह यह कि उनकी पत्नी सुदामा देवी परिषद की अध्यक्ष हैं. आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राजद दमदार उपस्थिती दर्ज कराएगी, यह अभी से ही दिख रहा है. धीरे–धीरे राजद के कार्यकर्ता गोलबंद हो रहे हैं व अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाने को बेताब हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतर्कलह और सवर्णों के बीच फंसी भाजपा

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले में भी राजनीति का खेल जातिगत समीकरणों के अखाड़े में ही होता आया है. नतीजा है कि आजादी के बाद से अब तक सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एक भी सवर्ण भाजपा की टिकट से संसद नहीं पहुंच सका है. जबकि सभी चुनावों में सवर्ण मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है. 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर एक खास तबका जिले में सवर्ण मतदाताओं को गोलबंद कर चुनावी अखाड़े में कूदने की कोशिश करता दिख रहा है.

बिहार के तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिले का अंग रहा सीतामढ़ी, वर्ष 1972 में स्वतंत्र जिला घोषित हुआ. इससे पहले तक यह पुपरी लोकसभा सीट का ही भाग हुआ करता था. यहां से तकरीबन 17 साल तक कांग्रेस के नागेंद्र प्रसाद यादव सांसद निर्वाचित होते रहे. 1972 में स्वतंत्र जिला का दर्जा मिलने के बाद पहली बार 1977 में सीतामढ़ी जिले में लोकसभा का चुनाव हुआ था. तब जनता पार्टी के टिकट पर महंत श्याम सुंदर दास बतौर सांसद निर्वाचित हुए थे. 1980 में कांग्रेस से बलिराम भगत तो 1984 में कांग्रेस की टिकट पर ही राम श्रेष्ठ खिरहर सांसद बने थे. 1989 में जनता दल के टिकट पर हुकुमदेव नारायण यादव तो 1991 एवं 96 में जनता दल से ही नवल किशोर राय ने संसद तक का सफर तय किया था. वर्ष 1998 के चुनाव में राजद प्रत्याशी रहे सीताराम यादव ने नवल किशोर राय को चुनावी दंगल में शिकस्त देकर संसद में दस्तक दी थी. लेकिन 1999 के चुनाव में एकबार फिर जनता दल की टिकट से चुनावी अखाड़ा में दमखम से इतरे नवल किशोर राय ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली. लेकिन 2004 के चुनाव में राजद के सीताराम यादव एक बार फिर से नवल किशोर राय को पटकनी देने में कामयाब रहे, और वे चुनाव जीत गये. सूबे में आयी राजनीतिक इथल–पुथल का नतीजा हुआ कि जनता दल यू के प्रत्याशी अर्जुन राय ने राजद के सीताराम यादव को किनारा कर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रहे. इन चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अब तक सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार संसद तक का सफर तय करने वालों में यादव बिरादरी ही रही है. तकरीबन 13 लाख मतदाताओं वालों इस संसदीय क्षेत्र में अल्पसंयख्क मतदाताओं की संख्या भी यादव मतदाताओं की संख्या से मामूली अंतर पर ही है. यादव सवा 3 लाख तो अल्पसंख्यक मतदाता पौने 3 लाख के करीब बताए जाते हैं. मतों के हिसाब से तीसरे स्थान पर रहने वाली भुमिहार जाति का भी तकरीबन ढाई लाख से कुछ अधिक तो ब्रहमणों का भी लगभग सवा लाख वोट है. राजपूत एवं कायस्थ के मतों को

डॉ बसंत कुमार मिश्रा

डॉ बलवंत शास्त्री

प्रो वीरेंद्र प्रसाद सिंह

सुफल झा

अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या करीब सवा 2 लाख की संख्या हो सकती है.

जहां तक भाजपा नेतृत्व का सवाल है, ऐसा नहीं है कि पार्टी ने सवर्ण को बतौर प्रत्याशी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में नहीं उतारा. लेकिन दूसरी बिरादरी की तरफ से समर्थन नहीं मिलने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 1980 में डा. रामकृपाल सिंह ने पहली बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाया था, तब उन्हे महज 40 हजार मत ही मिले थे. 1984 के चुनाव में प्रो. ठाकुर प्रसाद सिंह भाजपा की ओर से बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए थे. इस समय मतों में इजाफा हुआ था और उन्हें करीब 1 लाख 10 हजार मत मिले थे. वर्ष 1991 के चुनाव में डा. वसंत कुमार मिश्रा को भाजपा नेतृत्व ने उनकी कुशल राजनीतिक क्षमता को देखते हुए चुनावी समर में उतारा था. मगर ऐन मौके पर राजद के लालू प्रसाद यादव की तेज आंधी ने उनको महज 44 हजार मतों पर ही अटका कर रख दिया.

लगातार चुनाव में मिल रही शिकस्त से हलकान भाजपा नेतृत्व ने वर्ष 1996 के चुनाव में वैश्य बिरादरी के उमा शंकर गुप्ता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था. लेकिन उनकों करीब 85 हजार मतों से ही संतोष करना पड़ा. उसके बाद भाजपा नेतृत्व ने पूर्वी चंपारण से भूमिहार बिरादरी के अवनीश कुमार सिंह को सीतामढ़ी से टिकट देकर मैदान में उतारा. उनके समय में बहुत हद तक जिले में भाजपा एवं सवर्ण मतों का ध्रुवीकरण हुआ. वे भाजपा के अब तक के तमाम प्रत्याशियों के रिकार्ड को ध्वस्त करते हुए 2 लाख 32 हजार मत लाने में कामयाब रहे. परंतु नतीजा पराजय के रूप में ही सामने आया. लेकिन जिले में भाजपा की लहर ने जोर जरूर पकड़ी. इसी बीच बिहार की राजनीति ने करवट लेना शुरू किया और भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट से अपनी नजर टेढ़ी कर ली. बाद में बिहार में हुए राजग गठबंधन के तहत जदयू ने भाजपा को किनारे कर अपना किला बुलंद कर लिया. राजनैतिक प्रेक्षकों की मानें तो अगर सवर्ण मतदाता एक मंच पर आ जाते हैं तो सीतामढ़ी संसदीय सीट पर इनके कब्जे की संभावना प्रबल हो जाती है. कारण कि ऐसे हालात में अन्य वर्गों का भी कुछ न कुछ सहयोग की उम्मीद की जाती है. संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में सवर्ण मोर्चा का गठन कर सफलता को लेकर अभियान का शुभारंभ भी हो जाए. इन सब के बीच सीतामढ़ी जिले में नमो मिशन 2014 की सफलता को लेकर जहां एक ओर भाजपा मजबूती का दावा कर रही है. वही दूसरी ओर जिले में एक खास वर्ग के वर्चस्व के कारण पार्टी के अंदर अंतकर्लह में लगातार हो रहे इजाफे के कारण सफलता पर ग्रहण लगता दिख रहा है. भले ही पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अंतकर्लह की बात को नकार दें, लेकिन सच्चाई है कि जिला संगठन कई खेमे में विभक्त हो चुका है. वहीं पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई भाजयुमो का अंतकर्लह भी वर्तमान जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर चरम पर है. चर्चाओं पर यकीन करे तो युवा मोर्चा के अधिकांश कार्यकर्ता वर्तमान जिलाध्यक्ष कार्तिकेश झा के खिलाफ अघोषित रूप से मोर्चा खोल चुके हैं. इसके साथ ही सूबे में नव गठित फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी के बैनर तले युवा कार्यकर्ता पार्टी संगठन के हित में जोरदार तैयारी करने की ठानी है. अगर चर्चाओं में तनिक भी सच्चाई है तो जिला भाजपा को कठिन चुनौती के बीच से होकर गुजरना होगा. दूसरी ओर भाजपा के टिकट पर सवर्ण प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर चल रही मुहिम अगर जोर पकड़ती है तो संभव है कि पार्टी संगठन की मुसीबत में और भी इजाफा हो सकता है. हाल ही में भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य डा. बलवंत शास्त्री ने पटना में हुंकार रैली को लेकर सीतामढ़ी व शिवहर जिले में जनसंपर्क अभियान चलाया था. इस दौरान दोनों ही जिले में सवर्ण मतदाताओं ने अपनी भावना से श्री शास्त्री को अवगत कराते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी व शिवहर संसदीय सीट पर सवर्ण भाजपा प्रत्याशी को लाने को कहा है. डा. शास्त्री की माने तो मतदाताओं ने अपनी भावना से अवगत कराते हुए यह भी कहा कि अब तक अन्य बिरादरी को सवर्णों का मत मिलता रहा है. एक बार ईमानदार समर्थन सवर्णों को भी मिलना चाहिए. संभव है कि आगामी चुनाव में सवर्ण भाजपा प्रत्याशी की मांग दोनों ही जिले के लिए किया जा सकता है. ऐसा होता है तो सीतामढ़ी लोकसभा सीट से पूर्व में पार्टी के टिकट पर भाग्य आजमा चुके डा. बसंत कुमार मिश्रा के अलावा डा. बलवंत शास्त्री, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णमोहन सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी सुफल झा एवं प्रो. वीरेंद्र प्रसाद सिंह समेत अन्य प्रवल दावेदार हो सकते हैं. वजह यह है कि भाजपा संगठन में उक्त लोगों की भूमिका अब तक महत्व–पूर्ण बताई जाती है. वैसे चुनाव में अभी वक्त काफी है. परंतु भाजपा के जिला संगठन में अगर जातीय आधार पर पार्टी से टिकट की मांग की जाती है तो पार्टी को एक साथ कई मोर्चे पर मुकाबला करने को मजबूर होना पड़ेगा. एक ओर गठबंधन टूटने के बाद जदयू से भाजपा की आमने–सामने की भिड़ंत शुरू हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर भाजपा के पुराने राजनीतिक विरोधी राजद ने भी लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद भाजपा को टारगेट कर लिया है. अब यह तो समय ही बताएगा कि जिले में पार्टी के अंदर सवर्णों की मुहिम जोर पकड़ती है अथवा मांग रहा है हिंदोस्तान, लाल किले पर कमल निशान का नारा एकजुटता का स्वर गाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

शो रूम का उद्घाटन

भारत–नेपाल सीमा पर स्थित बैरगनिया बाजार के मुख्य पथ स्थित पूजा मार्केट में स्थानीय भाजपा विधायक मोतिलाल प्रसाद ने जॉन हिल नामक एक्सक्लूसिव शो रूम का उद्घाटन फीता काट कर किया. मौके पर शो रूम के व्यवस्थापक विनय रंजन, नगर पंचायत अध्यक्ष वशीर आलम, वार्ड पार्षद शंभू प्रसाद कानू, दीपलाल बघेला, जमीरी लाल साह, राजीव गौतम, मुखिया मो. हारिश, प्रमुख नीलम जायसवाल, थानाध्यक्ष रीता कुमारी समेत अन्य मौजूद थे. **– विनोद कुमार**

बांध काटा

सैकडों एकड़ जमीन में जल जमाव की समस्या से आम लोगों को निजात दिलाने को लेकर बेलसंड की जदयू विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति व जदयू किसान सेल के उपाध्यक्ष राणा रंधीर सिंह चौहान ने बांध काट कर पानी की निकासी का मार्ग प्रशस्त किया. समस्या को गंभीरता से लेते हुए श्री चौहान ने कई बार स्थानीय प्रशासन से भी इस मामले में पहल का आग्रह किया था. परंतु विलंब होने के साथ ही लोगों की बढ़ रही परेशानी को लेकर पिछले दिनों खुद ही कुदाल थाम ली. मौके पर दर्जनों स्थानीय लोग भी मौजूद थे.

वैष्णव सम्मेलन

सनातन धर्म पर मंथन के लिए बक्सर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वैष्णव सम्मेलन में प्रख्यात संतों तथा धर्माचार्यो ने सनातन धर्म को ही मानव जीवन की आचार संहिता बताया. श्री त्रिदण्डी स्वामी के शिष्य श्रीलक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी द्वारा आयोजित यह सम्मेलन पूरी तरह आध्यात्मिक था. वैष्णव सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश के कोने–कोने से धर्माचार्य तथा पीठाधीश्वर आए हुए थे. इसे देखने–सुनने के लिए लाखों लोगों का जनसैलाब भी उमड़ा, बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों का भी आना हुआ। देश में धर्म को नकारने की बढ़ती प्रवृति पर विद्वान संतों ने कहा कि धर्मविहीन समाज तथा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। सम्मेलन का उद्घाटन लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी ने किया। अध्यक्षता कांचीपुरम के पीठाधीश्वर श्री अनन्ताचार्यजी महाराज तथा संचालन अयोध्या के पीठाधीश्वर इसमें हनुमानगढ़ी अयोध्या के महामण्डलेश्वर धर्मदासजी महाराज, वृदांवन के डॉ. श्याम सुंदर परासर, पीठाधीश्वर राजनारायणाचार्य, मारुति किंकरजी महाराज, पुष्कर के रामचन्द्रजी महाराज, स्वामी राघवाचार्य, स्वामी बालकजी महाराज, स्वामी लक्ष्मणाचार्य आदि बड़ी संख्या में संतों ने भाग लिया। अंत में जीयर स्वामी को वैष्णव सम्प्रदाय का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। **– जयमंगल पाण्डेय**

कायम है तौजी की परम्परा

डुमरांव राज घराने द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तौजी की प्राचीन परम्परा का आयोजन कर जनता की सुख–शांति की कामना की गई। राजतंत्र शासन व्यवस्था के समय से चली आ रही तौजी की परम्–परा आज भी कायम है। तब राज परिवार विजयादशमी के दिन तौजी पूजा का आयोजन कर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया करता था। डुमरांव महाराज तथा पूर्व सांसद कमल सिंह आज भी इस परम्परा का निर्वहन करते हैं। अस्वस्थता के कारण इस बार महाराज नहीं आए। लेकिन युवराज चन्द्र विजय सिंह राजसी ठाठ–बाट के साथ दशहरा के दिन राजगढ़ पहुंचे। उनके कुल पुरोहित बलिराम मिश्र ने वैदिक विधि–विधान के साथ गढ़ में स्थित प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में विभिन्न देवी–देवताओं का पूजन कराया। इसके बाद परम्परागत अस्त्र–शस्त्रों की भी पूजा की गई। इसके बाद नगर में जुलूस भी निकाला गया। जिसमें गणमान्य लोगों ने भाग लिया। **– जयमंगल पाण्डेय**

मुखिया पति का बोलबाला

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों या उनके पुरुष रिश्तेदारों का ही बोलबाला रहता है. ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों हंटरगंज प्रखंड में देखने को मिला. कोशमा पंचायत की मुखिया सरिता देवी इनदिनों रबर स्टाम्प बनकर रह गई हैं. कहा जाता है कि सरिता के पति ही मुखिया का सारा काम निपटाते हैं. यही वजह है कि पिछले दिनों उप मुखिया रीना देवी के नेतृत्व में वार्ड सदस्यों ने मुखिया और उनके पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इस क्रम में ग्यारह में से नौ वार्ड सदस्यों ने मुखिया की वित्तीय शक्ति को निरस्त करने संबंधी आवेदन पर हस्ताक्षर कर चतरा के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष और बीडीओ को सौंप दिया है. उपायुक्त ने बीडीओ से जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

माफिया गिरतार

चतरा उपायुक्त हंसराज सिंह ने राज्य खाद्य निगम के दस हजार क्विंटल खाद्यान्न की हेराफेरी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में खाद्य निगम के गोदाम प्रभारी महेंद्र कुमार, परिवहन अभिकर्ता संजय प्रसाद व बृज भूषण प्रसाद शामिल हैं. उपायुक्त के आदेश के बाद सदर एमओ रामबहादुर सिंह ने सदर थाने में प्राथमीकि दर्ज कराई है. एमओ ने बताया कि खाद्यानों का उठाव कोडरमा से किया जाता है. जिले के लिए प्रति माह इक्तीस हजार क्विंटल खाद्यान आवंटित है, जिसके तहत सितंबर माह के चावल का उठाव तो किया गया लेकिन सिमरिया, हंटरगंज व प्रतापपुर के प्रखंडों के गोदामों में करीब दस हजार क्विंटल खाद्यान अबतक नहीं पहुंचाया गया है. **– अमरेंद्र प्रताप सिंह**

नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला यह समाज इस मोड़ पर आ जाएगा और सुशासन की पोल खोलने के लिए सड़क पर उतर जाएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था. विश्वकर्मा समाज द्वारा हाल ही में मोतिहारी के नगर भवन में आयोजित सम्मेलन में उमड़ी लोगों की भीड़ ने भी इसे और पुख्ता किया

नीतीश की परेशानी बढ़ाएगा विश्वकर्मा समाज

इन्तेजारुल हक

नीतीश कुमार की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर नीतीश से अब धीरे-धीरे उनका परंपरागत मतदाता नाराज होता दिख रहा है. कुछ ऐसी ही स्थिति चम्पारण जिले में बन पड़ी है. यहां का विश्वकर्मा समाज इन दिनों नीतीश सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ आग उगलने लगा है और आगामी चुनाव में अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए गोलबंद भी हो रहा है.

विश्वकर्मा सम्मेलन

विश्वकर्मा समाज अपने ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार, दबंगों द्वारा की जा रही मनमानी, सरकारी योजनाओं में उनकी उपेक्षा तथा कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को अब और सहने की स्थिति में नहीं है. इसके लिए बिहार प्रदेश विश्वकर्मा सोसाइटी के माध्यम से अपने अधिकार व खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा. चार माह पूर्व रामगढ़वा में शंभू शर्मा नामक एक व्यक्ति व उसके परिजनों पर दबंगों द्वारा किया गया जुल्म, तुरकौलिया के शंकर सरैया निवासी रामचन्द्र प्रसाद की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या जैसी घटनाओं के बाद इस समाज का नीतीश सरकार से भरोसा उठ गया है.

कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला यह समाज इस मोड़ पर आ जाएगा और सुशासन की पोल खोलने के लिए सड़क पर उतर जाएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था. विश्वकर्मा समाज द्वारा हाल ही में मोतिहारी के नगर भवन के मैदान में आयोजित सम्मेलन में उमड़ी लोगों की भीड़ व सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव ने यह साफ कर दिया है कि विश्वकर्मा समाज काफी जागरूक हो गया है और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. जिस तरह से सभी वक्ताओं ने खुलकर सुशासन पर निशाना साधा और उपस्थित जनसमूह ने अपनी एकता का परिचय देते हुए नीतीश सरकार को सबक सिखाने का संकल्प लिया उससे एक तरफ जहां चम्पारण की राजनीति गर्म हो उठी है वहीं सत्ताधारी दल जदयू में शामिल समाज के तथाकथित ठेकेदार काफी बेचैन दिखने लगे हैं. यहां बताते चलें कि लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा-कसेरा और शिल्पी जातियां विश्वकर्मा समाज के अन्तर्गत आती हैं. चम्पारण में इनकी आबादी करीब चार लाख के आस-पास है, जो चुनाव में खास भूमिका निभाती रही हैं. सम्मेलन में उपस्थित बिहार प्रदेश विश्वकर्मा सोसाइटी के अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद रामजी प्रसाद शर्मा, संरक्षक गोरखनन्दन विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रामश्रय शर्मा, केशव मिस्त्री, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर, पारस लाल विश्वकर्मा, राजेश्वर ठाकुर, कैलाश प्रसाद, सागर कुमार शर्मा, डा. चंदेश्वर ठाकुर, अमीरीलाल ठाकुर व शिववशंकर ठाकुर आदि ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाने व इसी तरह से एकजुट रहने पर बल दिया. दूसरी तरफ सोसाटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद रामजी शर्मा ने नीतीश सरकार पर विश्वकर्मा समाज को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल अखबारों में ही इस समाज का विकास हुआ है. सरकार की योजनाओं से यह समाज पूरी तरह उपेक्षित है. उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विश्वकर्मा आयोग का गठन करना चाहिए तथा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि इस समाज की आर्थिक स्थिति सुधर सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

18 नवंबर-24 नवंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

आजम की दंबगई पर मुलायम का वरदहस्त

संदीप कश्यप

समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खां एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अबकी बार उनकी सुर्खी का कारण उनका अपने मातहत काम करने वालों के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज करने वाला व्यवहार बना. जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो लम्बे समय से आजम के दुर्व्यवहार से नाराज चल रहे उनके स्टाफ ने बागवती तेवर अपना लिए. स्टाफ के अधिकारियों ने अखिलेश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें आजम के अधीन नहीं रहना है, उनका तबादला अन्यत्र कर दिया जाए. यह बात आजम को काफी नागवार गुजरी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए. सीएम ने भी साथ नहीं दिया. आजम ने बगावत करने वालों को निलंबित करने की मांग की तो सचिवालय कर्मचारी संगठन बगावती कर्मचारियों के पक्ष में खड़े हो गया. हालात की नजाकत को भांप कर मुख्यमंत्री ने बिना देर किए आजम की मांग को ठुकरा दिया और एक जांच कमेटी बैठा थी. इसके साथ ही एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या आजम के मंत्री रहते ऐसी कोई जांच ईमानदारी से सम्पन्न हो सकती है, जिसकी छीटें आजम के दामन पर भी पड़ रही हों. वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी एक इलेक्ट्रानिक चैनल के स्टिंग आपरेशन के बाद दंगों में आजम की भूमिका की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था. आजम पर आरोप था कि उन्होंने कुछ लोंगों को छोड़ने के लिए पर दबाव बनाया. तब भी कहा गया था कि आजम के मंत्री रहते जांच सही तरीके से सम्पन्न नहीं हो सकती है. इस समय भी सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया था, जबकि दूसरी तरफ जब अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर डीएसपी जिया-उल-हक हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में जांच बैठाई गई थी तो उन्हें यह कहते हुए मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था कि उनके मंत्री रहते जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है. अखिलेश सरकार के दोहरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन आजम की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. मेरे मुलायम और मैं मुलायम का... मंत्र जाप करके आजम समाजवादी पार्टी के भीतर सबको हाशिये पर रखे हुए हैं.

बहरहाल, इस हकीकत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आजम समय के साथ बदलने में माहिर हैं. बसपा राज में मौन रहकर राजनीति करने वाले खां साहब की जुबान में सत्ता पर सवार होते ही तल्खी आ गई है. पार्टी के भीतर और बाहर उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है. जामा मस्जिद के इमाम बुखारी और आजम की अदावत शायद ही कभी ठंडी पड़ती होगी. गृह जिला रामपुर में खां साहब के पार्टी विरोधी और कांग्रेसी नेता खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं. कभी जौहर विवि के बहाने आजम को निशाना बनाया जाता है तो कभी उनका तानाशाही व्यवहार उनके लिए मुसीबत लेकर आ जाता है. रामपुर की सपा सांसद जयाप्रदा के साथ उनका व्यवहार किसी से छिपा नहीं है. आजम ने जया को पार्टी से बाहर निकाल कर ही दम लिया. वैसे तो उनके गृह जनपद में रहने वाले अधिकांश नेताओं को यह शिकायत रहती है कि आजम खां अपने विरोधियों को विरोधियों की तरह नहीं, दुश्मनों की नजर से देखते हैं. उनका अहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. रामपुर की सांसद जयाप्रदा की गाड़ी से जबरन लाल बत्ती उतरवाने के प्रकरण में भी उनका नाम आया था. रामपुर में तैनात सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो उनसे सहमे ही रहते हैं. उनके गृह जनपद में पोस्टिंग न हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर अर्दली तक प्रयासरत रहते हैं. वह जब चाहते हैं किसी की भी इज्जत उतार लेते है. हालांकि, कोई जुबान तो नहीं खोलता है लेकिन जब आजम खां जैसे नेता सत्ता से बेदखल होते हैं तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं.

बात-बात पर इस्तीफा देना, अमेरिका को कोसना, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानने, वंदेमातरम का विरोध सहित तमाम अर्मयादित टिप्पणी उनके जीवन का हिस्सा ही बन गई हैं. पूर्व सपा नेता अमर सिंह के कारण तो उन्हें सपा तक छोड़नी पड़ गई थी और अमर के सपा से जाने के बाद ही आजम की पार्टी में वापसी हो पाई थी. रामपुर के नवाब घराने से तो उनका छत्तीस का आंकड़ा रहता है. दोनों ही एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. आजम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ एक ही तरफ से नहीं टूटा है. अदालत से भी उन्हें झटका मिला है. रामपुर की सीजेएम अदालते ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज मुकदमा वापस लेने से मना कर दिया. आजम के खिलाफ 2007 में स्वार टांडा विधानसभा उप चुनाव के दौरान आयोजित एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था. सपा की सरकार बनी तो आजम को इस मुकदमे से बचाने की मुहिम शुरू हो गई थी. शासन की ओर से गृह सचिव आरएम श्रीवास्तव ने आजम खां पर दर्ज चार मुकदमों को वापस लेने का आदेश रामपुर जिला प्रशासन को दिया था. चार में से तीन मुकदमे वापस भी हो गए थे, लेकिन माया के खिलाफ जातिसूचक शब्द बोलने वाला मुकदमा नहीं खत्म हो पाया, मुकदमा वापसी के लिए जो शासनादेश आया था, उसमें 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लेख किया गया था. मुकदमा धारा 504,171 (छ) आईपीसी की धारा व 3/10 एससी/एसटी एक्ट और 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लेख किया गया था, जिस कारण से सीजेएम वीरेंद्र कुमार पांडे ने इस मुकदमे की वापसी से इन्कार कर दिया.

खैर, आजम की सपा में अच्छी धाक है. आजम अपने आप को मुसलमानों का नेता समझते हैं लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि खां साहब भी कौम के हितों के नाम पर सतही राजनीति करने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं. कभी कांग्रेस को तो कभी भाजपा को कोसते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती तो हमेशा ही उनके निशाने पर रहती हैं. इसे अल्पसंख्यकों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके वोट बैंक के सहारे मलाई मारने वाले तमाम नेताओं ने मुस्लिमों के बच्चों को अच्छी तालीम मिले, उनकी प्रगति हो और उनकी रोजी-रोटी के नए अवसर खुलें. इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया. मुसलमानों की दुर्दशा का ठीकरा फोड़ने की जब बात आती है तो भाजपा जैसे दलों को आगे कर दिया जाता है. यह देखकर दुख होता है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वालों को आजादी के लिए अपनी शहादत देनेवालों का सम्मान करना भी नहीं आता है. शायद ये दल यही चाहते होंगे कि मुस्लिमों की शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति अवरुद्ध रहे, ताकि वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वार्थ की रोटियां लाल कर सकें. हाल में ही उत्तराखंड सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जब आपदा से नहीं लड़ पाए तो जंग कैसे लड़ेंगे. रामपुर की ऐतिहासिक इमारतों को तुड़वाने का भी उन पर आरोप लगता रहा है, कांग्रेस ने इसके खिलाफ जांच तक बैठाने की बात कही.

आजम खां ने अपनी सियासत चकमाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के एक नामचीन नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम काफी उछाला है. आजम ने मौलाना जौहर के नाम पर रामपुर में एक उर्दू-अरबी-फारसी का विश्वविद्यालय खोलने का सराहनीय एवं ऐतिहासिक कार्य किया, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने विरोधियों को इस मामले में कई सवाल खड़े करने के मौके दे दिए. बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब आजम के गृह जनपद रामपुर के स्वार टांडा से विधायक काजिम अली उर्फ नावेद मियां अपना दर्द लेकर लखनऊ पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर विकास मंत्री आजम खां ने निजी ट्रस्ट के लिए सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा ली है. यह जमीन विवि परिसर के भीतर है. काजिम का कहना था कि आजम ने जौहर ट्रस्ट के लिए जमीन के दो टुकड़ों पर कब्जा कर लिया है. इसका रकबा 220 और 200 बीघा है. इस मौके पर रामपुर के उद्यमी फैसल भी मौजूद थे, वह तो बात करते-करते तो ही पड़े और बोले, आजम ने मुझे तबाह कर दिया और मरवा भी सकते हैं. फैसल का कहना था कि उनकी फोटो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ छप गई थी, इसी बात को लेकर आजम खां मुझे बेहद नाराज हो गए. काजिम को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आजम की शिकायत रंग लाएगी, लेकिन शासन-प्रशासन इसके उलट काजिम की ही आवाज दबाने लगा. हो सकता है कि नावेद मियां को भी अमर सिंह, इमाम बुखारी, जयाप्रदा जैसे तमाम नेताओं की तरह पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि आजम से अदावत का अंजाम यहीं होता है. ■

आजम खां ने अपनी सियासत चकमाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के एक नामचीन नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम काफी उछाला है. आजम ने मौलाना जौहर के नाम पर रामपुर में एक उर्दू-अरबी-फारसी का विश्वविद्यालय खोलने का सराहनीय एवं ऐतिहासिक कार्य किया, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने विरोधियों को इस मामले में कई सवाल खड़े करने के मौके दे दिए.

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री बनने के लिए मुलायम ने मांगी मदद

मौलानाओं के सहारे मुस्लिमों पर डोरे

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के दावेदार मुलायम सिंह यादव का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर जाग उठा है. राज्य के अलग-अलग जिलों से आए सैकड़ों मौलानाओं को अपने सामने देखकर सपा सुप्रीमो हुंकार भरने लगे. उन्हें आगे-पीछे की सभी बातें याद आ गईं. ऐसा लग रहा था मानो मुलायम इस दिन का लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे. भावनाओं का सैलाब उमड़ा तो सपा प्रमुख ने दो टूक कह दिया, चाहे हम सरकार में रहें हों या नहीं रहें हों, हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे. हम उनकी समस्याओं से वाकिफ हैं. मुस्लिमों की भाषा, संस्कृति, पूजापद्धति, परंपरा की रक्षा की गारंटी समाजवादी पार्टी देती रही है. चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका वादा है. सांप्रदायिक शक्तियों को सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा.

यादव सपा के प्रदेश कार्यालय में कानपुर, खुर्जा, बिजनौर, लखनऊ, रायबरेली आदि से सैकड़ों की संख्या में आए मौलानाओं को संबोधित कर रहे थे. मुलायम ने मुस्लिमों के लिए प्यार का इजहार किया तो कई मौलानाओं ने दो कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि नेताजी आपने बाबरी मस्जिद बचाई थी, तब से आज तक आप उसी रास्ते पर हैं. आप में कोई अंतर नहीं आया है. अब हम सब वायदा करते हैं कि आपको बड़ी ताकत के साथ दिल्ली भेजेंगे. हम सब 2014 में सपा की फतेह की दुआ करते हैं. मुलायम ने मौलानाओं को बताया कि मुस्लिमों की पूरी मदद से ही समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है. लोकसभा चुनावों में भी आपकी मदद की जरूरत है.

लोकसभा के होने वाले चुनाव राजनीति को नई दिशा देने वाले होंगे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जन्म ही सांप्रदायिकता की चुनौती को स्वीकार करने के लिए हुआ था. समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर सांप्रदायिकता के दैत्य को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन एक-एक कर सांप्रदायिकता का राक्षस सिर उठाता रहता है.सपा प्रमुख ने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए बताया कि पहले कांग्रेस राज में पुलिस में एक से डेढ़ प्रतिशत मुसलमानों की भर्ती होती थी. समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्रमशः 9 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत, 14.15 प्रतिशत और 27 प्रतिशत तक मुसलमानों की भर्ती हुई. उन्होंने मुजफ्फरनगर की घटना को दुःखद और निंदनीय बताते हुए कहा कि वहां मृतकों को 10 लाख रुपये की मदद दी गई. आवास बनाने के लिए 1800 मुस्लिम परिवारों को 5-5 लाख रुपये की मदद की गई है. किसी सरकार ने इतनी मदद कभी मुस्लिमों की नहीं की. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं. उन्होंने कहा कि सपा सरकार हमेशा से मुस्लिमों की हितैषी रही है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दंगों में शामिल या दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगेस्टर एक्ट जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग किया जाएगा. समाजवादी पार्टी सरकार अपने चुनाव वायदों की पूर्ति में कब्रिस्तानों की चहारदिवारी बनवाने के लिए बजट में धन की व्यवस्था कर चुकी है. मदरसों को मदद दी जा रही है. 10वीं पास मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है. लैपटाप वितरण से तमाम घर रोशन हुए हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग हो रही है. मुलायम से मिलने वालों में प्रमुख मौलाना-मो. जफर मसूद किछौछवी, शेख सुलेमान (बिजनौर), हाजी अजीजो, हाजी राशिद (खुर्जा), इमरान काजी (सहारनपुर) मुफ्ती-ए-शहर पीलीभीत, सैयद प्रधान, मसूद आलम नदवी (नसीराबाद, रायबरेली) मौलाना सज्जाद रजा (लखनऊ) इंसाफ रजा खां नन्दी (घाटमपुर-कानपुर) आदि थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

देश की दुर्गति से बड़ा नहीं है राहुल गांधी का दुख

मार्कण्डेय प्रसाद सिंह

[illegible] चमत्कार ही होगा. पर यह चमत्कार हो भी तो देश को क्या हासिल होगा? कांग्रेस की हालत आज सचमुच दयनीय मालूम हो रही है. फिलहाल इसे विपक्षी दलों से नहीं, अपने दलों के नेताओं से ज्यादा खतरा है. ■

आज़मगढ़ से सपा का चुनावी शंखनाद

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

यूपी के रास्ते दिल्ली की सत्ता पर क़ाबिज़ होने का मंसूबा लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एवं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने लाव-लश्कर के साथ पिछले दिनों आज़मगढ़ के आईटीआई मैदान पर पहुंचे. यहां हज़ारों-हज़ार की संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. समाजवादी पार्टी ने इस महारैली को देश बचाओ-देश बनाओ का नाम दिया था. यह रैली यूपी से सपा के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी है और मोदी की कानपुर रैली का जवाब भी. मुलायम सिंह यादव ने मंच पर पहुंचते ही जनता का अभिवादन स्वीकार किया और फिर यूपीए सरकार पर हमला बोलने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी को भी आड़े हाथों लिया. मोदी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए मुलायम ने कहा कि मोदी या तो गुजरात में दिखते हैं या फिर टीवी में. उन्होंने भाजपा पर देश को बर्बाद करने का भी आरोप मढ़ा और यह भी कहा कि साम्प्रदायिक ताक़तें अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी. क्योंकि उनको रोकने के लिए समाजवादियों ने कमर कस ली है. आज़मगढ़ से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने की वजह बताते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि लोग कहते हैं कि आज़मगढ़ मुसलमानों और यादवों का गढ़ है, इसीलिए हम अपने अभियान की शुरुआत यहां से करते हैं. लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है. क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों का ध्यान रखा है. हमारी सरकार आज भी 17 पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने पीएम को बेचारा बताया. कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है. क्योंकि वह अपनी मरज़ी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को कमज़ोर कर रखा है. और जिस देश का मुखिया कमज़ोर होता है वह देश भी कमज़ोर होता है. देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते. घोटालों पर बरसते हुए कहा कि पिछले एक दशक में केन्द्र सरकार घोटालों की सरकार के रूप में उभर कर सामने आई है. विकास दर भी काफ़ी घट गई है जो देश के लिए चिंता का सबब है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल की जनता से यूपी की सभी 80 सीटें जिताने का विनम्र निवेदन किया. कहा कि प्रदेश की सारी सीटें जिता दो तो देश की तक़दीर बदल जाएगी. अगर सपा के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बन जाएगी तो महंगाई और भ्रष्टाचार का नामो-निशान देश से मिटा देंगे.

महारैली को सम्बोधित करने के लिए माइक थामते ही सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और मोदी को निशाने पर ले लिया. किसी का नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि ये दोनों न गांव जानते हैं और न ही किसान. उनकी नीतियां ग़रीब और किसान विरोधी हैं. तल्ख तेवरों में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़मगढ़ का आईटीआई मैदान लोगों की भीड़ से छोटा पड़ गया है. जो लोग अपनी रैलियों का ढिंढोरा पीटते हैं, वह देख लें कि असली रैली कैसी होती है. अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को ललकारते हुए नेताजी (मुलामय सिंह यादव) को दिल्ली पहुंचाने का आह्वान किया. कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो नेतृत्व के कारण सपा को अपार समर्थन और प्यार मिला. जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया. अबकी बार ज़िम्मेदारी उनकी है और वह चाहते हैं कि नेताजी को रिटर्न गिफ्ट दिया जाए, जिसके लिए हमें लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालकर पार्टी मुखिया को दिल्ली भेजना होगा. सीएम अपनी सरकार की उपलब्धियां बयान करने से भी नहीं चूके. उन्होंने एक-एक कर पार्टी की नीतियों को भी जनता के सामने

रखा. विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विकास हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, जबकि अन्य पार्टियां सांप्रदायिकता फैलाकर देश-प्रदेश का माहौल ख़राब करने में जुटी हुई हैं. मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं मुस्लिम ट्रंप कार्ड आज़म खान ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को मंच से उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए झाड़ पिलाई. ग़ौरतलब हो कि इन धर्मगुरुओं ने मोदी को माफ़ करने की बात कही थी. जिससे आज़म ख़ान भड़क उठे थे. मंच से उन्होंने धर्मगुरुओं को नसीहत देते हुए कहा कि जिनके घर दंगों में नहीं जले हैं और जिनकी बहन-बेटियों की आबरू सलामत है, ऐसे लोग कह सकते हैं कि क़ातिलों से समझौता हो सकता है. यह बेशर्मी की हद है. उन्होंने मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आबादी के हिसाब से आरक्षण देने के साथ ही सांप्रदायिक दंगा विरोधी विधेयक संसद में पास करने की भी मांग की. आज़म के वक्तव्य में दंगों का दर्द भी छलक कर सामने आया. उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के पीड़ित मुसलमान युवकों के पाक ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के सम्पर्क में होने के राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की. यही नहीं, यूपी के वरिष्ठ मंत्री ने गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के लिए नरेन्द्र मोदी द्वारा गाड़ी की ठोकर से पिल्ले की मौत हो जाने के दिए गए उदाहरण पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की. आज़मगढ़ के युवाओं को आतंकवादी क़रार दिए जाने के वाक़यों का भी उन्होंने ज़िक्र किया. महारैली को प्रदेश के पंचायती राज मंत्री बलराम यादव, परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविन्द चौधरी ने भी सम्बोधित किया.

हिन्दुस्तान नहीं हिन्दोस्तान

आज़म ख़ान ने अपने भाषण में देश को हिन्दुस्तान के बजाय हिन्दोस्तान कहने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ सांप्रदायिक ताक़तें देश को सिर्फ़ हिन्दुस्तान बनाना चाहती हैं. जबकि यह देश हिन्दू और मुसलमान सभी का है. यहां की हर क़ौम को बाक़ी क़ौमों की ज़रूरत है. कुछ लोग देश को बांटने के लिए इसे सिर्फ़ हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं. जबकि हमें इसे हिन्दोस्तान बनाना है. आज़म ख़ान के भाषण के बाद जनसमूह को सम्बोधित करने पहुंचे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी उनकी बात का समर्थन किया. कहा कि आज से समाजवादी पार्टी और इसके कार्यकर्ता हिन्दुस्तान नहीं बल्कि हिन्दोस्तान ही कहेंगे. ■

मुलायम का हौसला और आजम का कद बढ़ा

[illegible] पा रहे हैं कि दंगों का दाग कैसे धुलेगा. अखिलेश ने मुलायम के लिए रिटर्न गिफ्ट की मांग की. उनका कहना था कि मुलायम की वजह से हम यूपी जीते हैं, इसलिए उन्हें (मुलायम सिंह का) रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए. मगर यह बात प्रदेश की जनता के समझ में आती है कि नहीं, यह देखने की बात होगी. *-संजय सक्सेना*

मोहर्रम शांतिपूर्वक निपटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती

फिर दंगों की आग में झुलसा उत्तर प्रदेश

संदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना समाजवादी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है. बमुश्किल शांत हुआ मुजफ्फरनगर एक बार फिर हिंसक वारदातों से दहल उठा. चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. वहीं शामली में मोटर साइकिल सवार पति-पत्नी के ऊपर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले में हुई एक मौत की घटना को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा पांच पर पहुंच जाता है. उक्त घटनाओं के चंद घंटों के भीतर ही डीजीपी देवराज नागर ने अपने मातहत काम करने वाली पुलिस पर ही लापरवाही का आरोप जड़ कर सबको चौंका दिया. आनन-फानन में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. फिलहाल ऊपर से देखने में हालात अब शांत हैं, लेकिन ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है. इसका जवाब किसी के पास नहीं है. यहां के बाशिंदों के बीच आपसी विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही है. पुलिस और सरकार द्वारा शांति बहाली के लिए उठाये जा रहे कदमों को लेकर भी स्थानीय नागरिकों की राय बंटी हुई है. सरकार पर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उत्पीड़न और भेदभाव का अरोप लगाया जा रहा है तो पुलिस पर भी राजनैतिक दबाव में काम करने की बात देखने में आ रही है. इससे इतर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका मानना है कि अगर शांति बहाली के उपाय गंभीरता से और दंगा भड़काने वालों पर बिना पक्षपात के कार्रवाई की गई होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती की वह दोबारा शहर की फिजा में जहर घोल पाता. दंगाइयों पर हाथ डालने की बजाए पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया. अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस हाथ बांधे खड़ी है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर की घटना गंभीर है. जो लोग आपस में अलगाव पैदा करने और वैमनस्य फैलाने की कोशिशों में लगे हैं, उन्हें अपने मंसूबों में सफल नहीं होने दिया जाएगा. सांप्रदायिक ताकतों से ज्यादा शक्ति सरकार में होती है. किसी पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा

कि मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से भी ज्यादा खराब है. शिक्षा, नौकरी, राजनीति सभी क्षेत्रों में वे उपेक्षित हैं. हम इसीलिए इनके साथ खड़े हैं, ताकि समाज में सामंजस्य रहे और कोई उत्पीड़न का शिकार न हो. हम उनके साथ किसी भी स्तर पर अत्याचार या भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे. यादव ने कहा कि मुस्लिमों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी सरकार ने उनकी बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए 30 हजार रुपये का अनुदान और मुजफ्फरनगर घटना के शिकार विस्थापित मुस्लिमो को घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपये की सहायता दी है. पीड़ितों को 90 करोड़ की सहायता दी जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिशें लम्बे समय से चल रही हैं. मंदिर-मस्जिद विवाद के पीछे समाज के बंटवारे की साजिश थी. शिलान्यास करके विवाद को भड़काया गया. बाबरी मस्जिद को हमने टूटने से बचाया और मजबूरन गोली चलानी पड़ी. अभी 84 कोसी परिक्रमा के बहाने लोगों को साधु वेष में अयोध्या लाने की साजिश हुई. उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ पुरजोर लड़ाई अकेले ही लडते रहे हैं. भाजपा जब तक अपनी नीतियां नहीं बदलतीं, हम विरोध करते रहेंगे. बहरहाल, एक तो चुनाव वर्ष और उस पर दंगों की बाढ़ के बीच मोहर्रम भी आ गया है. मोहर्रम शांतिपूर्वक निपट जाए, यह भी अखिलेश सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. इतिहास गवाह रहा है कि मोहर्रम के मौके पर शासन-प्रशासन की थोड़ी भी लापरवाही का बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है. मोहर्रम करीब दो महीने तक चलेगा. इस दौरान जरा सी भी चूक होने का मतलब सांप्रदायिक ताकतों को अपने मंसूबों को परवान चढ़ाने का मौका देने जैसा होगा. फिलहाल, तनाव वाले इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं. इसी कड़ी में गत दिनों सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील पुराने लखनऊ में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च और गश्त की. विभिन्न जिलों में सभ्रात लोगों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सौंपा जा रहा है. ■

कानून व्यवस्था : फिर वही ढाक के तीन पात

दर्शन शर्मा

अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जबर्दस्त फजीहत झेल रही है. लाख यत्न करने के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. स्थिति यह है कि किसी को कानून का डर ही नहीं रह गया है. शहरों से लेकर गांवों तक अराजकता का माहौल बना हुआ है. महिलाएं घर से निकलने में हिचक रही हैं, वहीं आम आदमी अपने को असुरक्षित मान रहा है. ऐसी स्थिति में सपा सरकार के अच्छे कार्य भी धुंधले पड़ते जा रहे हैं. कभी हार न मानने वाले सपा प्रमुख का यह बयान कि मंत्रियों और विधायकों से नाराजगी की सजा उन्हें न दी जाए, मुलायम सिंह की हताशा को दर्शाता है. अपने बचाव की मुद्रा में दिखने वाले मुलायम सिंह की इसके लिए राजनीतिक गलियारों में आलोचना हुई. जानकारों का कहना है कि सपा प्रमुख निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश सरकार उनके निर्देशन में चलती है. वह समय-समय पर सब कुछ दुरुस्त करने और अखिलेश सरकार के मंत्रियों को ठीक करने की भी घोषणा करते रहते हैं. उन्होंने प्रदेश की समस्याओं के लिए नौकरशाही को कई बार कोसा है. सपा सरकार की कमजोरी विपक्षी दलों को इस समय रास आ रही है. उत्तर प्रदेश की रैलियों में भाजपा के घोषित प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी मंच से सपा सरकार पर तंज कसते हैं कि जब उत्तर प्रदेश का कोई युवा गुजरात में नौकरी के लिए जाता है, तो उसकी मां तब तक नहीं सोती, जब तक वह उत्तर प्रदेश की सरहद पार कर गुजरात की सीमा में नहीं पहुंच जाता. बहरहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है. दो दशक पहले तक एक हत्याकांड पर जनता कांप जाती थी. लेकिन अब सपाई दबंगों की करतूतें कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं. सरकार से डरे लोग अदालत

की शरण में जा रहे हैं. कन्नौज कनकपुर गांव के निवासी कल्याण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं ने उसके घर में घुसकर लड़कियों से छेड़छाड़ की व बलात्कार करने की कोशिश की. इसकी शिकायत पुलिस को किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाई नहीं की गई. ऐसे ही कई अपराध के किस्से सुर्खियों में छाए रहते हैं. जिनकी पुलिस अनदेखी करती है. इससे साबित होता है कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं से जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, वहीं नागरिकों का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने की तो दूर, मुकदमा दर्ज करने में भी आना-कानी करती है. पिछले दिनों माफिया के गूर्गों ने ढाई करोड़ के टेंडर बाराबंकी में लूट लिए, जो पुलिस के लिए एक चुनौती कही जाएगी. भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक का कहना है कि प्रदेश में लगातार खराब हो रही कानून-व्यवस्था पर धन देने के बजाय, सीएम दूसरे राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि ले रहे हैं. सूबे में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है. उन्नाव में बेखौफ दुष्कर्मियों ने न सिर्फ नवीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप किया, बल्कि विरोध करने पर उसके भाई की हत्या कर दी. पूरे प्रदेश में शोहदों के हौसले बुलंद हैं. लखनऊ में एक तेल मिल मालिक को गोली मारकर बदमाश रफूचक्कर हो गए. यूपी पुलिस की हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मेरठ में पुलिस से ही रंगदारी मांगी गई. अपराधी बाकायदा खाता नंबर बताकर उसमें रुपये जमा करने की बात कह रहे थे, जिसकी पुलिस पड़ताल चल रह रही है. डीजीपी देवराज नागर का कहना है कि अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है. पुलिस अब हिंसा व बलात्कार पीड़ित महिलाओं से पूरी हमदर्दी से पेश आएगी, बल्कि पीड़ित का मनोबल बढ़ाएगी.

सिविल सोसाइटी के लोगों का मानना है कि सत्ता पक्ष के नेता थानों में अपने मनपसंद पुलिसकर्मियों व थाना प्रभारी की तैनाती के लिए दबाव बनाते हैं, जिसके चलते ईमानदार अधिकारियों की तैनातीनहीं हो पाती है. भ्रष्ट अधिकारी-नेता मिलकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं. केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घटना की फिर रिपोर्ट तलब की है. डीजीपी देवराज नागर ने मुजफ्फरनगर के फुगाना व भौराकलां क्षेत्र में हुई चार हत्याओं को सांप्रदायिक हिंसा मानने से इन्कार किया है. उनका कहना है फुगाना में महिला की हत्या आपराधिक वारदात है, जबकि मोहम्मदपुर रायसिंह में हुई तीन हत्याएं आपसी विवाद का नतीजा हैं. लेकिन मुलायम सिंह का कहना है कि मुजफ्फरनगर में हुई घटना गंभीर है. असल सवाल तो यह है कि मायावती के शासन में अपराधी पुलिस से खौफ खाते थे तो सपा शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि अपराधियों से पुलिस खौफ खाती है. अखिलेश सरकार को ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम चाहिए. ■

राजपूत पार लगाएंगे राजनाथ की नैया

कुमार निलाम्बुज

भले ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के विकास और जन भावनाओं को भुनाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह के प्रधानमंत्री के सपने को धूमिल नहीं कर पाई है. राजनाथ सिंह अभी भी खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर नहीं मानते, तभी तो राजपूत-पुत्र नेताओं को पार्टी का सियासी चोला पहनाकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं. जानकारों का कहना है कि राजनाथ सिंह ज्यादातर टिकट राजपूत नेताओं को दिलाने की कोशिश में हैं. कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है इसमें कुछ भी स्थाई नहीं होता. राजनाथ सिंह सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आखिर तक हार नहीं मानते. इसीलिए मोदी के प्रधानमंत्री का विरोध सरेआम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों को टिकट दिलाने की चाल चल रहे हैं. राजनाथ सिंह अपने सपने को मूर्तरूप देने के लिए कोई भी समझौता करके पार्टी के अंदर अपना एजेंडा चला रहे हैं. क्षत्रिय क्षत्रपों को अपने कुनबे से जोड़ने के क्रम में राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सिंह के बड़े बेटे पंकज शेखर को पार्टी की सदस्यता दिला कर पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटरों को रिझाने का काम किया है. पंकज सिंह भले ही राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से उनका वासता कम ही रहा है. पंकज शेखर सिंह के राजनीति में अनाड़ी होने का फायदा भी राजनाथ सिंह को ही होने वाला है. लेकिन पंकज सिंह भी सयाने निकले. पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सलेमपुर से दावेदारी ठोंक कर अपनी मंशा जाहिर कर दिया है. राजनाथ सिंह ने पंकज शेखर के सहारे पूर्वांचल में अपनी पकड़ और क्षत्रिय वोटों के सहारे खुद को पार्टी में मजबूत करने और इसी बहाने खुद को ताकतवर दिखाने का भी दांव चला है. अब क्षत्रिय क्षत्रप राजनाथ को कितना सियासी मदद कर पाते हैं, यह तो चुनाव बाद तय होगा, लेकिन सियासी दाव पेंच तो अभी से करने पड़ रहे हैं. पिछली दफे जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, तब भाजपा के पीएम इन वेटिंग आडवाणी जी थे और चुनाव प्रचार का जिम्मा अरुण जेटली और प्रमोद महाजन संभाल रहे थे. पिछले दफे राजनाथ सिंह के दामन पर भी हार के दाग लगे थे. इस बार मोदी की हवा के सहारे दामन में लगे दाग को धोने के साथ-साथ अपनी राजनीति चमकाने की दोहरी चाल चली है राजनाथ सिंह ने. उन्होंने पंकज शेखर की आड़ में पार्टी को यह संदेश दिया है कि पार्टी में क्षत्रियों के झंडाबरदार वे स्वयं हैं. जुगाड़ू राजनाथ सिंह ने पंकज शेखर सिंह के सहारे एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है. वैसे राजपूत बिरादरी विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़कर कभी किसी एक सियासी दल के साथ नहीं रही. राजपूत बिरादरी मजबूत स्वजातीय को छोड़ दें तो किसी अन्य के पाकेटवोट नहीं रहे है. क्षत्रिय वोटर समय-समय पर

अपने आका और पार्टी बदलते रहे है. इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी ने विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर क्षत्रिय वोट भाजपा की ओर सरका है. राजपूत बिरादरी के सकलडीहा (चन्दौली) के बाहुबली विधायक सुशील सिंह और जौनपुर के दबंग सांसद धनन्जय सिंह लगातार राजनाथ सिंह के सम्पर्क में हैं. अगर पार्टी उन्हें टिकट का आश्वासन दे तो वे पार्टी का दामन थाम सकते हैं. पंकज शेखर सिंह उन्हीं कड़ियों में से एक हैं. पंकज के सलेमपुर से पार्टी प्रत्याशी घोषित करने से स्थानीय भाजपा नेताओं के कान खड़े हो गए हैं. बलिया में भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले छात्र राजनीति के धुरंधर भरत सिंह ने तो बाकायदा पंकज शेखर संह के टिकट का विरोध लखनऊ तक कर डाला है. भरत सिंह का कहना है कि पंकज सिंह का कोई जनाधार नहीं है. उनको टिकट देने से साल भर भाजपा का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता नाराज हताश होकर बैठ जाएंगे, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा.

पंकज सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सिंह के बेटे जरूर हैं लेकिन राजनीति में नए हैं, वहीं सलेमपुर से उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता रविशंकर सिंह पप्पू पहले से ही मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. निर्दल एमएलसी और कोयला कारोबारी ठहरे पप्पू सिंह बाहुबली और ठेकेदार भी हैं. उनके पास राजनीति का अनुभव और स्वजातीय गणित के साथ गैर जातियों में अच्छी पहचान है. जिसके चलते कहा जा सकता है कि चन्द्रशेखर सिंह के मुंहबोले नाती उनके बेटे पंकज पर सियासी तौर पर भारी पड़ेंगे. जहां तक क्षत्रिय वोटों का अगुवा बनने का सवाल है मोदी के नाम पर वैसे भी क्षत्रिय वोटर भाजपा की ओर सरके हैं. यही कारण है कि जीत की चाह में ज्यादातर धनपशु नेता और महाबली भाजपा की टिकट की बाट जोह रहे हैं. जहां तक पंकज के सहारे पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटरों को रिझाने की बात है तो पंकज कभी भी बलिया या सलेमपुर में आम आदमी के साथ नहीं जुड़े, उनका दिल दिल्ली ही रमता है. राजनाथ सिंह ने पंकज को पार्टी में लाकर क्षत्रिय झंडाबरदार बनने के अपनी चाल ठीक ही चली है. राजनाथ तिकड़मी नेता माने जाते हैं, लिहाजा उनकी चाल के पीछे की राजनीति ने पार्टी के लोगों और रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर किया है. हर बिरादरी के लोग मजबूत आदमी को अपना नेता मानते हैं लेकिन पंकज इस मामले में कमजोर हैं. क्योंकि यहां पहले से ही उन्ही के परिवार के पप्पू सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सिंह के नाम पर राजनीतिक जमीन बनाई है. यहां पर अगर पंकज शेखर और उनके भतीजे में लड़ाई होती है तो इसका फायदा तीसरे प्रत्याशी को मिलना तय है. पप्पू सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलएसी का चुनाव भी जीत चुके हैं. जनता में अच्छी पकड़ भी है. उधर समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय वोट भाजपा में खिसकता देखकर एक बार फिर राजा भैया के सिर पर मंत्री का सेहरा बांध कर क्षत्रिय वोटरों को रिझाने की चाल चली है. आजम खाने के सहारे मुस्लिम और राजा भैया के सहारे राजपूत दोनों ही वोटरों पर सपा ने डोरे डाले हैं. मोदी की आंधी में उड़ने की चाह में पूर्वांचल के दजर्नों नेता राजनाथ सिंह के सम्पर्क में हैं. राजनाथ की सियासत और मोदी का क्रेज दोनों का एक ही दल में मुकाबला है. अब वक्त बताएगा की मोदी और राजनाथ की सियासी गणित में कौन बाजी मारता है. ■

आज भी निभा रहे पीढ़ियों पहले हुआ बहिष्कार

एच. एन. सिंह

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पल्हना ब्लाक में ऐसा भी एक गांव है, जहां ब्राम्हण सैकड़ों साल से एक अजीब बंधन में बंधे हैं. अगर इस बंधन से निकलने की सोचे भी तो उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है. आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर व ब्लाक मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर तरवा-लालगंज मार्ग पर स्थित इस गांव का नाम है हैबतपुर डुभाव, जहां की बातें आज के वैज्ञानिक युग में किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं. इस गांव में लगभग 150 घर ब्राम्हण हैं और एक ऐसे ब्राम्हण के आदेश से बंधे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है. इस गांव के ब्राम्हणों के लिए समीपवर्ती छह गांवों में भोजन की तो बात ही दूर है, पानी तक पीना उनके लिए अभिशाप के समान है. बात सैकड़ों साल पहले की है जिसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन उसे आज भी मानते हैं. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले की बात है जब इस गांव के एक ब्राम्हण कहीं से बैल खरीद कर ला रहे थे, रास्ते में दूसरे गांव के एक दबंग ने बैल को अपने दरवाजे पर जबरन बांध लिया. इस ब्राम्हण ने पहले तो काफी अनुनय-विनय किया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. इसके बाद अपनी बात आस-पास के छह गांवों तक पहुंचाई. ब्राम्हण के कहने पर इन गांवों के लोग पहुंचे और पंचायत हुई, लेकिन पंचों ने ब्राम्हण के विपक्ष में फैसला दे दिया. विपक्ष में फैसले से वह ब्राम्हण इतना आहत हो गया कि उसने वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया. प्राण त्यागने से पूर्व इस ब्राम्हण ने हैबतपुर डुभाव

> **ब्राम्हण के कहने पर इन गांवों के लोग पहुंचे और पंचायत हुई, लेकिन पंचों ने ब्राम्हण के विपक्ष में फैसला दे दिया. विपक्ष में फैसले से वह ब्राम्हण इतना आहत हो गया कि उसने वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया. प्राण त्यागने से पूर्व इस ब्राम्हण ने हैबतपुर डुभाव के ब्राम्हणों को इन छह गांवों का पानी पीने से मना किया. कहा कि अगर किसी ने उसकी बात पर अमल नहीं किया तो वह सुखी नहीं रहेगा.**

के ब्राम्हणों को इन छह गांवों का पानी पीने से मना किया. कहा कि अगर किसी ने उसकी बात पर अमल नहीं किया तो वह सुखी नहीं रहेगा. इसके बाद से ही हैबतपुर डुभाव के ब्राम्हणों ने आस-पास के छह गांवों का भोजन पानी त्याग दिया. आज भी वह परम्परा कायम है. समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ. लेकिन वह सलाम दुआ और निमंत्रण तक ही आज भी सीमित है. अगर इन गांवों से किसी ब्राम्हण के घर निमंत्रण आ भी गया तो लोग निमंत्रण देने तो जाते हैं, लेकिन वहां न तो कुछ खाते हैं और न ही इन गांवों का पानी ही पीते हैं. अगर किसी ने कभी भूल से इन छह गांवों में से किसी गांव में पानी भी पी लिया तो उस पर संकट आना तय माना जाता है.

नशे के नकली कारोबार ने उजाड़े परिवार

दर्शन शर्मा

आजमगढ़ और मऊ में जहरीली शराब पीने से हुई कई दर्जन मौतें रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं. विषैली शराब ने इन दोनों जिलों के कई गरीब परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है. इनमें छोटे तबके के खेतिहर मजदूर, किसान और छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं. इनकी संख्या 46 तक पहुंच गई है. यह विभाग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में इन्हीं लोगों के लिए शाम की दवा सस्ती करने के लिए बसपा सरकार की खिंचाई की थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा सरकार लैपटॉप बांटने के चक्कर में पड़ी है. कारोबारियों के मुनाफा कमाने के चक्कर में गरीबों की जान ले रही है. इस व्यवसाय के पीछे छिपी है व्यवसायियों द्वारा अकूत धन कमाने की प्रतिस्पर्धा और लालसा. इस विभाग के माध्यम से जितना लाभ सरकार को मिलता है इससे अधिक के वारे-न्यारे इससे जुड़े लोग कर लेते हैं. एल्कोहल निर्मित इस कारोबार में फायदा ही फायदा है. लिहाजा कारोबारी भी खुश और सरकार भी नीलामी में अंधाधुंध राजस्व कमा लेती है.

बुद्धजीवियों का मानना है कि जहां शराब की खपत पहले अधिक गन्ना उत्पादक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती थी, वहीं अब इसका चस्का पूरे प्रदेश में युवाओं से लेकर बूढ़ों तक फैल गया है. स्वास्थ्य से बेखबर गांव के किसान, मजदूर यहां तक कि किशोरों को भी इसकी लत लग गई है. मनरेगा के आने के बाद गांवों में बढ़ी मजदूरी ने लोगों के शौक दुगने कर दिए हैं. इनमें सबसे बड़ा शौक आजकल शराब का बढ़ता चलन है. स्थिति तो यह है कि चुनावों के वक्त चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार मदिरा का सहारा लेने लगे हैं. एक पाउच पर एक वोट उनका पक्का हो जाता है. यहां तक कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, शराब की दावतें चलती रहती हैं.

प्रदेश में पीने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है. जहां ठेके वाले लाइसेंस लेकर सरकारी शराब की खपत तो करते ही हैं, वहीं नकली शराब की बिक्री का भी धंधा इस व्यवसाय के समानान्तर चलता रहता है. सरकार की नींद तब टूटती है, जब एक साथ कई दर्जन लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं. अवैध शराब बेचने वालों की ओर सरकारी अमला प्रायः अपनी आंखें मूंदे रहता है. इससे सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी इस गोरखधंधे में कोई लाभ मिलता है? यदि नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? अवैध शराब बनाने वाले ज्यादा लाभ लेने के चक्कर में ज्यादा तीव्रता का एल्कोहल मिलाते हैं. लोग ऐसी नकली शराब पीने के बाद मौत के मुंह में चले जाते हैं. जानकारों के मुताबिक कम लागत पर अधिक राजस्व देने वाले इस मदिरा उद्योग में सरकार ने इस विभाग का दायरा तब और बढ़ा दिया, जब गांवों में कमाई के स्रोत ज्यादा दिखने लगे. शहरी जहां अधिकतर अंग्रेजी शराब का प्रयोग करते हैं, वहीं गांव देहातों में छोटी-छोटी गुमटियों में भी देसी शराब के पाउच की बिक्री धुआंधार होती है. एक समय नशे के धंधे को चलाने के लिए सरकार सहजता से लाइसेंस नहीं देती थी, लेकिन इतनी तादाद में बढ़ रही पियक्कड़ों की संख्या देखकर सरकार ने ठेकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है. जहां पहले नशे के लिए लोगों को दूरदराज कस्बों में जाकर लाइसेंसी दुकान पर शराब की बोतलें, पौवा, अद्धा मिल पाता था. वहीं अब शराब माफियागिरी के चलते छोटे-छोटे गांवों में शराब बिकने लगी है. तीन चार दशक पहले जहां ठेकों की नीलामी में न तो ठेकेदारों को भी इतनी रुचि होती थी और न ही सरकार इसे बढ़ावा देती थी. दरअसल तब पीने वालों की एक सीमित संख्या होती थी. लेकिन युवाओं में जब इसका शुरूर चढ़ा तो यह संख्या देखते-देखते कई गुना पहुंच गई. यह व्यवसाय घोर भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है.

प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को जैसी खुली छूट मिली हुई है, उससे आजमगढ़ जैसी घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है. पुलिस इस घटना का दोष आबकारी विभाग पर मढ़ रही है. दुकान चलाने वाले कच्ची शराब की आपूर्ति करते थे, इस संबंध उनका चालान भी हुआ था. नकली शराब बेचने वालों पर भारी जुर्माने के साथ ही सख्त सजा का प्रावधान है. लेकिन अकूत धन कमाने के लालच में कारोबारी गैरकानूनी ढंग से ज्यादा नशा पैदा करने के लिए दूसरे सस्ते रसायन भी मिला देते हैं, जिनके दुष्प्रभाव के चलते असाध्य बीमारियां हो जाती हैं. कभी-कभी रसायनों की ज्यादा तादाद जानलेवा भी साबित होती है. आजमगढ़ और मऊ के लोगों की मौत के पीछे भी यही कारण हैं. सरकार को विषैली शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों. ■

केदारनाथ मंदिर के निर्माण का रहस्य खुलेगा

रेनु शर्मा

केदारधाम में आई हिमालयी सुनामी कई मायने में इस धाम के लिए वरदान सिद्ध होगी. केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर जल्द कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं. मंदिर की सफाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दीवारों व गुंबदों पर हजारों अक्षर गुदे हुए मिले. इन अक्षरों के अध्ययन के लिए विभाग की मैसूर स्थित ब्रांच से इपिग्राफी (पुरालेख) ब्रांच की टीम ने केदारनाथ मंदिर पहुंचकर अक्षरों को रिकॉर्ड किया. पुरातत्वविदों का मानना है कि इन पुरालेखों में मंदिर के सभी राज छिपे हो सकते हैं. मंदिर निर्माण को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाए हैं. इतिहासकारों में भी मंदिर के इतिहास को लेकर अलग-अलग धारणाएं विद्यमान हैं.

केदारघाटी में 16-17 जून को आई तबाही में मंदिर को काफी नुकसान हुआ और भारी मात्रा में मलबा भी मंदिर के अन्दर बाहर भर गया. मलबे को साफ कर दीवारों व गुंबदों को सुरक्षित तरीके से साफ करने के लिए एएसआइ की साइंस ब्रांच यहां केमिकल ट्रीटमेंट (रासायनिक उपचार) कर रही है. पुरातत्व रसायनज्ञों ने जब मलबा हटाया तो दीवारों व गुंबदों पर तेल व दीया आदि जलाने से पैदा होने वाले कालेपन की करीब डेढ़ सेंटीमीटर परत भी चढ़ी हुई मिली. विशेषज्ञों ने जब परत हटाई तो दीवारों व गुंबदों पर हजारों अक्षर गुदे हुए मिले. साइंस ब्रांच की इस जानकारी पर मैसूर से इपिग्राफी ब्रांच के विशेषज्ञ की केदारनाथ पहुंचे. विज्ञान शाखा के निदेशक केएस राणा ने बताया कि इपिग्राफी शाखा की टीम ने अक्षरों को रेकार्ड कर अपने साथ ले गए. पुरालेख

का मैसूर में अध्ययन किया जा रहा है. जल्द ही इसका प्रकाशन किया जाएगा. जिसके बाद काफी हद तक यह साफ हो जाएगा कि मंदिर कब बना, इसे किसने व क्यों बनवाया. मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय ने कराया. एक मत यह भी है कि जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो कि 10वीं सदी से पहले की बात है. प्रख्यात घुमक्कड़ एंव लेखक राहुल सांकृत्यायन ने मंदिर का निर्माणकाल 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में बताया था. अब वह दिन दूर नहीं है कि मन्दिर की सच्चाई जनसमान्य के समक्ष सरकार लाएगी और मंदिर का भी पूरी तरह से कायाकल्प होगा. ■

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

18 नवंबर-24 नवंबर 2013

> केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी फिर से तबाही ला सकती है. नदी ने आपदा के बाद अपना रास्ता बदल दिया है. यह बात खुद आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया स्वीकार रहा है. पहले यह नदी मंदिर के दाईं तरफ से बह रही थी. इसके मंदिर के 200 मीटर पीछे से बहने की वजह को विशेषज्ञ मंदिर समेत आस-पास के गांवों के लिए खतरा मान रहे हैं.

केदारनाथ में गिरी बर्फ ने बढ़ाया संकट

राजकुमार शर्मा

केदारनाथ धाम में मौसम बदलना शुरू हो गया है. धाम में हुई पहली बर्फबारी ने अपना विकराल रूप ले लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र का तापमान गिर रहा है. धाम में रह रहे सरकारी अधिकारी, पंडा पुजारी एंव तीर्थयात्रियों के लिए मौसम की करवट बदलने की स्थिति अब भारी पड़ रही है. बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में अचानक मौसम बदल गया. कभी हल्की धूप तो कभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है. केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर कहा कि मई माह से पहले-पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए. हरीश रावत ने इस मामले में आस्कर फर्नांडीज और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात करने का आश्वासन दिया. देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में हरीश रावत के साथ बातचीत में रावल ने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए पूरा देश उत्तराखंड का साथ देने को तैयार है. उत्तराखंड के राजनेताओं को देश की सहानुभति का ध्यान रखना चाहिए. केदारनाथ के लिए दो रास्तों का निर्माण होना चाहिए. एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए. रावल का कहना था कि निर्माण कार्य तेज करने की जरूरत है.

यह काम अब इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है. आपदा के कामों को चुनाव की आचार संहिता से अलग रखा जा सकता है पर फिर भी सरकार के लिए कुछ हद तक बंदिश जरूर रहेगी. वहीं केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. मौसम का मिजाज पूरी तरह से अनिश्चित है. शासन भी अंदरखाने यह स्वीकार कर रहा है कि फिलहाल अब निर्माण कार्य शुरू कराना आसान नहीं होगा. 2014 में लोकसभा चुनाव की चुनौती सामने होगी. ऐसे में मई माह में अगले साल की यात्रा से पहले केदारघाटी को पटरी पर लाना मुश्किल होगा. खासकर तब जबकि केदारनाथ के लिए दो मार्ग

बनाने हों, नदियों के किनारे बाढ़ नियंत्रण, स्लोप स्टेबलाइजेशन आदि का काम पूरा करना हो. हे बाबा केदार! ऐसी दीपावली फिर कभी न आए. यह निराशा भरे शब्द रोशनी के त्यौहार दीपावली पर केदारघाटी के गांवों में सुनने को मिले. दीपावली के समय सामान्य दिनों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं. स्थानीय तीर्थ पुरोहित और व्यापारी छह माह केदार रह कर घरों को लौटते हैं. केदार यात्राकाल में ही तीर्थ पुरोहित और व्यापारी पैसा कमाते थे और सही मायनों में लक्ष्मी आती थीं. इस बार लक्ष्मी तो क्या कई लोग घर ही नहीं लौटे. साढ़े चार माह पूर्व जलप्रलय में अपनों को खो चुके लोगों की पीड़ा दीपावली पर पुन: उभर आई है. गांवों में दीपावली पर मातम पसरा हुआ है. अपने सात परिजन केदारनाथ आपदा में खो चुके ल्वाड़ी निवासी बांके लाल बगवाड़ी कहते हैं कि घर में विधवा बहुओं और बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता. दिलमी का दिनेश नौटियाल भी आपदा में लापता हो गया था. उसके चार वर्षीय पुत्र भविष्य की समझ में नहीं आ रहा है कि दीपावली आ गई है, पापा घर क्यों नहीं आ रहे हैं. यही हाल दीवली भणिग्राम के तिवारी और लमगौंडी के लालमोरिया व बाजपेयी परिवार के हैं. केदारनाथ धाम को मंदाकिनी नदी फिर से तबाही ला सकती है. नदी ने पहले से आपदा के बाद अपना रास्ता बदल दिया है. यह बात खुद आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) स्वीकार रहा है. पहले यह नदी मंदिर के दाईं तरफ से बह रही थी, अब इसका प्रवाह बाईं तरफ से हो रहा है. इसके मंदिर के 200 मीटर पीछे से बहने की वजह से अत्यधिक वर्षा या भूस्खलन की स्थिति में विशेषज्ञ मंदिर समेत आस-पास के गांवों के लिए खतरा मान रहे हैं. एएसआई (दून सर्किल) के अधीक्षण पुरातत्वविद अतुल भार्गव के अनुसार केदारनाथ क्षेत्र खतरे की जद में हैं. इसके अलावा अगस्त्यमुनि, विजयनगर समेत रूद्रप्रयाग जिले समेत आस-पास पड़ने वाले कई क्षेत्र इस नदी की वजह से भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं. समस्या यह है कि मंदिर के आस-पास मलबे को हटाए जाने समेत तमाम पुनर्निर्माण को लेकर जीएसआई की रिपोर्ट पर काम होना है. इसने मलबे को हटाने को लेकर सहमति नहीं दी है. एएसआई मंदिर के भीतरी स्वरूप का पुनरुद्धार करने में जुटा है, अब मौसम की वजह से इसमें भी बाधा खड़ी हो गई है. इस कार्य में अगला सीजन भी लगने की संभावना है. आपदा के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथार्टी (एनडीएमए) के सदस्य वीके दुग्गल का कहना है कि माइंटेन डिजास्टर पर पूर्वानुमान देना अभी मौसम विभाग के लिए बड़ा कठिन है. ऊंची-नीची पहाड़ियों और प्रतिकूल मौसम के चलते आंकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है. यही कारण है कि उत्तराखंड आपदा पर मौसम विभाग की सटीक जानकारी नहीं आ सकी. उत्तराखंड आपदा पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को केंद्र से नियुक्त हुए एनडीएमए सदस्य वी.के. दुग्गल साढ़े चार महीने उत्तराखंड में बिताने के बाद यहां से रिलीव हो गए. सचिवालय में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में दुग्गल ने कहा कि माउंटेन डिजास्टर को लेकर एनडीएमए और केंद्र सरकार एक कंपोजिट प्लान तैयार कर रही है, ताकि सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि ओडिशा में आए फैलिनी के संबंध में एनडीएमए को साढ़े चार दिन पहले मौसम विभाग ने सटीक जानकारी दे दी थी. इतने पहले इतनी सटीक जानकारी मिलने से ही लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का मौका मिल गया. जबकि उत्तराखंड में आई आपदा में मौसम विभाग की इतनी सटीक जानकारी नहीं थी. आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों पर सरकार की सराहना करते हुए दुग्गल ने कहा कि जो हालात थे, इसमें सरकार समेत सभी ने बेहतर कार्य किया है. उत्तराखंड आपदा ने माइंटेन डिजास्टर पर अब सभी का फोकस किया है. इस राज्य में विभिन्न तरह के डिजास्टर हैं. कभी भूकंप है तो कभी बाढ़ और कभी अतिवृष्टि से आपदाएं होती रहती हैं. यह स्थिति पूरे हिमालयन राज्यों की है. इसके मद्देनजर एनडीएमए कंपोजिट प्लान तैयार कर रहा है. अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ ही पूरे डिजास्टर सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश शुरू हो गई है. उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं. यह यह मंदिर भारत के द्वादश ज्योर्तिलिंगों में सबसे प्रख्यात है. मंदिर के रावल ने गृभ गृह में पूजाकर इस प्रक्रिया को संपन्न करवाया. इस वर्ष बाबा केदार मंदिर के कपाट 14 मई को ग्रीष्मकाल में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले थे. प्राचीन परंपरानुसार, केदारनाथ मंदिर के कपाट भैयादूज पर बंद होते हैं. मंदिर के गर्भगृह में विशेष समाधि पूजा के साथ लिंग को भस्म से ढका जाएगा. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए.■

मुख्यमंत्री के शाहजादे सन ऑफ सरकार की भूमिका में

रेनु शर्मा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लाडले साकेत बहुगुणा अपने पिता की दलाली के मामले में इस कदर सरनाम हो रहे हैं कि उनकी पहचान सन ऑफ सरकार के रूप हो गई है. मुख्यमंत्री का शहजादा होने के कारण पूरी सरकार में उनकी खासी पकड़ है. राज्य सरकार के हड़ताली कर्मचारी इस बात को मानने लगे हैं. तमाम धरने-प्रदर्शन को खत्म करवाने और विवादों को सुलझाने में साकेत की खास भूमिका अदा करने की वजह से यह स्थिति बनी है. आपदा के समय सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के लिए भी भाजपा ने साकेत को घेरा था. ऋषिकेश के आमबाग भूमि आवंटन मामले में भी भाजपा ने साकेत पर ही आरोप जड़ा था और राज्य में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित पार्टी के प्रमुख गुट के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हरीश रावत ने भी ऋषिकेश के आमबाग भूमि आवंटन मामले में जांच की मांग करके पूरी सरकार का संकट बढ़ा दिया है. उन्हें भी अब शाहजादे की बढ़ती दखल रास नहीं आ रही है. राज्य सरकार में बड़ी डील में साकेत की भूमिका कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री की शोहरत खराब कर रहा है. जो राज्य के मुख्य विपक्ष भाजपा के लिए वरदान सिद्ध होगा. यही नहीं, साकेत विपक्ष के निशाने पर भी रहने लगे हैं. यही वजह है कि अब लोग साकेत को सन ऑफ सरकार कहने लगे हैं. इस समय हड़ताल कर रहे प्रदेश के करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी भी सरकार में साकेत की पकड़ को अच्छी तरह से जानते हैं. यही वजह है कि वह रविवार को अपनी मांगों के संबंध में साकेत से मिलने पहुंच गए. सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि कुछ समय पहले मिनिस्ट्रीयल की हड़ताल तुड़वाने और मांगों को शासन से मनवाने में साकेत का हाथ रहा है. इसके अलावा भी कई मामलों को सुलझाने में साकेत खास रोल अदा कर चुके हैं.

पलटन बाजार में वाहनों की आवाजाही हो या कोई प्रदर्शन, साकेत अक्सर मध्यस्थता करने पहुंच जाते हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाते रहे हैं. हालांकि, विवाद भी साकेत को घेरे रहते हैं. चकराता रोड पुनर्निर्माण में व्यापारी दबी जुबान कह रहे हैं कि दुकानों को तुड़वाकर मॉल बनाने की योजना के केंद्र में साकेत ही हैं. ■

भाजपा ने कहा, राष्ट्रपति की मंजूरी को असंवैधानिक कहना राष्ट्रद्रोह

नया लोकायुक्त बिल तो प्रदेश में लागू है- खंडूड़ी

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में अपने बनाए हुए लोकायुक्त बिल पर मौजूदा कांग्रेस सरकार के रवैये से पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी नाखुश हैं. उन्होंने कहा कि बिल तो उसी दिन लागू हो गया था जिस दिन राष्ट्रपति ने मंजूरी दी. वैसे भी विधेयक पारित होते समय कांग्रेस विधानमंडल दल ने समर्थन दिया था. उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का दस्तावेज भी सामने रखा, जिसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत ने विधेयक को जनहित में पारित करने के लिए अपने दल का समर्थन करने का ऐलान किया था. खंडूड़ी नेता प्रतिपक्ष डॉ. रावत के पलटी मारने के बयान से हैरान हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता बीसी खंडूड़ी ने लोकायुक्त को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी को असंवैधानिक कहना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है. खंडूड़ी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में निराशा हताशा के माहौल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. जब स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी भी बिल को लागू करने की पैरवी कर रहे हैं तो सरकार को क्या परेशानी है. जनरल ने कहा कि वैसे तो राष्ट्रपति की मंजूरी वाले दिन से ही बिल लागू होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार को परेशानी है तो कानून में संशोधन का प्रस्ताव सदन में रखना चाहिए. मुख्यमंत्री तो स्वयं न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें तो कानून की जानकारी होनी चाहिए. गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो चुका है फिर सरकार कौन से बिल को लटकाने की बात कर रही है. इस एक्ट में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से लागू और 180 दिन का समय ढांचा खड़ा करने के लिए है. अब सरकार स्ट्रक्चर खड़ा करे. खंडूड़ी ने कहा कि भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि पर खड़ी इस सरकार ने ट्रांसफर एक्ट को निरस्त किया और सेवा का अधिकार कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया. मुख्यमंत्री बहुगुणा के रिश्ते में भाई लगने वाले जनरल ने अपने भाई के भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस के विनाश का काल नजदीक होने के कारण ही बहुगुणा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है. उन्होंने इस मामले पर संविधान के मर्मज्ञ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल की राय पर घोर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सिब्बल जैसे सलहकारों के गलत सलाह के चलते ही कांग्रेस का गढ़ दरक रहा है. पूरा देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. दिल्ली से दून आने पर इस बार जनरल का सुपर हीरो की तरह स्वागत किया गया. सूत्र बताते हैं कि मोदी द्वारा नायक माने जाने के बाद जनरल खंडड़ी के चेहरे की दमक बढ़ गई है. ■

भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी के लिए महाभारत

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी के लिए महाभारत शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की दिली इच्छा है कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड में मोदी के नेतृत्व के चमत्कार और राजनाथ के सत्कार के बल पर पांच की पांचों सीटों पर पार्टी का कब्जा हो. राज्य में जिस तरह नेता जोश में हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को अंदाजा भी नहीं और नेताओं ने अपने-अपने तरीके से बढ़त बनानी शुरू कर दी है. राज्य की पांच संसदीय सीट पर चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की दावेदारी के साथ रानी टिहरी के मामले ने पार्टी हाई कमान के माथे पर पसीना ला दिया है. इसके बावजूद राजा को पता नहीं मुसहरे वन बांट लिए है की कहावत कि तर्ज का जो खेल जारी है इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस की बांछे खिल उठी हैं. भाजपा के दिग्गजों का बेलगाम होकर बहकना कांग्रेस नेतृत्व को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है.

इसमें दावेदारी अब होर्डिंग वार में तब्दील होती दिख रही है. नैनीताल-ऊधमसिंहनगर संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पूरी हनक के साथ सक्रियता बढ़ाई है. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री बच्ची सिंह रावत के सैकड़ों होर्डिंग उनके लिए सिरदर्द बने हैं. संघ परिवार के सहारे राजनीतिक सफर शुरू कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का शानदार सफर करने वाले भगत दा का कोई विकल्प नहीं है फिर भी राजनीति में सब कुछ सम्भव है. इसी कारण धनबल से रावत की जोरदार मौजूदगी का एहसास हो भी रहा है. इधर, टिकट के चक्कर में ही बलराज पासी ने भी विधायक राजकुमार ठुकराल के लिए इतना आक्रामक होकर आंदोलन किया कि वह जेल पहुंच गए. कई दिन के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है.

पौड़ी लोकसभा पर वैसे तो हैवी-वेट जनरल बीसी खंडूड़ी का नाम प्रमुखता के साथ सामने आ ही रहा था कि नरेन्द्र मोदी द्वारा एक बार फिर खंडूड़ी है जरूरी को स्वीकारने के कारण अब जनरल खंडूड़ी सब की मजबूरी बन गए हैं. जनरल की बेदाग छवि ने मोदी को इतना प्रभावित किया है कि मोदी ने उन्हें अपना नायक मान लिया है. इस का पुख्ता प्रमाण हरियाणा के रेवाड़ी की सैनिकों की रैली में देखने को मिला. जनरल के राज में लाए गए लोकपाल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उत्तराखंड में भ्रष्ट्राचार विरोधी नायक के रूप में जनरल का नया अवतार इस बात को प्रदर्शित करता है कि मिशन 2014 में भ्रष्ट्राचार को मुद्दा बना कर मोदी जनरल के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस को घेरने की रणनीति को अपना समर्थन दे कर अपने मिशन फतह करेंगे.

हरिद्वार सीट को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी है, यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तगड़ी दावेदारी पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं साध्वी उमा की दावेदारी ने निशंक दल में सबको स्तब्ध कर दिया है. उमा भारती ने भी कुछ होर्डिंग लगाकर अपना दावा पेश किया है. इस सीट पर हरिद्वार शहर सीट से विधायक मदन कौशिक ने पिछले काफी समय से चुनावी कसरत शुरू कर दी थी. इसलिए यहां पर चुनाव से पहले टिकट पाने का मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा. दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के दावे के मध्य मदन भैया का दावा भी अपने में महत्व रखता है. राजनीति के सफर में धनवान, बलवान बन चुके मदन को पूरा भरोसा है कि पार्टी हाईकमान जिस तरह उनकी सुनेगा वे सुनवाने के लिए हर दांव आजमाएंगे.

टिहरी सीट पर पूर्व राजघराने की महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा केवल एक चुनाव और लड़ने की बात कहकर सेटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू करवाने की बात लगभग फाइनल ही है. आगे की राजनीति में राज-घराने का कोई वारिस अब तक नहीं है. रानी ने जिस तरह मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत को धूल चटाकर बहुगुणा की सीट उप चुनाव में जीत ली, टिहरी राजघराने के प्रति जनता का आदर अभी भी शेष है का प्रमाण प्रस्तुत किया, इससे भी उनके समक्ष किसी की दावेदारी नहीं ठहरती है. रानी का जनता से पुत्रवत मिलना, बेदाग छवि के चलते उनके प्रति जन-जन में आज भी जो आदर है, इसके समक्ष कांग्रेस के फरेबी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुत्र का कोई ग्राफ ही नहीं निर्मित होता.

सुरक्षित सीट अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के उलट नहले पर दहला के रूप में जनरल खंडूड़ी ने अजय लम्टा को पेश करने की रणनीति बनाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सूबे का दलित मतदाता भाजपा के साथ है. तमाम उठा पटक के बावजूद मोदी की तुरुप चाल में जनरल को दिया गया महत्व प्रदेश के साथ देश की राजनीतिक दशा दिशा तय करेगा, जिसमें जनरल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता. ■

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379